हिमाचल प्रदेश विधान सभा

विधान सभा की बैठक बुधवार, दिनांक 09 मार्च, 2022 को माननीय अध्यक्ष, श्री विपिन सिंह परमार की अध्यक्षता में कौंसिल चैम्बर, शिमला-171004 में 11.00 बजे पूर्वाह्न आरम्भ हुई।

प्रश्न काल

तारांकित प्रश्न

09.03.2022/1100/KS/AS/1

प्रश्न संख्याः 4962

श्री नरेन्द्र ठाकुरः अध्यक्ष जी, वैसे तो माननीय मंत्री जी ने काफी डिटेल में सूचना रखी है लेकिन मैं यह भी पूछना चाहूंगा कि जैसे कि उत्तर में बताया गया है कि 583 सौर ऊर्जा पैनल विभिन्न सरकारी कार्यालयों की छतों पर लगे हैं, उनको लगाने की टोटल इन्वैस्टमैंट कितनी आई है और जो ये सोलर पैनल आप लगा रहे हैं, इसकी ड्यूरेबिलिटी कितनी है? यह कितने समय तक चलेगा? इसके साथ ही मैं यह भी जानना चाहूंगा कि हमारे जो बेरोज़गार युवा हैं, क्या यह सोलर एनर्जी का बिजनैस शुरू कर सकते हैं? अगर कर सकते हैं तो इसमें शुरू में क्या इन्वैस्टमैंट है और सरकार उनमें काम करने के लिए क्या सहायता कर रही है?

बहुद्देश्यीय परियोजनाएं एवं ऊर्जा मंत्रीः अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने जो जानना चाहा, 583 सरकारी कार्यालयों की छतों पर सौर ऊर्जा पैनल लगाए गए हैं। जिनकी क्षमता 5504.9 किलोवाट है। हमने पूरी डिटेल में बताया है कि हमने 1,24,94,891 युनिट बिजली का उत्पादन अभी तक किया है जिससे सरकारी खजाने में 5,87,25,988 रुपये की बचत हुई है। छतों पर जो सौर ऊर्जा पैनल लगे हैं, उनकी पूरी लागत 26 करोड़ रुपये है। जो पैनल लगाने का काम होता है इसमें टैंडर होते हैं। जो टैंडर में पार्टिसिपेट करते हैं, कंडिशन पूरी करने के बाद उन्हीं को यह काम आबंटित किया जाता है।

श्री ध्वाला जी अ0व की बारी में...

09.03.2022/1105/av/as/1

प्रश्न संख्या : 4962 -------- क्रमागत

श्री रमेश चंद ध्वाला : अध्यक्ष महोदय, प्रदेश में बहुत सारे युवाओं ने आई0टी0आई0, डिप्लोमा या डिग्री की है, तो क्या विधान सभा क्षेत्रवाइज इन बेरोजगार युवाओं की कमेटी

बनाकर के किसी जिम्मेवार व्यक्ति को हिम ऊर्जा के प्रोजैक्ट लगाने के लिए आवश्यक औपचारिकताएं पूर्ण करवाने की जिम्मेवारी दी जा सकती है? इन प्रोजैक्ट्स को लगाने के लिए उन युवाओं को क्या सरकारी जमीन मिल सकती है? बेरोजगारी को मद्देनज़र रखते हुए प्रदेश की हर पंचायत में 2, 5 या 7 मैगावाट के प्रोजैक्ट्स लग जाए तो इनसे बेरोजगार युवा को इंकम आएगी क्योंकि मेरे ख्याल से इनको लगाने का खर्चा भी ज्यादा नहीं होता। इसलिए मैं मंत्री जी से यह पूछना चाहता हूं कि क्या सरकार इसके लिए सब्सिडी का प्रावधान कर सकती है?

बहुउद्देश्यीय परियोजनाएं एवं ऊर्जा मंत्री : अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय सदस्य को बताना चाहता हूं कि अभी तो इस प्रकार की कोई पॉलिसी नहीं है **परंतु इस बारे में विचार किया जा सकता है।**

श्री नरेन्द्र ठाकुर : अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री ने मेरे प्रश्न का सही जवाब नहीं दिया है। मैंने यह पूछा था कि इनकी ड्यूरेबिलिटी कितनी है। इन सोलर पैनल को लगाने पर 26 करोड़ रुपये का खर्चा आया है। इसलिए मैं यह पूछ रहा था कि यह घाटे का सौदा है या लाभ का सौदा है। अगर यह घाटे का सौदा है, तो इस बारे में सरकार क्या विचार कर रही है? इसके अतिरिक्त मैंने यह भी पूछा था कि क्या हमारा बेरोजगार युवा इसको बिजनैस के तौर पर शुरू कर सकता है? अगर कर सकता है तो इसमें शुरू में कितनी इंवैस्टमैंट करनी पड़ेगी और सरकार की ओर से इसमें क्या सहायता मिल सकती है?

09.03.2022/1105/av/as/2

बहुउद्देश्यीय परियोजनाएं एवं ऊर्जा मंत्री : अध्यक्ष महोदय, पूर्व में लगे हिम ऊर्जा प्रोजैक्ट्स से अभी तक 5,87,25,998/- रुपये की बचत हुई है और इसकी ड्यूरेशन लगभग 25 वर्ष है। मैं यह भी बताना चाहता हूं कि यह घाटे का सौदा नहीं है बल्कि लाभ का सौदा है। दूसरा आपने जहां तक बेरोजगार युवाओं को इन प्रोजैक्ट्स को लगाने के बारे में पूछा है तो मैं यह बताना चाहता हूं कि इस बार भी रूफ टोप सोलर पैनल के 10 मैगावाट के टैंडर

किए जा रहे हैं। मगर उसका टैंडर केवल क्वालीफाईड व्यक्ति को ही मिल सकता है। सरकार ने हिम ऊर्जा की ओर प्रोत्साहित करने के लिए इस वर्ष के बजट में 3 किलोवाट प्रोजैक्ट लगाने के लिए 6,000 रुपये प्रति किलोवाट की सब्सिडी का प्रावधान किया है। पिछली बार यह सब्सिडी 4,000 रुपये प्रति किलोवाट थी। अगर कोई व्यक्ति अपने घर की छत पर 3 किलोवाट का सोलर पैनल लगाएगा तो उसके लिए 40 प्रतिशत की सब्सिडी केंद्र सरकार की ओर से दी जाएगी और 6,000 रुपये प्रति किलोवाट की सब्सिडी राज्य सरकार की ओर से दी जाएगी। उससे ऊपर 10 किलोवाट तक 20 प्रतिशत तक सब्सिडी का प्रावधान है और उसमें भी प्रदेश सरकार 6,000 रुपये प्रति किलोवाट की दर से सब्सिडी देगी। लेकिन 10 किलोवाट से ऊपर लगाए जाने वाले सोलर पैनल के लिए केंद्र सरकार की ओर से कोई भी सब्सिडी नहीं दी जाती हालांकि प्रदेश सरकार की ओर से उसके ऊपर सब्सिडी है। इसलिए कोई भी व्यक्ति यदि अपने घर की छत पर सोलर पैनल लगाना चाहता है तो वह लगा सकता है।

प्रश्न समाप्त

अगला प्रश्न टी सी द्वारा जारी

09/03/2022/1110/टी0सी0वी0/डी0सी0/1

प्रश्न संख्या :4963

ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री : अध्यक्ष महोदय, उत्तर सभा पटल पर रख दिया गया है।

प्रश्न संख्याः 4964

श्री राकेश जम्वाल : अध्यक्ष महोदय, मैं मंत्री महोदय से यह जानना चाहूंगा कि इस पुल का कितना एस्टिमेट बनाया गया और इसको कब बी0बी0एम0बी0 के पास प्रेषित किया गया?

बहुउद्देश्यीय परियोजनाएं एवं ऊर्जा मंत्री : अध्यक्ष महोदय, मै माननीय सदस्य को बताना चाहूंगा कि दिनांक 21-10-2011 को सुकेती खड्ड पर तीन जीप योग्य पुलों को स्वीकृति दी गई थी। इनमें से 60 मीटर का एक पुल बना दिया गया है और दिनांक 24-12-2019 को दो अन्य पुलों का लोक निर्माण विभाग द्वारा प्राक्कलन बना कर भेजा गया था। इसमें जमीन का विवाद था और जिलाधीश द्वारा दिनांक 08-03-2022 को यह सूचित किया गया है कि इसकी जांच की जा रही है ताकि यह विवाद खत्म हो सकें। जैसे ही यह जमीन का विवाद खत्म हो जाएगा, इन दो पुलों के निर्माण का मामला भी बी0बी0एम0बी0 से उठाएंगे और इसका एस्टिमेट तैयार करवाएंगे ताकि जनहित में ये दोनों ब्रिज बनाए जा सकें।

श्री राकेश जम्वाल : अध्यक्ष महोदय, बी0बी0एम0बी0 प्रोजैक्ट मेरे और नाचन विधान सभा क्षेत्र में लगा है। इस प्रोजैक्ट में सुन्दरनगर की बहुत प्राइम लैंड गई है। हम समय-समय पर बी0बी0एम0बी0 से विभिन्न मुद्दे उठाते रहे हैं। इस प्रोजैक्ट के कारण लोगों के खेत खराब हो रहे हैं। जैसा अभी माननीय मंत्री जी ने कहा कि तीन ब्रिज सैंक्शन हुए थे जिनमें एक बनकर तैयार हो गया है और उसका उद्घाटन भी हो गया है। दूसरा ब्रिज भी बनकर तैयार है लेकिन मैं आपके माध्यम से माननीय सदन को जानकारी देना

चाहता हूं कि यह एक ऐसा ब्रिज बनाया गया है जिसके दोनों तरफ कोई सड़क नहीं है। उसका अभी उद्घाटन नहीं हुआ है। धानडा-तलवाली के पास जो जीप योग्य पुल बनना है, इसकी सैंक्शन वर्ष 2011 में मिली थी और इसका कोई विवाद नहीं है लेकिन बी0बी0एम0बी0 द्वारा इसके लिए कोई धनराशि मुहैया नहीं करवाई गई। मैं मुख्य मंत्री जी से भी निवेदन करना चाहूंगा क्योकि यह सारा विषय उनके ध्यान में भी है। मुख्य मंत्री जी बी0बी0एम0बी0 के चेयरमैन को बुलाएं और हमारे विधान सभा क्षेत्र के विभिन्न लम्बित मुद्दों का समाधान करवाएं। जिला शिकायत निवारण समिति की बैठक में मैंने मुद्दा उठाया था, जल शक्ति मंत्री जी ने इसकी अध्यक्षता की थी। इन्होंने एक समिति गठन की। हमने वहां

विजिट किया जिसमें बी0बी0एम0बी0 और लोक निर्माण विभाग के सारे अधिकारी थे। उसके सारे एस्टिमेट्स बी0बी0एम0बी0 को भेज दिए गए हैं और लगभग 8 महीने का समय हो गया है लेकिन उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई है। मेरे विधान सभा क्षेत्र में सुन्दरनगर से कपाही की जो सड़क है उसकी हालत बहुत खस्ता है। इस ब्रिज की मंजूरी भी वर्ष 2011 में बी0बी0एम0बी0 ने दी है और लोक निर्माण विभाग

एन0एस0 द्वारा जारी .....

09-03-2022/1115/NS/DC/1

प्रश्न संख्या : 4964 ..... क्रमागत

श्री राकेश जम्वाला .....जारी

ने इसका एस्टिमेट बना करके बी0बी0एम0बी0 को सबमिट किया है लेकिन अभी तक इस ब्रिज की मंजूरी नहीं मिल रही है। मैं, विशेष तौर से मुख्य मंत्री जी और मंत्री जी से निवेदन करना चाहूंगा कि बी0बी0एम0बी0 के साथ जो हमारे इश्यूज हैं आप उनको रिजोल्व करवाएं। आपके आशीर्वाद से जहां सुन्दरनगर में बाकी विकास कार्य तेजी से चल रहे हैं वहां बी0बी0एम0बी0 के कारण हमारे क्षेत्र में चल रहीं समस्याओं का भी समाधान होगा। मैं चाहूंगा कि इस पुल की हमें जल्दी-से-जल्दी मंजूरी मिले ताकि सुन्दरनगर और नाचन क्षेत्र की जनता को लाभ हो सके।

बहुउद्देशीय परियोजनाएं एवं ऊर्जा मंत्री: अध्यक्ष महोदय, मैंने पहले ही कहा है कि हम इस मामले को बी0बी0एम0बी0 से प्रभावशाली तरीके से उठाएंगे और उनको बुलाएंगे। माननीय सदस्य ने जो तीसरा पुल बनाने की बात है तो इस मसले को उनके साथ उठा कर इस पुल को कैसे बनाया जा सकता है, इसका समाधान करने की कोशिश करेंगे।

मुख्य मंत्री : अध्यक्ष महोदय, जो प्रश्न श्री राकेश जम्वाल जी ने किया है। इस प्रश्न का उत्तर मंत्री जी ने काफी विस्तार से दे दिया है। सही बात यह है कि बी0बी0एम0बी0 के साथ एक बार नहीं इस तरह के अनेक बार प्रयास हुए हैं लेकिन इसके बावजूद भी वे इस विषय को गंभीरता से नहीं ले रहे हैं। ऐसे में एक बार नहीं बल्कि अनेक बार उनके चेयरमैन और अधिकारियों के साथ बातचीत हुई है। अभी जो बी0बी0एम0बी0 के नए चेयरमैन बने हैं मैंने

उनसे भी कहा है कि हमारे कुछ मामले हैं इसमें चाहे सिल्ट या अन्य मसले हैं और इनको आपके साथ डिसकस करना है। सुन्दरनगर, बल्ह और नाचन क्षेत्र में इससे बहुत तबाही हुई है। इन विधान सभा क्षेत्रों के विकास के छोटे-छोटे प्रोजेक्ट्स बी0बी0एम0बी0 का सकारात्मक दृष्टिकोण न होने के कारण सहयोग न देने की मंशा के साथ लंबित पड़े हुए हैं। जो मामले बी0बी0एम0बी0 से संबंधित हैं जिनके कारण लोगों को परेशानी हो रही है और वर्षों से क्रोनिक इश्यू बने हुए हैं और इनका समाधान बार-बार कहने के बाद भी नहीं हो पा रहा है और इसके अतिरिक्त विकास के जो प्रोजेक्ट्स हैं जैसे रास्ते और सड़कों का ज़िक्र किया गया है इस तरह के तमाम इश्यूज को ले करके हम प्लान कर लेंगे और एक मीटिंग करेंगे ताकि इन समस्याओं का हम समाधान

09-03-2022/1115/NS/DC/2

कर सकें। **मैं, माननीय सदस्य को आश्वस्त करना चाहूंगा कि बहुत जल्दी हम बी0बी0एम0बी0 के चेयरमैन को बुला करके इन सारे मामलों का समाधान करेंगे।**

श्री राकेश जम्वाल : मैं, मुख्य मंत्री जी का धन्यवाद करना चाहूंगा और निवेदन करना चाहूंगा कि जब आप बी0बी0एम0बी0 के चेयरमैन और अधिकारियों को यहां बुलाएं तो सुन्दरनगर, नाचन और बल्क क्षेत्र के विधायकों को भी बुलाएं ताकि हम अपने मामले वहां पर रख सकें।

मुख्य मंत्री : अध्यक्ष महोदय, इस बात को हम सुनिश्चित करेंगे। विशेष तौर से तीन विधान सभा क्षेत्र के विधायक तो होंगे ही लेकिन 4 विधायक और भी हैं तो इन सबको बुलाने की कोशिश करेंगे। हमारे अधिकारी इस बात को सुनिश्चित कर लेंगे। बी0बी0एम0बी0 से संबंधित जितने भी विधान सभा क्षेत्र प्रभावित हैं उन सबको बुलाएंगे और इस पर चर्चा करेंगे ताकि इनका समाधान हो सके।

अगला प्रश्न .....श्री बी0 एस0 द्वारा जारी।

09.03.2022/1120/बी.एस./एच0के0/-1

प्रश्न संख्याः 4965

श्री जिया लाल : अध्यक्ष जी, जो सूचना सभा पटल पर रखी गई है, उसके मुताबिक इस भवन का निर्माण कार्य जून महीने तक पूर्ण कर लिया जाएगा। परंतु जिस भवन की अभी तक छत ही नहीं बनी है और वहां पर कार्य ही शुरू नहीं हुआ है तो वह जून तक कैसे पूरा हो जाएगा। मैं माननीय मुख्य मंत्री जी से भी आग्रह करना चाहता हूं कि लोक निर्माण विभाग भी इन्हीं के पास है, इस कार्य का जो एग्रीमेंट हुआ था वह 05.09.2020 को हुआ था। अब तक यह कार्य पूर्ण हो जाना चाहिए था। हमारे कॉलेज के बच्चे एक सरांय में या वरिष्ठ माध्यमिक स्कूल, भारमौर में अपनी शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं। मुख्य मंत्री जी अधिकारियों को आदेश करें कि यह कार्य जल्दी पूरा हो सके।

शिक्षा मंत्री : अध्यक्ष जी, जो माननीय सदस्य ने कहा है कि इसका काम बहुत धीमी गति से चल रहा है, मैं कहना चाहता हूं कि इस महाविद्यालय के लिए 14 करोड़ रुपए की प्रशासनिक स्वीकृति दे दी गई है और उसमें से 12 करोड़ 24 लाख रुपए लोक निर्माण विभाग को जारी कर दिए गए हैं। मुझे लगता है कि कार्य में देरी नहीं होनी चाहिए। हम इस बात को सुनिश्चित करेंगे की लोक निर्माण विभाग इस कार्य में तेजी लाए। लेकिन जो सूचना है, उसमें यह कहा गया है कि 65 प्रतिशत कार्य पूर्ण हो गया है और बचे कार्य को जून, 2022 तक पूर्ण कर लिया जाएगा और जो टाइम लाइन दी है यह भी लोक निर्माण विभाग ने दी है। यदि कहीं कोई कमी है, तो उसे सही से सुनिश्चित करें, क्योंकि इसमें धन का भी पूरा प्रावधान है।

प्रश्न समाप्त/

09.03.2022/1120/बी.एस./एच0के0/-2

प्रश्न संख्याः 4966

श्री भवानी सिंह पठानिया : महोदय, जो सूचना सभा पटल पर रखी है, यही सूचना लगभग 7-8 महीनों से आ रही है। मैं इस भवन के बारे में बताना चाहता हूं कि यह वर्ष 2016-17 में मुख्य मंत्री जी की घोषणा भी है। इस भवन का टैंडर हो चुका है और इसके बाद इश्यू यह है कि एक विभाग ने दूसरे विभाग को क्लीयरेंस प्रदान करनी है। प्रदेश सरकार के दोनों

विभाग हैं, आपसे निवेदन है कि इस कार्य में थोड़ा तेजी लाएं। कुछ प्रोजैक्ट्स ऐसे होते हैं जो पार्टी विशेष से संबंधित नहीं होते हैं, जन भावनाओं से संबंधित होते हैं। मेरी इच्छा है कि इसे चुनाव से पहले पूरा करके इसका उद्घाटन माननीय मुख्य मंत्री जी से करवाना चाहता हूं।

जल शक्ति मंत्री : अध्यक्ष जी, माननीय सदस्य जी ने कहा कि 7-8 महीनों से यही उत्तर मिल रहा है। मुझे तो इस प्रकार से ध्यान नहीं है कि ऐसा उत्तर दिया होगा। जो स्थिति है वह इस प्रकार से हैः-

फतेहपुर में जो हमारा मिनी सचिवालय बहुउद्देश्यीय भवन का निर्माण होना है उसके लिए लोक निमार्ण विभाग द्वारा इसकी प्रशासनिक अप्रूवल प्रदान कर दी गई थी। पहले लोक निर्माण विभाग इसकी नोडल एजेंसी थी लेकिन अब उस नोडल एजेंसी को बदल करके उसे राजस्व विभाग कर दिया गया है। मैं माननीय सदस्य को बताना चाहता हूं कि इस भवन का निर्माण कार्य होना है इसके लिए जमींन का खसरा नम्बर 730,634,590,487,733,687,637 एवं 488 रक्बा तादादी- 70 हैक्टेयर किस्म चरागाह, दरखतान भूमि चयन की थी। लेकिन भूमि वन विभाग की होने के कारण उसमें एफ0सी0ए0 लगता है और उसकी स्वीकृति उच्चतम न्यायालय से मिलती है।

श्री एन0 जी0 द्वारा जारी...

09-03-2022/1125/एच.के.-एन.जी. /1

प्रश्न संख्या - 4966 .....जारी

जल शक्ति मंत्री..... जारी

वन विभाग की भूमि होने के कारण उसमें एफ.आर.ए./एफ.सी.ए. लगता है। अब तो एफ.सी.ए. की स्वीकृति माननीय सर्वोच्च न्यायालय से प्राप्त होती है। इसमें बड़ा लम्बा समय लग सकता है इसलिए विभाग नई भूमि की ओर आगे बढ़ रहा है। नई भूमि के लिए

खसरा नम्बर 734, 687, 637 व 488/2, रकबा तादादी 0-24-87 हैक्टर गैर मुमकिन खड्ड का चयन किया गया है। अब इस भूमि के लिए एन.ओ.सी. प्राप्त करने हेतु उपायुक्त, कांगड़ा ने विभिन्न विभागों को लिखा है जिनमें वन विभाग, लोक निर्माण विभाग, बिजली बोर्ड व जल शक्ति विभाग शामिल है। दिनांक 14-02-2022 को यह पत्र जारी किया गया है। जैसे ही इन सभी विभागों से अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त होते हैं तब इस भूमि पर कार्य शुरू किया जा सकता है। माननीय सदस्य के क्षेत्र में जो मिनि सचिवालय का भवन बन रहा है उसके लिए माननीय मुख्य मंत्री जी ने एक करोड़ रुपये पहले ही दे दिए थे और दिनांक 03-03-2022 को एक करोड़ रुपये और जारी कर दिए गए हैं। इस प्रकार कुल दो करोड़ रुपये की धनराशि इस भवन निर्माण के लिए हमारे पास उपलब्ध है। अभी इस भवन के निर्माण के लिए Expenditure Sanction दी जानी शेष है। अभी केवल Administrative Approval ही दी गई है। मैं माननीय सदस्य जी को यह भी बताना चाहता हूं कि इस मिनि सचिवालय भवन में कौन-कौन से विभागों के कार्यालय प्रस्तावित हैं। इसमें उप मण्डलाधिकारी, फतेहपुर का कार्यालय, तहसील कार्यालय, डी.एस.पी., बाल विकास परियोजना अधिकारी, खण्ड विकास अधिकारी, खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले विभाग, सहकारिता विभाग, उद्योग विभाग, चुनाव आयोग का कार्यालय और पुस्ताकालय होगा। इन 10 विभागों की ओर से लिखित रूप में आया है कि हमें इस भवन के अंदर स्थान दिया जाए। मैं पुनः कहना चाहूंगा कि **जैसे ही भूमि का हस्तांतरण हो जाता है उसके उपरांत लोक निर्माण विभाग आगामी प्रकिया करेगा। इसके लिए 2 करोड़ रुपये दे दिए गए हैं और Expenditure Sanction भी दे देंगे। उसके बाद इसका टेण्डरिंग प्रोसेस शुरू होगा और फिर इसके निर्माण कार्य को आगे बढ़ाया जा सकता है।**

प्रश्न समाप्त/-

09-03-2022/1125/एच.के.-एन.जी. /2

प्रश्न संख्या - 4967

श्री रमेश चंद ध्वाला (ज्वालामुखी) : अध्यक्ष महोदय, मेरा विधान सभा क्षेत्र ज्वालामुखी है और विकास खण्ड क्षेत्र (ब्लॉक) देहरा है। इस विकास खण्ड में लगभग 79 पंचायतें

शामिल हैं। मैं माननीय मंत्री जी से आश्वासन चाहता हूं कि क्या आप ज्वालामुखी में एक नया ब्लॉक बनाने की स्वीकृति प्रदान करेंगे?

ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री : अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य जी ने जो प्रश्न किया उसका उत्तर विस्तृत रूप से दिया जा चुका है। ज्वालामुखी विधान सभा क्षेत्र के टिहरी तथा खुंडियां में नए विकास खण्ड खोलने की मांग प्राप्त हुई है। इस संदर्भ में दोनों मामले उपायुक्त, कांगड़ा को मामलों की व्यवहारिता की जांच करने व प्रस्तावना विभाग को भेजने बारे क्रमशः दिनांक 03-12-2021 व 14-02-2022 को लिखा गया है। अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य जी ने **अभी ज्वालामुखी के लिए कहा है तो हम इसे एग्ज़ामिन कर लेंगे और जहां पर भी सम्भावना होगी तो उसे करने पर विचार करेंगे।**

अगला वक्ता....श्री जे.एस. द्वारा जारी.....

09.03.2022/1130/JS/YK/1

प्रश्न संख्याः 4967 :-----जारी-----

श्री रमेश चन्द ध्वालाः माननीय अध्यक्ष जी, माननीय मंत्री जी आश्वासन दे दें। वह कार्यालय कहां पर बनना है, उसके बारे में प्रधानों की सहमति से देखा जाए कि उस कार्यालय को बनाने का केन्द्र बिन्दू कहां पर है, वहां पर उस कार्यालय को खोलने की स्वीकृति इनकी तरफ से प्रदान होनी चाहिए।

अध्यक्षः माननीय सदस्य, माननीय मंत्री जी ने उत्तर तो दे दिया है। यह मैटर एग्जामिन हो रहा है।

ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्रीः अध्यक्ष महोदय, जिलाधीश की तरफ से जो भी रिपोर्ट आएगी उसके अनुसार कार्रवाई करेंगे।

श्री परमजीत सिंहः माननीय अध्यक्ष जी, मेरा भी इसमें प्रश्न संख्याः 4988 लगा हुआ है लेकिन वह बहुत पीछे लगा हुआ है और इसी से संबंधित है। मेरा माननीय मंत्री जी और

मुख्य मंत्री जी से निवेदन है कि कई विधान सभा क्षेत्रों में दो-दो बी.डी.ओ. कार्यालय खुले हैं, मैं उनकी खिलाफ़त नहीं कर रहा हूं। मेरा आपके माध्यम से निवेदन है कि मेरे विधान सभा क्षेत्र, दून में यह ऑफिस खोला जाए। इसकी कृपया स्वीकृति दे दें, इसके लिए मेरा आपसे विनम्र अनुरोध है। कई जगह दो-दो ऑफिस खुले हैं लेकिन हम उसके खिलाफ नहीं हैं।

ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्रीः माननीय अध्यक्ष जी, यह बात बिल्कुल ठीक है कि कांगड़ा में पालमपुर, ज्वालामुखी और सोलन में दून ये तीन ऐसे विधान सभा क्षेत्र हैं, जहां पर बी.डी.ओ. ऑफिस नहीं हैं। **माननीय सदस्य ने जो यहां पर कहा है इस पर गम्भीरता से विचार करेंगे और जल्दी से इसके ऊपर कोई निर्णय लेंगे।**

09.03.2022/1130/JS/YK/2

श्री आशीष बुटेलः माननीय अध्यक्ष जी, मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहूंगा कि जिलाधीश कांगड़ा से ज्वालाजी के लिए रिपोर्ट मांगी है। क्या जिलाधीश कांगड़ा से पालमपुर विकास खण्ड कार्यालय खोलने की आपके पास रिपोर्ट आई है? दूसरे, आपके कार्यकाल में कितने विकास खण्ड कार्यालय पूरे प्रदेश भर में खुले हैं? ऐसे कौन से मापदंड हैं, जो पालमपुर, ज्वालामुखी और दून विधान सभा क्षेत्र पूरा नहीं करते हैं? मैं, माननीय मुख्य मंत्री जी से आग्रह करूंगा कि आप होली के दौरान पालमपुर जाएंगे तो कृपया इस कार्यालय की भी आप घोषणा कर दें।

ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्रीः माननीय अध्यक्ष जी, माननीय सदस्य ने जो कहा, उसके बारे में मैं यह कहना चाहता हूं कि जब हिमाचल प्रदेश बना था तो उस वक्त 38 विकास खण्ड थे। वर्ष 2000 तक आते-आते तीन विकास खण्ड खुले। वर्ष 2018 में भी खोले और 2020 में एक विकास खण्ड खोला गया। वर्ष 2021 में विकास खण्ड कार्यालय सात खोले और अब इनकी कुछ संख्या 88 हो गई है। माननीय सदस्य ने जानना चाहा है कि इस कार्यालय को खोलने के क्या मापदंड होते हैं? तो भौगोलिक परिस्थितियों और आम जनता

की जन सुविधाओं को मध्यनज़र रखते हुए विकास खण्ड खोले जाते हैं। माननीय सदस्य ने पालमपुर के बारे में कहा और मैंने कहा कि यह मैटर हमने इग्जामिन करने के लिए भेजा है, जैसे ही जिलाधीश से जो भी उत्तर प्राप्त होगा, इस पर विचार करेंगे।

श्री एस.एस. द्वारा जारी-----

09.03.2022/1135/SS-YK/1

प्रश्न संख्या : 4968

श्री विनय कुमार : अध्यक्ष महोदय, जो संगडाह विकास खंड है उसमें 44 पंचायतें हैं और आपने जो मनरेगा का तीन वर्ष का डाटा दिया है वह लगभग 9-10 पंचायतों का है। आपने जो उत्तर दिया है आप इसमें यह देखिए कि एक पंचायत एक करोड़ से ऊपर मनरेगा में काम कर रही है और बाकी 34 पंचायतें में एक लाख से 3 लाख के छोटे-छोटे कार्य हैं। तीसरी बात यह है कि जो इंटरलॉक टाइल्स के 30-30 लाख रुपये के कार्य चल रहे हैं इसमें स्किल्ड लेबर लगती है। हमारे लोगों को कार्य नहीं मिल रहा है। टेक्निकल लोग बाहर से आते हैं, बिहार से आते हैं और इंटरलॉक टाइलें लगाते हैं और लगाकर चले जाते हैं। आप सिर्फ खानापूर्ति के लिए हमारे लोगों की हाज़रियां लगाते हैं। एक तो यह विसंगति हो रही है।

दूसरी बात यह है कि कई जगह मनरेगा में कम्प्लेंट्स आई हैं और कार्यों में जे0सी0बी0 मशीन का प्रयोग हुआ है। क्या आप इन सभी बातों को चैक करके कार्रवाई करेंगे?

ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री : अध्यक्ष जी, वैसे तो उत्तर विस्तृत रूप से रख दिया है लेकिन जैसे इन्होंने कहा कि 44 पंचायतें इसमें आती हैं, वित्त वर्ष 2019-20 में विकास खंड संगडाह में 390 कार्य पिछले वर्ष के थे। उसको स्पिल ऑवर करके 389 नए कार्य इसमें जोड़ दिए गए हैं। उसमें से 383 कार्य पूर्ण कर लिए हैं। इसी प्रकार 2020-21 में 396 कार्य पिछले बचे थे। उसको स्पिल ऑवर करके 1333 नए कार्य थे। उनमें से 481 कार्य पूर्ण कर लिए हैं। इसके साथ-साथ 2021-22 में 1248 कार्य पिछले बचे थे और 1077 नए

कार्य इसमें ऐड हुए हैं। उनमें से 491 कार्य पूर्ण कर लिए गए हैं। अब आपने जो 5 लाख से ऊपर के कार्यों की बात कही है वे 1834 कार्य हैं जिनमें कार्य प्रगति पर है। जहां तक आपने कहा कि टाइल्स लग रही हैं, बड़े-बड़े काम हो रहे हैं तो यह अच्छी बात है। लेकिन साथ में आप यह भी शिकायत कर रहे हैं कि जे0सी0बी0 और बाहर की लेबर का प्रयोग हो रहा है। इसमें दो पार्ट हैं। एक तो 100 परसैंट मनरेगा से है वहां पर बाहर की लेबर काम नहीं कर सकती है और

09.03.2022/1135/SS-YK/2

जे0सी0बी0 का प्रयोग नहीं हो सकता है। लेकिन जहां काम कंवरजैंस में है, इसको वित्तायोग के साथ कर रहे हैं या विधायक निधि या सांसद निधि के साथ कर रहे हैं वहां पर इसका प्रयोग हो रहा है। **लेकिन अगर फिर भी आपको लगता है कि कहीं पर ऐसी कोई विशेष पंचायत है तो आप लिखकर दें हम उसमें कार्रवाई करेंगे।**

श्री विनय कुमार : अध्यक्ष महोदय, मैं यह कहना चाह रहा था कि आपने जो यहां डाटा दिया है या तो आप पूरा उत्तर दीजिए जोकि आपने बोला है। आपने बहुत छोटा-सा उत्तर दिया है वह सब के सामने है, सभापटल पर है। आपने सिर्फ 10 पंचायतों का ज़िक्र किया है। मैंने आपसे सिर्फ 5 लाख रुपये से ऊपर के कार्य की बात कही है। इसमें आपने 10 पंचायतें टच की हैं, क्या बाकी 33 पंचायतों में कार्य नहीं हो रहे हैं?

दूसरी बात है कि मनरेगा के तहत कुछ लोगों ने अपने निजी आवास के लिए 20 से 30 लाख रुपये की टाइलें लगा ली हैं। क्या आप इसको चैक करके उनके खिलाफ कार्रवाई करेंगे? इसके अलावा क्या आप मनरेगा के वेजिज़ बढ़ाएंगे या नहीं?

ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री : अध्यक्ष जी, मैंने माननीय सदस्य को कह दिया है कि मुझे लिख कर दे दो। जहां पर गलत हुआ है वहां पर कार्रवाई करेंगे।

प्रश्न समाप्त

09.03.2022/1135/SS-YK/3

प्रश्न संख्या : 4969

श्री अरुण कुमार : अध्यक्ष महोदय, मेरा प्रश्न छात्रों के साथ जुड़ा हुआ प्रश्न है और थोड़ा विस्तरपूर्वक है तो

जारी श्रीमती के0एस0

09.03.2022/1140/KS/AS/1

प्रश्न संख्याः 4969 जारी..

श्री अरुण कुमार जारी---

मैं माननीय मंत्री जी को बताना चाहता हूं कि नगरोटा विधान सभा क्षेत्र का महाविद्यालय उत्कृष्ट महाविद्यालय की श्रेणी में आ गया है। हिमाचल प्रदेश उच्चतर शिक्षा विभाग की अधिसूचना संख्याः EDN-A-Kha(6)10/95 P+111 creation जो थी, जो कि दिनांक 6 अगस्त,2006 को जारी की गई थी के माध्यम से प्राचार्य सहित विभिन्न श्रेणियों के 34 पद स्वीकृत किए थे जिनमें कम्प्यूटर एप्लीकेशन का एक पद, जियोलॉजी के 2 पद शामिल थे जिनकी कॉपी मैं माननीय मंत्री महोदय को दे रहा हूं। परन्तु बाद में यहां जैसे-जैसे पढ़ने वाले छात्रों की संख्या बढ़ती गई, इस चीज़ को नज़रअंदाज करते हुए यहां से 6 पदों को जिनमें कम्प्यूटर एप्लीकेशन का 1 पद, जियोलॉजी का एक पद, अर्थशास्त्र का 1, जर्नलिज्म एण्ड मास कम्युनिकेशन का 1, जियोग्राफी 1, टूरिज्म एण्ड ट्रैवल का 1 पद शामिल है, को अन्य महाविद्यालयों को रिज़र्व पूल के माध्यम से शिफ्ट कर दिया जो कि दुर्भाग्यपूर्ण है। जैसे-जैसे यहां छात्रों की संख्या बढ़ती गई, मौजूदा समय में 3200 के करीब छात्र यहां पढ़ रहे हैं, वैसे-वैसे यहां पर शिक्षकों के पद कम होते गए। मौजूदा समय में प्राचार्य सहित कुल 29 पद ही वहां रह गए हैं। अब जबकि महाविद्यालय के छात्र-छात्राओं की संख्या 3200 के पार है, तो क्या शिक्षा विभाग दोबारा से इन पदों को इस महाविद्यालय

में शिफ्ट करने का विचार कर रहा है? क्योंकि बहुत से ऐसे छात्र हैं जो इन विषयों में शिक्षा ग्रहण करना चाहते हैं। उनके पसंदीदा पाठ्यक्रम जिनमें उनकी रुचि है, वे इन विषयों के क्षेत्र में उच्च शिक्षा ग्रहण कर अपना भविष्य बनाना चाहते हैं।

अध्यक्षः माननीय सदस्य, जो आप पूछना चाहते हैं वह मंत्री जी के ध्यान में बात आ गई है।

09.03.2022/1140/KS/AS/2

श्री अरुण कुमारः अध्यक्ष महोदय, आज के समय में कम्प्यूटर हमारे जीवन का एक अभिन्न अंग है और आज के समय में छात्र- छात्राओं को इस विषय का ज्ञान होना आवश्यक भी है। इस समय नगरोटा बगवां महाविद्यालय जो कि उत्कृष्ट महाविद्यालय बन चुका है, में बेसिक विषयों के पद न होना बड़े अचरज की बात है। मेरा माननीय मंत्री महोदय से यह एक विनम्र निवेदन है कि छात्रों की संख्या को देखते हुए, क्योंकि इसकी वजह से उनको या कांगड़ा जाना पड़ता है या धर्मशाला जाना पड़ता है। जब सरकार ने वहां पर इतनी अच्छी सहूलियत दी है, तो कृपा करके इन विषयों के पदों को भरा जाए।

इसके साथ-साथ इसी विद्यालय के सम्बन्ध में मेरा एक और प्रश्न संख्या 5003 भी लगा है । उसमें मैंने कुछ पदों के बारे में पूछा है। मैं दोनों प्रश्नों के बारे में ये कागज़ात माननीय मंत्री महोदय को दे देता हूं और इनसे विनम्र गुजारिश भी करुंगा क्योंकि छात्रों के भविष्य का प्रश्न है इसलिए इसमें ये अवश्य कार्रवाई करे। धन्यवाद।

शिक्षा मंत्रीः अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने जो कहा है, एक तो इनको बधाई देता हूं कि माननीय मुख्य मंत्री श्रीमान जय राम ठाकुर जी ने नगरोटा महाविद्यालय को उत्कृष्ट महाविद्यालय बना दिया है और उसके लिए एक करोड़ रुपये की अतिरिक्त राशि प्रदान की है। नगरोटा महाविद्यालय में 65 पद स्वीकृत थे जिनमें 35 पद शिक्षक और 30 नॉन टीचिंग स्टाफ के थे। वर्ष 2009 में रेशनलाइजेशन हुई और उस समय वहां पर छात्र और छात्राओं की संख्या कम होने के कारण से 4 पद असिस्टैंट प्रोफैसर के थे उनको सरप्लस पूल में स्थानांतरित किया गया। इसके अतिरिक्त रेशनलाइजेशन में 2 पद और किए गए लेकिन जैसे कि माननीय सदस्य ने कहा, उसके बाद वर्तमान में लगभग 3000 से ऊपर

छात्र-छात्राएं नगरोटा महाविद्यालय में हो गए हैं। छात्रों की बढ़ती संख्या को देखकर **मैं इन्हें आश्वस्त करता हूं कि जिन-जिन विषयों की इनको आवश्यकता है, उसके मुताबिक हम आगामी कार्रवाई करेंगें और इन पदों को दोबारा से भर देंगे। माननीय सदस्य इस बारे में निश्चिंत रहे।**

प्रश्न समाप्त

अगला प्रश्न अ0व0 की बारी में---

09.03.2022/1145/av/as/1

प्रश्न संख्या : 4970

श्री मोहन लाल ब्राक्टा : अध्यक्ष महोदय, मैंने मंत्री महोदय से यह जानना चाहा था कि क्या एस0डी0एम0 कार्यालय रोहडू व डोडरा-क्वार में प्राकृतिक आपदाओं (Natural Calamities such as fire, accidents and other death cases etc.) के कितने मामले भुगतान हेतु लंबित हैं; नाम व पते सहित ब्यौरा दें। मंत्री महोदय द्वारा सभा पटल पर रखी गई सूचना के अनुसार एस0डी0एम0 कार्यालय रोहडू के अंतर्गत 19 मामले लंबित हैं तथा डोडरा-क्वार में कोई नहीं है। लिखित सूचना के अनुसार आपने ज्यादातर केसिज में 10,000 रुपये की फौरी राहत दी है, केवल क्रमांक संख्या 15 पर आपने 20,000 रुपये की फौरी राहत प्रदान की है। इसमें क्रमांक संख्या 4, 5, 6, 8, 9, 10, 14 और 19 से संबंधित मामलों में आपने कोई फौरी राहत नहीं दी है; मैं मंत्री महोदय से यह जानना चाहता हूं इन मामलों में फौरी राहत न देने के क्या कारण हैं? मैं मंत्री महोदय से यह भी आग्रह करना चाहूंगा कि भविष्य में ऐसे मामलों में जल्दी-से-जल्दी फौरी राहत प्रदान करने और राशि को बढ़ाने की कृपा करें। इसके अतिरिक्त मेरा मंत्री महोदय से अनुरोध रहेगा कि लिखित सूचना में शेष 74,80,000/-रुपये की राशि के शीघ्रातिशीघ्र भुगतान हेतु आदेश करने की कृपा करें।

जल शक्ति मंत्री : अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय सदस्य को बताना चाहता हूं कि एस0डी0एम0 कार्यालय रोहड़ू के अंतर्गत दिनांक 20 फरवरी, 2022 तक कुल 19 मामले लंबित हैं और डोडरा-क्वार में आपदा राहत के तहत कोई भी मामला लंबित नहीं है। मैं यह भी बताना चाहता हूं कि इन लंबित मामलों का निपटारा इसी वित्तीय वर्ष में कर दिया जाएगा और इसके लिए विभाग द्वारा जिलाधीश शिमला को दिनांक 2 मार्च, 2022 को 5 करोड़ रुपये की राशि प्रदान कर दी गई है। इसके अतिरिक्त, माननीय सदस्य ने यह पूछा है कि कुछ मामलों में 10-10 हजार रुपये की राशि भी नहीं दी गई है और सरकार इस राशि को बढ़ाने बारे विचार करे। मैं सदन को अवगत करवाना चाहता हूं कि कई बार ऐसे गरीब परिवार होते हैं जहां बोडी को लाने या ले जाने के लिए भी उनके पास पैसा नहीं होता। इसलिए संबंधित एस0डी0एम0

09.03.2022/1145/av/as/2

और तहसीलदार को यह कहा गया है कि आप ऐसे मामलों में फौरी राहत तुरंत प्रदान करें। ऐसे मामलों में प्रश्न रोहड़ू या डोडरा-क्वार का नहीं है बल्कि पूरे जिला शिमला का है और जहां-जहां पर भी ऐसे मामले होंगे उनके लिए जिलाधीश शिमला को 5 करोड़ रुपये की राशि प्रदान कर दी गई है। जिलाधीश शिमला उस राशि को आगे सभी उप मण्डलाधिकारी (नागरिक) को देंगे और शेष लंबित मामलों में सारी-की-सारी राशि का भुगतान कर दिया जाएगा।

श्री मोहन लाल ब्राक्टा : अध्यक्ष महोदय, मैंने यह पूछा था कि शेष बचे मामलों में अभी तक फौरी राहत न देने के पीछे क्या कारण रहे हैं।

जल शक्ति मंत्री : अध्यक्ष महोदय, मैं पहले ही बता चुका हूं कि कुछ मामलों में जैसे कोई गरीब व्यक्ति है; तो

टी सी द्वारा जारी

09/03/2022/1150/टी0सी0वी0/डी0सी0/1

प्रश्न संख्या : 4970 ... क्रमागत्

श्री जल शक्ति मंत्री .. जारी

एन0डी0आर0एफ0 और एस0डी0आर0एफ0 के अंतर्गत आने वाले जो केसिज हैं उनमें से जब कोई मृत्यु होती है तो उनके अभिभावक यह चाहते हैं कि हमें तुरंत कुछ राशि दी जाए तो वह उसी व़क्त दे दी जाती है। जो ऐसी इच्छा जाहिर नहीं करते हैं, उनको यह राशि नहीं दी जाती है **लेकिन मैंने कहा कि 4-4 लाख रुपये की राशि सभी को 31 मार्च, 2022 से पहले-पहले दे दी जाएगी**।

अध्यक्ष : माननीय सदस्य, इस प्रश्न का मंत्री जी ने बड़े विस्तार से उत्तर दे दिया है। श्री अनिरुद्ध सिंह जी आप बोलिए।

श्री अनिरुद्ध सिंह : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मुख्य मंत्री जी को बताना चाहूंगा कि यह प्रैक्टिकल प्रोब्लम है और यह प्रोब्लम जिला शिमला की ही नहीं बल्कि पूरे हिमाचल प्रदेश की है। जैसे जिला शिमला में 20 लाख रुपया एस0डी0एम0 ग्रामीण के पास आता है परंतु अब डैथ केस में अधिकतम राशि 4 लाख कर दी गई है और हाउस व आग लगने पर जो राशि दी जाती है उसकी अधिकतम राशि अभी भी 70-75 हजार रुपये ही हैं। पहले 20 लोगों को एक लाख रुपये से पेमेंट हो जाती थी लेकिन आज सिर्फ उससे 5 लोगों को ही भुगतान हो रहा है। इसलिए पेंडेंसी बढ़ती जा रही है। मेरा मुख्य मंत्री जी से आग्रह है कि इस रिलीफ अमाउंट को बढ़ाया जाए ताकि पेंडेंसी शीघ्र खत्म हो सके।

जल शक्ति मंत्री : अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य की चिंता वाजिब है लेकिन मैं माननीय सदन को अवगत करवाना चाहूंगा कि एन0डी0आर0एफ0 और एस0डी0आर0एफ0 के तहत निम्न प्राकृतिक आपदा के कारण होने वाली मृत्यु के लिए ही राहत राशि जारी की जाती है:-

09/03/2022/1150/टी0सी0वी0/डी0सी0/2

1. आग के कारण मृत्यु/घायल
2. बाढ़ के कारण मृत्यु/घायल
3. आसमानी बिजली गिरने के कारण मृत्यु/घायल
4. भूकम्प आने के कारण मृत्यु/घायल
5. जमीन धंसने के कारण मृत्यु/घायल
6. हिम स्खलन के कारण मृत्यु/घायल
7. बर्फ के पिघलने के कारण मृत्यु/घायल
8. सूखा पड़ने के कारण मृत्यु/घायल
9. महामारी फैलने के कारण मृत्यु/घायल
10. चक्रवात के के कारण मृत्यु/घायल
11. अत्यधिक बारिश के कारण मृत्यु/घायल
12. बादल के फटने के कारण मृत्यु/घायल
13. ओलावृष्टि के कारण मृत्यु/घायल

इसके अतिरिक्त प्रदेश सरकार, निम्न कारणों से होने वाली मृत्यु पर भी राहत राशि जारी कर रही है :-

- वाहन दुर्घटना के कारण मृत्यु/घायल
- नाव दुर्घटना के कारण मृत्यु/घायल
- विषैले भोजन के कारण मृत्यु/घायल
- पेड़ या चट्टान से गिरने के कारण मृत्यु/घायल
- गैर-विस्फोटक के कारण मृत्यु/घायल
- सर्पदंश के कारण मृत्यु/घायल
- आवारा/पालतू पशु के हमने से मृत्यु/घायल

- बिजली का करंट लगने से मृत्यु/घायल

09/03/2022/1150/टी0सी0वी0/डी0सी0/3

भारत सरकार द्वारा जारी मापदण्ड सूची में प्रमुख रूप जिन मदों में राहत राशि जारी की जाती है, वह निम्न प्रकार से हैं:?

1. मृत्यु होने पर अनुग्रह राशि- मु0 4.00 लाख रुपये
2. 40 प्रतिशत से 60 प्रतिशत अपंग होने पर मु0 59,100 रुपये
3. 60 प्रतिशत से अधिक अपंग होने पर मु0 2.00 लाख रुपये
4. पक्का/कच्चा मकान पूर्ण रूप से क्षतिग्रस्त होने पर मु0 1,01900 रुपये
5. कच्चा मकान आंशिक रूप से क्षतिग्रस्त होने पर मु0 10,000 रुपये
6. दुकान/पशुशाला की क्षति पर मु0 10,000 रुपये
7. दुकान के समान की क्षति पर मु0 25,000 रुपये
8. बड़े पशु की मृत्यु पर मु0 30,000 रुपये
9. छोटे पशु की मृत्यु पर मु0 30,000 रुपये
10. कृषि भूमि के नुकसान पर मु0 12,200 रुपये प्रति हैक्टेयर
11. भूस्खलन/हिमस्खलन के कारण कृषि भूमि के नुकसान पर मु0 37,500 रुपये प्रति हैक्टेयर
12. स्कूल के नुकसान पर मु0 2.00 लाख रुपये प्रति स्कूल
13. प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र के लिए मु0 2.00 लाख रुपये प्रति केन्द्र
14. पंचायत घर/आंगनबाड़ी/महिला मंडल/युवा केन्द्र/सामुदायिक भवन पर मु0 2.00 लाख रुपये
15. राज्य मार्ग/ प्रमुख जिला मार्ग पर 1.00 लाख रुपये प्रति किलोमीटर
16. ग्रामीण सड़कों व पुलों पर मु0 60,000 रुपये प्रति किलोमीटर/प्रति पुल।

अध्यक्ष : आप द्वारा दी गई सूचना से माननीय सदस्य पूर्ण रूप से संतुष्ट हो गए हैं।

जल शक्ति मंत्री : अध्यक्ष महोदय, इन्होंने यह सारी जानकारी चाहिए थी। इसलिए मैंने यह सदन में रख दी है।

09/03/2022/1150/टी0सी0वी0/डी0सी0/4

श्री रविन्द्र कुमार : अध्यक्ष महोदय, मंत्री जी ने बड़े विस्तार से उत्तर दिया है। इन्होंने कहा है कि 5 करोड़ रुपये की राशि जिला शिमला के लिए जारी की गई है लेकिन बाकी जिलों में भी बहुत सारे केसिज पेंडिंग हैं। क्या इन्होंने जिलावार फंड्ज जारी किए हैं? मैं यह भी जानना चाहता हूं कि यह अनहोनी घटना हुई होती है, जो राहत राशि प्रदान की जाती है क्या उसके लिए कोई समय सीमा निर्धारित करेंगे?

एन0एस0 द्वारा जारी .....

09-03-2022/1155/NS/DC/1

प्रश्न संख्या : 4970 ..... क्रमागत

श्री रविन्द्र कुमार .....जारी

श्री रविन्द्र कुमार : एक अनहोनी घर में हुई होती है और जो राहत राशि प्रदान करते हैं उसे टाइम बाउंड किया जाए। क्या मंत्री जी इसके लिए कोई टाइम फ्रेम फिक्स करेंगे?

जल शक्ति मंत्री : अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने चिंता जाहिर की है और मैंने प्रश्न के उत्तर में कहा है कि शिमला जिले के लिए अभी हमने मार्च माह में लगभग 5 करोड़ रुपये की राशि जारी की है और इसी प्रकार से अन्य जिलों के लिए भी राशि जारी की है। वर्ष 2021-22 में जो राशि आबंटित की है अगर अध्यक्ष महोदय आपकी अनुमति हो और माननीय सदन जानना चाहे तो मैं इसको पढ़ देता हूं। मैं माननीय सदन की सहमति से इस प्रति को सभा पटल पर उप स्थापित करता हूं।

09-03-2022/1155/NS/DC/2

प्रश्न संख्या : 4971

श्री बिक्रम सिंह जरयाल : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री जी को अवगत करवाना चाहता हूं। मेरे क्षेत्र में राजकीय प्राथमिक पाठशाला, चक्की है और यह स्कूल सड़क से 13 किलोमीटर दूर है। इस स्कूल के आज से 30 वर्ष पहले कमरे बने थे और इसकी छत उड़ गई है और वहां पर विद्यार्थी बैठ नहीं सकते हैं तथा उनको मिडल स्कूल में बिठाया जा रहा है। मंत्री जी इसके लिए धनराशि स्वीकृत करने की कृपा करें। अध्यक्ष महोदय, मेरे क्षेत्र की राजकीय प्राथमिक पाठशाला, बसोल्दा भारी बरसात के कारण ढह गई है। छात्रों को मिडल स्कूल में बिठाया जा रहा है। इसके लिए भूमि की व्यवस्था हो गई है। मेरा मंत्री जी से आग्रह है कि वहां पर दो कमरे बनाने के लिए धनराशि स्वीकृत करें ताकि स्टूडैंट्स शिक्षा ग्रहण कर सकें। इसके अतिरिक्त राजकीय प्राथमिक पाठशाला, जुंगला जोकि एजुकेशन ब्लॉक, चुवाड़ी के अंतर्गत आता है। यहां पर कोई भी कमरा नहीं है। दो कमरे थे और वे गिर चुके हैं। इस स्कूल में छात्रों की संख्या भी ज्यादा है। आपने एक कमरा बनाने के लिए 3.15 लाख रुपये की राशि दी है। अगर आप एक और कमरे के लिए धनराशि स्वीकृत कर दें तो मंत्री जी की बड़ी कृपा होगी। राजकीय प्राथमिक पाठशाला, बडेई के लिए आपने 15.39 लाख रुपये की धनराशि दी है और यह स्कूल सड़क से 9 किलोमीटर दूर है और यह स्कूल बेकवर्ड पंचायत में पड़ता है। आप इसकी कंप्लीशन के लिए लगभग 5 लाख रुपये की राशि और स्वीकृत करें तभी इस स्कूल के तीन कमरे तैयार हो सकते हैं। इसके अतिरिक्त राजकीय प्राथमिक पाठशाला, बिहाली के लिए भी धनराशि स्वीकृत करें। मैं मंत्री जी से इन स्कूलों के निर्माण के लिए धनराशि स्वीकृत करने का आश्वासन चाहता हूं।

शिक्षा मंत्री : अध्यक्ष महोदय, **माननीय सदस्य ने चक्की, बसोल्दा, जुंगला और बिहाली व बडेई स्कूलों के नाम लिए है और इन स्कूलों में जिस भी धनराशि की आवश्यकता पड़ेगी उसे आपको उपलब्ध करवा दिया जाएगा ताकि इन स्कूलों के भवनों का निर्माण पूरा हो सके।**

09-03-2022/1155/NS/DC/3

प्रश्न संख्या : 4972

श्री जगत सिंह नेगी : अध्यक्ष महोदय, मैं केवल यह कहना चाहूंगा कि बागवानी विभाग किसी समय में बहुत ही बढ़िया विभाग था। अब इसमें जंग लग चुका है। जो मैंने प्रश्न पूछा

है उन सारी स्कीमों में प्रूनिंग कैंची और पाईपें बांटने के सिवाय कोई काम नहीं किया है। मैं, मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि प्लांट मटीरियल और जो स्कीमें आपने दी हैं तो क्या विभाग इनको दोबारा से सक्रिय करेगा?

जल शक्ति मंत्री .....श्री बी0 एस0 द्वारा जारी।

09.03.2022/1200/बी.एस./एच0के0/-1

जल शक्ति मंत्री : अध्यक्ष जी, मैं प्रदेश के मुख्य मंत्री जी और देश के प्रधान मंत्री जी का भी धन्यवाद करना चाहूंगा कि केवल और केवल मात्र जिला किन्नौर के लिए एक ऐसी बड़ी योजना जिसका शुभारंभ मुख्य मंत्री जी ने किया है, आदरणीय नेगी जी, आज तक शायद जिला किन्नौर के लिए इतना पैसा नहीं मिला होगा, भारत सरकार से 50 करोड़ रुपए की राशि स्वीकृत हो करके आई है और इसमें 100 प्रतिशत फंडिंग भारत सरकार की ही है। प्रदेश को इसमें कुछ नहीं देना है। आप 50 करोड़ रुपए मिलने पर भी कह रहे हैं कि विभाग को जंग लग गया है। आपको तो मुख्य मंत्री जी का और माननीय प्रधान मंत्री जी का धन्यवाद करना चाहिए। मैं यह कहना चाहता हूं कि सबसे ज्यादा राशि किन्नौर जिला को दी गई है।

प्रश्न काल समाप्त

09.03.2022/1200/बी.एस./एच0के0/-2

व्यवस्था का प्रश्न

अध्यक्ष : माननीय सदस्य श्री राजेन्द्र राणा जी कुछ कहना चाहते हैं।

श्री राजेन्द्र राणा : माननीय अध्यक्ष जी, मैं सबसे पहले आपका धन्यवाद करना चाहता हूं कि आपने मुझे बोलने का मौका दिया। मैं आपके माध्यम से शहरी विकास मंत्री जी के ध्यान में विषय लाना चाहता हूं, आज भी सभी समाचार पत्रों की सुर्खियां बना है कि नगर परिषद बद्दी के नौ पारषदों में से पांच पारषदों ने 2 फरवरी, 2022 को अविश्वास प्रस्ताव पारित करके उपायुक्त, सोलन को दिया और वे पांचों शारीरिक रूप से वहां मौजूद रहे हैं। उन्होंने बाद 15 फरवरी को फिर रिमांइडर दिया कि वे अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के खिलाफ अविश्वास

प्रस्ताव ले करके आए हैं। इन्होंने का कि अध्यक्ष और उपाध्यक्ष को नोटिस जारी किया जाए कि वे फिर से विश्वास हासिल करें और 22 फरवरी को ए0डी0सी0 के माध्यम से वहां के जो पांच पारषद, जिन्होंने अविश्वास प्रस्ताव दिया था,उनमें से एक तरसेम चौधरी को नोटिस जारी होता है कि आपने लगातार तीन मीटिगें अटेंड नहीं की है, इसलिए क्यों न आपकी सदस्यता रद्द कर की जाए? महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री जी के ध्यान में लाना चाहता हूं कि जो तीन मीटिगों का हवाला दिया जा रहा है उसमें से दो में गणपूर्ति का अभाव था और दूसरा यह कि यहां पर भेदभाग साफ -साफ नजर आ रहा है कि इसमें से बार्ड न0-4 के पार्षद संतोष जी हैं, उन्होंने लगातार चार मीटिगें अटेंड नहीं की है और उन्हें कोई नोटिस नहीं दिया गया है। मैं दिनांक का हवाला भी दे रहा हूं। दिनांक 16 जुलाई, 17 सितम्बर, 20 नवम्बर और 17 दिसम्बर, ये चार दिन वे भी बैठकों में उपस्थित नहीं रहे हैं। अब मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि कल सैकड़ों की संख्या में लोग ने बद्दी से नालागढ़, एस0डी0एम0 के समक्ष जा करके प्रदर्शन किया है। वहां पर बाजार बंद हुआ और सरकार की भी फ़जिहत हो रही है। मेरा यह कहना है कि जब कानूनी तौर पर 15 दिन के अंदर विश्वास हासिल करना है, इस मामले को राजनीतिक दबाव के कारण दबाने की कोशिश की जा रही है, इस मामले को लटकाने की कोशिश की जा रही है। मैं मंत्री जी से निवेदन करना चाहता हूं कि आप इस पर अपना वक्तव्य दें। क्योंकि जो विश्वास मत हासिल करेगा, वह अपना अधिकार ले ले। इसमें कोई किन्तु और प्रन्तु वाला विषय नहीं है।

09.03.2022/1200/बी.एस./एच0के0/-3

शहरी विकास मंत्री : अध्यक्ष जी, माननीय सदस्य ने सदन के ध्यान में लाया है कि बद्दी नगर परिषद में कोई अविश्वास प्रस्ताव आया है या कोई नोटिस किसी को गया है। यह बात हमारे संज्ञान में नहीं है, यह डायरेक्टर लैवल तक या डी0सी0 के पास गया होगा। यदि माननीय सदस्य वास्तव में इसमें नियम-62 के अन्तर्गत नोटिस देते तो मैं सारी जानकारी ले करके सदन में बता सकता **था। मैं इसकी जानकारी ले लूंगा और उसके बाद माननीय सदस्य को अवगत करवा दूंगा।**

श्री एन0 जी0 द्वारा जारी...

09-03-2022/1205/एच.के.-एन.जी./1

अध्यक्ष जारी..... जारी

माननीय सदस्य श्री परमजीत सिंह जी कुछ कहना चाहते हैं।

श्री परमजीत सिंह (दून) : अध्यक्ष महोदय, बद्दी से हमीरपुर काफी दूर है। माननीय सदस्य श्री राजेन्द्र राणा जी ने यहां पर गलत कहा है और यह राजनीतिक षड़यंत्र है। श्री तरसेम चौधरी लगातार 7 माह से नहीं आ रहा था। वहां पर जो अविश्वास प्रस्ताव दिया गया है उससे पहले पार्षदों ने कम्पलेंट की है। वहां पर सभी लोग, चाहे वे कांग्रेस के थे या भाजपा के उनकी अटैंडेंस लगी हुई और श्री तरसेम चौधरी ही है जो 7 माह से लगातार नहीं आ रहा था। दून विधान सभा क्षेत्र में यह केवल राजनीतिक मुद्दा बनाने की कोशिश की जा रही है और यह केवल सरकार को बदनाम करने की कोशिश है। माननीय सदस्य श्री राजेन्द्र राणा जी आपको इसके बारे में पूरा पता नहीं है और जिसने भी आपको यह फीडबैक दिया है वह बहुत गलत दिया है, वे लोग अपनी राजनीतिक रोटियां सेक रहे हैं और इस मामले में ऐसा कुछ नहीं है।

09-03-2022/1205/एच.के.-एन.जी./2

<u>कागज़ात सभा पटल पर</u>

अध्यक्ष : अब माननीय ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री कागज़ात सभा पटल पर रखेंगे।

ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री : अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से महात्मा गान्धी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम, 2005 के अन्तर्गत महात्मा गान्धी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के सोशल लेखा प्रतिवेदन, वर्ष 2017-18 व 2018-19 (विलम्ब के कारणों सहित) की एक-एक प्रति सभा पटल पर रखता हूं।

अध्यक्ष : अब माननीय बहुउद्देश्यीय परियोजनाएं एवं ऊर्जा मंत्री कागज़ात सभा पटल पर रखेंगे।

बहुउद्देश्यीय परियोजनाएं एवं ऊर्जा मंत्री : अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से संस्था अधनियम, 1860 के अन्तर्गत हिमऊर्जा (हिमाचल प्रदेश ऊर्जा विकास अभिकरण) हिमाचल प्रदेश का वार्षिक प्रशासनिक प्रतिवेदन, वर्ष 2020-21 की प्रति सभा पटल पर रखता हूं।

09-03-2022/1205/एच.के.-एन.जी./3

सदन की समितियों के प्रतिवेदन

अध्यक्ष : अब श्रीमती आशा कुमारी, सभापति, लोक लेखा समिति, समिति के निम्न प्रतिवेदनों की एक-एक प्रति सभा में उपस्थापित करेंगी तथा सदन के पटल पर रखेंगी।

श्रीमती आशा कुमारी : अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से लोक लेखा समिति के निम्न प्रतिवेदनों की एक-एक प्रति सभा में उपस्थापित करती हूं तथा सदन के पटल पर रखती हूं।

i. समिति का 210वां मूल प्रतिवेदन (तेरहवीं विधान सभा) जोकि भारत के नियन्त्रक एवं महालेखापरीक्षक के प्रतिवेदन वर्ष 2011-12 (राज्य के वित्त/राजस्व क्षेत्र) पर आधारित तथा आबकारी एवं कराधान विभाग से सम्बन्धित है;

ii. समिति का 211वां मूल प्रतिवेदन (तेरहवीं विधान सभा) जोकि भारत के नियन्त्रक एवं महालेखापरीक्षक के प्रतिवेदन वर्ष 2012-13 (राज्य के वित्त/राजस्व क्षेत्र) पर आधारित तथा आबकारी एवं कराधान विभाग से सम्बन्धित है; और

iii. समिति का 212वां मूल प्रतिवेदन (तेरहवीं विधान सभा) जोकि भारत के नियन्त्रक एवं महालेखापरीक्षक के प्रतिवेदन वर्ष 2013-14 (राज्य के वित्त/राजस्व क्षेत्र) पर आधारित तथा आबकारी एवं कराधान विभाग से सम्बन्धित है ।

अध्यक्ष : अब कर्नल इन्द्र सिंह, सभापति, लोक उपक्रम समिति, समिति के निम्न प्रतिवेदनों की एक-एक प्रति सभा में उपस्थापित करेंगें तथा सदन के पटल पर रखेंगें।

कर्नल इन्द्र सिंह : अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से लोक उपक्रम समिति के निम्न प्रतिवेदनों की एक-एक प्रति सभा में उपस्थापित करता हूं तथा सदन के पटल पर रखता हूं।

09-03-2022/1205/एच.के.-एन.जी./4

i. समिति का 53वां कार्रवाई प्रतिवेदन (तेरहवीं विधान सभा) जोकि समिति के 18वें मूल प्रतिवेदन (तेरहवीं विधान सभा) (वर्ष 2019-20) में अन्तर्विष्ट सिफारिशों पर आधारित तथा हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत निगम सीमित से सम्बन्धित है; और

ii. समिति का 54वां कार्रवाई प्रतिवेदन (तेरहवीं विधान सभा) जोकि समिति के 13वें मूल प्रतिवेदन (तेरहवीं विधान सभा) (वर्ष 2018-19) में अन्तर्विष्ट सिफारिशों पर आधारित तथा सावड़ा कुडडु हाईड्रो इलैक्ट्रिक प्रोजैक्ट से सम्बन्धित है ।

अध्यक्ष : अब श्री रमेश चन्द ध्वाला, सभापति, प्राक्कलन समिति, समिति के निम्न प्रतिवेदनों की एक-एक प्रति सभा में उपस्थापित करेंगे तथा सदन के पटल पर रखेंगे।

श्री रमेश चन्द ध्वाला : अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से प्राक्कलन समिति का 21वां मूल प्रतिवेदन (तेरहवीं विधान सभा) जोकि प्रदेश में महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा चलाई जा रही विभिन्न योजनाओं/कार्यों एवं आय-व्ययक प्राक्कलनों की संवीक्षा पर आधारित तथा महिला एवं बाल विकास विभाग से सम्बन्धित की प्रति सभा में उपस्थापित करता हूं तथा सदन के पटल पर रखता हूं।

09-03-2022/1205/एच.के.-एन.जी./5

वित्तीय वर्ष 2022-2023 के लिए बजट अनुमान पर सामान्य चर्चा एवं समापन ।

अध्यक्ष : अब वित्तीय वर्ष 2022-2023 के लिए बजट अनुमानों पर सामान्य चर्चा होगी। आज ही चर्चा का समापन माननीय मुख्य मंत्री जी के उत्तर से होगा। इसलिए मेरा सभी माननीय सदस्यों से निवेदन है कि जो समय आवंटित किया गया है, 13 से 15 मिनट के बीच, इस व्यवस्था को ध्यान में रखें। आज 7 माननीय सदस्य विपक्ष की ओर से और 5 सदस्य सत्तापक्ष की ओर से बोलने वाले हैं। उसके बाद माननीय मुख्य मंत्री जी इस चर्चा का उत्तर भी देंगे। मुझे बार-बार यहां से ऐसा न कहा पड़े कि वाइंडअप कर दीजिए या बैल बजानी पड़े।...व्यवधान.. इसमें बाइंडिग की कोई बात नहीं है। ऐसे तो पिछले कल सत्र रात्रि 09.10 बजे तक चला है। सत्तापक्ष से काफी सदस्य बोलने वाले थे तथा विपक्ष की ओर कोई नहीं था और आपके केवल दो ही सदस्य यहां पर बैठे हुए थे। एक ऊना के माननीय सदस्य थे और एक कांगड़ा के माननीय सदस्य थे। पिछले कल शाम को भी यही तय हुआ था कि चाहे यह सत्र 10.00 बजे तक चले। लेकिन विपक्ष की ओर से कोई नहीं मौजूद था। जब इस माननीय सदन में बजट रखा गया था तब भी मैंने कहा था कि आवंटित समय में ही बात रखनी है। अब इस चर्चा में माननीय सदस्य श्री रोहित ठाकुर जी भाग लेंगे। उससे पहले माननीय मुख्य मंत्री जी कुछ कहना चाहते हैं।

मुख्य मंत्री : अध्यक्ष महोदय, आपने जो यह व्यवस्था दी है

श्री जे.एस. द्वारा जारी.....

09.03.2022/1210/JS/YK/1

मुख्य मंत्रीः---जारी-----

इस बजट पर जो माननीय सदन में चर्चा हुई उसका मुझे उत्तर भी देना है। सभी सदस्य अगर समय की सीमा का पालन करें तो मैं समझता हूं कि अच्छा रहेगा। पार्टिसिपेशन सबका हो, हमें इसमें कोई आपत्ति नहीं है। पिछले कल शाम तक आपकी ओर से, विपक्ष की ओर से यहां पर संख्या नहीं थी और शायद ज्यादा सदस्य बोलने वाले नहीं थे। सदन तो

रात के 9.10 बजे तक चला। मुकेश अग्निहोत्री जी आप तो जल्दी सो जाते हैं। अध्यक्ष महोदय, यदि आपकी अनुमति हो तो मैं युक्रेन वाली स्टेटमैंट को यहां पर पढ़ता हूं।

अध्यक्ष महोदय, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। अध्यक्ष महोदय, युक्रेन से संबंधित जो इस सदन में जानकारी देने का क्रम लगातार बना हुआ है वह इसलिए बना हुआ है कि हिमाचल प्रदेश के सभी लोग इस बात से चिंतित थे कि जो बच्चे वहां पर फंसे हुए थे वे सकुशल वापिस आने चाहिए। इसलिए जब भी जो सूचना हमें प्राप्त होती है तो उस सूचना के माध्यम से मैं सदन को भी अपडेट करता हूं, उसके बाद मीडिया के माध्यम से लोगों तक भी वह जानकारी पहुंचाई जाती है।

अध्यक्ष महोदय, मैं यह स्टेटमैंट यहां पर पढ़ता हूं। युक्रेन में युद्ध की स्थिति से उत्पन्न संकट में वहां पर फंसे प्रदेश के छात्रों की सकुशल वापसी के बारे में मैं नियमित रूप से सदन को अवगत करवाता रहा हूं, उसी क्रम में आज भी वक्तव्य देना चाहूंगा। मुझे कहते हुए संतोष हो रहा है कि प्रदेश के 441 छात्र अब सकुशल वापिस आ चुके हैं। 8 छात्र ऐसे हैं, जो युक्रेन के पड़ौसी देशों में सुरक्षित पहुंच गए हैं तथा अपनी इच्छा से फिलहाल भारत वापिस नहीं आना चाहते हैं। अब प्रदेश के केवल 9 छात्र वापिस आने शेष हैं, इनमें से 7 पोलैंड अथवा रोमानिया पहुंच चुके हैं। युक्रेन के सुमी शहर में प्रदेश के 2 ही छात्र फंसे थे। विदेश मंत्रालय की सूचना के अनुसार सुमी क्षेत्र में फंसे सभी भारतीयों को वहां से निकाल दिया गया है और पश्चिमी सीमा की ओर ले जाया जा रहा है। उन्हें भी ऑप्रेशन गंगा के तहत विशेष उड़ानों द्वारा वापिस भारत पहुंचाया जाएगा। अतः शेष बचे 9 प्रदेशवासी शीघ्र ही

09.03.2022/1210/JS/YK/2

वापिस पहुंच जाएंगे। केन्द्र सरकार के अथक प्रयासों से ऑप्रेशन गंगा अपने अंतिम चरण में है। केन्द्र सरकार द्वारा युक्रेन और रूस दोनों देशों से बातचीत की जाती रही है। भारत सरकार के भरसक प्रयासों के द्वारा भारतीयों की सकुशल वापसी सुनिश्चित हो रही है। मैं

इसके लिए केन्द्र सरकार का आभार प्रकट करता हूं। इस सन्दर्भ में प्रदेश सरकार, विदेश मंत्रालय और युक्रेन व पड़ौसी देशों में फंसे प्रदेश के छात्रों व उनके परिवारों से लगातार सम्पर्क में है। यह संकटकाल शीघ समाप्त हो, ऐसी मैं कामना करता हूं। धन्यवाद।

09.03.2022/1210/JS/YK/3

अध्यक्षः अब माननीय सदस्य, श्री रोहित ठाकुर जी चर्चा में भाग लेंगे।

श्री रोहित ठाकुर (जुब्बल-कोटखाई)ः अध्यक्ष महोदय, जो माननीय मुख्य मंत्री, श्री जय राम ठाकुर जी ने 4 मार्च, 2022 को इस माननीय सदन में वर्ष 2022-23 के बजट अनुमान प्रस्तुत किए हैं, उस पर चर्चा चली है, मैं भी अपने आपको इसमें शामिल करता हूं।

अध्यक्ष महोदय, चुनावी वर्ष है। स्वाभाविक है जनता को रीझाने का, लुभाने का प्रयास किया गया है। मैंने ये पूरा बजट पढ़ा है। मात्र एक-दो क्षेत्र को छोड़ कर अगर आप सम्पूर्ण प्रदेश के जो महत्वपूर्ण भाग हैं, उनके बजट में कटौती की गई है। सामाजिक क्षेत्र में अवश्य आपने बढ़ौत्तरी की है उसके लिए मैं आपको बधाई देता हूं। इससे भी जो आपकी महत्वपूर्ण योजना थी, जिसे एक तरह से आपका फ्लैगशिप प्रोग्राम भी कहा जा सकता था "मुख्य मंत्री सहारा योजना" इसमें भी जिस तरह से आपने अन्य घटकों में बढ़ोत्तरी की लेकिन इसमें बढ़ोत्तरी नहीं हुई। मैंने अपने राज्यपाल अभिभाषण में इस ओर भी आपसे आग्रह किया था। साथ-ही-साथ आपने इन्कम क्राइटेरिया में जो रिलैक्सेशन दी यह भी स्वागत योग्य है लेकिन मैं समझता हूं कि जो हमारा असहाय वर्ग होता है, उसमें विधवा बहनें होती हैं, अपंग होते हैं उनमें भी इन्कम क्राइटेरिया में रिलैक्सेशन हो। यह भी मैं समझता हूं कि यह मानवता की एक बहुत बड़ी सेवा होगी। यहां पर अन्य जिन क्षेत्रों में कार्य हुआ है।

श्री एस.एस. द्वारा जारी-----

09.03.2022/1215/SS-YK/1

श्री रोहित ठाकुर क्रमागत :

उदाहरण के तौर पर मैं विधायक निधि की अवश्य बात करूंगा। प्रो0 प्रेम कुमार धूमल जी ने विधायक निधि को वर्ष 1999 में मात्र 15 लाख रुपये से प्रारम्भ किया था। हालांकि उस वक्त के 15 लाख रुपये भी काफी हुआ करते थे। 15 लाख रुपये से यह यात्रा आपकी प्रारम्भ हुई। हालांकि एक वर्ष तक वह विधायक निधि चली थी। उसके उपरांत वर्ष 2003 में वीरभद्र सिंह जी की सरकार ने पुनः विधायक निधि 15 लाख रुपये से प्रारम्भ की थी और जो हमारा अंतिम बजट 2017-18 का था उसमें इसे 1.10 करोड़ रुपये के आस-पास तक लाए हैं। फिर आपने विधायक निधि को 2 करोड़ रुपये तक बढ़ाया है। इसके लिए आपको बहुत-बहुत बधाई है। स्वैच्छिक निधि भी जो कांग्रेस कार्यकाल के दौरान 2 लाख रुपये से प्रारम्भ हुई थी आज वह 12 लाख रुपये तक पहुंची है। मैं समझता हूं कि चाहे पक्ष या विपक्ष की बात हो, यह पूरे प्रदेश के हित की बात है।

तीसरा, आपने यहां पर विशेष रूप से बात रखी है कि जो हमारी नाबार्ड के माध्यम से डी0पी0आर्ज0 जाती हैं उसकी सीलिंग 135 करोड़ रुपये से 150 करोड़ रुपये की है। अगर आप इस 150 करोड़ का अध्ययन करेंगे तो इसमें 80 करोड़ वह है जो 2014 से 2017 के बीच कांग्रेस सरकार के कार्यकाल के दौरान सीलिंग रखी गई थी। आपके कार्यकाल के दौरान यह 70 करोड़ रुपये बढ़ी है। यह हमारा पहाड़ी क्षेत्र है, जिस तरह से आपका क्षेत्र है, 15 करोड़ रुपये में मुश्किल से सिर्फ एक डी0पी0आर0 बनती है। सैंट्रल रोड फंड में हमारे क्षेत्र को पैसा नहीं मिला। प्रधान मंत्री ग्रामीण सड़क योजना के तहत भी हमारे क्षेत्र वंचित रहे। वर्ल्ड बैंक के तहत भी हमारे क्षेत्र की कोई योजना नहीं आई है। चूंकि अभी आपने उत्तर देना है इसलिए मेरा आपसे आग्रह रहेगा कि वर्तमान में 70 करोड़ रुपये की जो सीलिंग है इसको 100 करोड़ रुपया किया जाए। 150 करोड़ रुपये से 180 करोड़ रुपया किया जाए। भौगोलिक दृष्टि से जो हमारा क्षेत्र है उससे आप भलीभांति परिचित हैं। मैं लोक निर्माण विभाग की बात कर रहा था। सड़कें हमारे पहाड़ी क्षेत्र की भाग्य रेखाएं हैं। अगर आप 2021-22 और 2022-23 के बजट अनुमानों की तुलना करेंगे तो जहां 2021-22 में इसमें

4502 करोड़ रुपये का प्रावधान रखा गया था वहीं वर्तमान में यह घटाकर 4373 रखा गया है।

09.03.2022/1215/SS-YK/2

इसमें लगभग 150 करोड़ रुपये क कटौती हुई है। मैं समझता हूं कि यह बहुत चिंताजनक बात है क्योंकि सड़कें हमारी जीवन रेखाएं हैं। आने वाले समय में एयर कनैक्टिविटी हमारे प्रदेश में हो, वह अच्छी बात है। लेकिन धरातल पर क्या है वह हम सभी जानते हैं। हिमाचल प्रदेश में रेल कनैक्टिविटी हो। आज मैं कह सकता हूं कि हिमाचल प्रदेश की 90.9 परसैंट जो means of communication है वे सड़कें हैं। अगर हम सड़कों के लिए बजटरी अलॉटमैंट घटाएंगे तो हिमाचल प्रदेश का विकास सम्भव नहीं होगा। आपकी बहुत-सी महत्वपूर्ण पोस्टें रिक्त चली हैं। तीन चीफ इंजीनियर की पोस्टें रिक्त चली हैं। हमारी एस0ई0 की 11 पोस्टें रिक्त चली हैं। अगर मैं अपने रोहड़ू वृत की बात करूंगा तो वहां पर एक वर्ष से एस0ई0 नहीं है। आपके सैंकड़ों एक्सियन के पद खाली पड़े हैं। यह भी मैं समझता हूं कि हम सब के लिए चिंता का विषय है। पीछे नितिन गडकरी जी का बयान आया था कि हिमाचल प्रदेश के लिए लगभग 5600 करोड़ रुपये के 13 रोपवे स्वीकृत हुए। मुझे उनके नेशनल हाईवे भी याद आए। उस वक्त उन्होंने हिमाचल प्रदेश के लिए 69 नए नेशनल हाईवे घोषित किए थे। अगर आप इन चार वर्ष का मूल्यांकन करेंगे तो एक भी राष्ट्रीय उच्च मार्ग प्रदेश के लिए इन चार वर्षों में स्वीकृत नहीं हुआ है। इसी बजट में अगर आप पी0डब्ल्यू0डी0 की बात करेंगे तो कहीं पर भी टनल्स का विवरण नहीं है। क्योंकि हमारा पहाड़ी क्षेत्र है आपकी ऑल वैदर कनैक्टिविटी के लिए आने वाले समय में टनल्स का निर्माण अत्यंत महत्वपूर्ण है। इसका कहीं पर विवरण नहीं है। मैं समझता हूं कि जहां टनल्स के माध्यम से डिस्टैंस शॉर्ट होंगे वहां साथ-ही-साथ पर्यावरण की रक्षा होगी और आपको ऑल वैदर कनैक्टिविटी पहाड़ी क्षेत्र में मिलेगी। ए0एम0पी0 में आपने जो हमारे टूरिज्म की दृष्टि से क्षेत्र विकसित हैं वहां पर स्पैसिफिकेशन 5 वर्ष से 3 वर्ष की है वह स्वागत योग्य है। लेकिन जो हमारे स्नो बाउंड क्षेत्र हैं वहां पर भी यह मापदंड लागू किया जाए। वर्तमान में वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए जो आपने ए0एम0पी0 की एप्रूवल दी है वह प्रति निर्वाचन क्षेत्र लगभग 30 मीटर के आस-पास है। अगर आप हमारे पहाड़ी क्षेत्र की बात करेंगे या चौपाल रोहड़ू की बात करेंगे तो हमारे क्षेत्र में लगभग 1200 किलोमीटर सड़कें हैं

इसको बढ़ाने की आवश्यकता है। मुझे याद है कि 2016-17 में अगर मैं अपने क्षेत्र की बात करूं तो कोई 80 किलोमीटर के आस-पास

जारी श्रीमती के0एस0

09.03.2022/1220/KS/AS/1

श्री रोहित ठाकुर जारी---

AMP की अप्रूवल्ज़ उस दौरान मिला करती थी। आपने स्पेसिफिकेशन बढ़ाई है पहले 18-20 एम.एम. के लगभग हुआ करती थी अब 30 एम.एम. है जो कि एक स्वागत योग्य कदम है लेकिन जो 30 किलोमीटर आपने कम कर दिया, मैं समझता हूं कि वह ऊंट के मुंह में जीरा है। इसको भी बढ़ाने की आवश्यकता है। AMP जितनी आपकी कंसीच्युएंसी में आपकी रोड़ लैंथ है उसका कम से कम 10 प्रतिशत के आसपास उसकी स्वीकृति मिले, यह महत्वपूर्ण है।

अध्यक्ष महोदय, स्वास्थ्य क्षेत्र बहुत ही महत्वपूर्ण है लेकिन दुर्भाग्यवश कोविड काल में आपने बजटरी अलॉटमैंट में इस क्षेत्र में भी कटौती की है। लगभग 8.7 परसेंट के आसपास कटौती हुई है। जो वर्ष 2021-22 में 3016 के आसपास था, आज वह घटकर 2752 रह चुका है। यह भी स्वास्थ्य क्षेत्र के प्रति हमारी सोच को दर्शाता है। पीछे इस बारे में एक प्रश्न लगा था, अगर आप हैल्थ वर्कर्ज़ की बात करें, चाहे मेल और फीमेल हैल्थ वर्कर्ज़ की बात है, हिमाचल प्रदेश में लगभग 1100 पोस्टें खाली हैं। 60 परसेंट हमारे सब सैंटर्ज़ बिना मेल और फीमेल हैल्थ वर्कर्ज़ के हैं। एम्ज़ की तो खैर बड़ी बात है। आने वाले समय में वह भी खुले लेकिन जो स्वास्थ्य संस्थान का बेसिक युनिट होता है, उसकी दशा आप सभी के सामने हैं।

अध्यक्ष महोदय, 15 करोड़ रुपये का प्रावधान आपने एम्बुलैंसिज़ के लिए किया है, यह स्वागत योग्य है लेकिन पहले की जो एम्बुलैंसिज़ हैं, उनमें ड्राईवर्ज़ नहीं हैं। मैं चौपाल का उदाहरण सुन रहा था, शिमला ग्रामीण का उदाहरण सुन रहा था। ड्राईवर्ज़ की बहुत सी पोस्टें रिक्त पड़ी हैं। मैं पीछे स्वास्थ्य विभाग के एक वरिष्ठ अधिकारी का कथन पढ़ रहा था

कि यहां पर स्वास्थ्य विभाग में डॉक्टर्ज़ की ज़ीरो वेकेंसीज़ हैं। अगर मैं अपने क्षेत्र की बात करुं, धर्मशाल के सत्र के दौरान मैंने माननीय सदन में प्रश्न उठाया था, उस वक्त मुझे बताया गया था कि 3 प्राईमरी हैल्थ सैंटर खाली थे, आज वह

09.03.2022/1220/KS/AS/2

संख्या बढ़कर 7 हो चुकी है। चाहे रेणुका की बात हो, शिलाई की बात हो, जितने भी हमारे दुर्गम क्षेत्र हैं, वहां पर स्वास्थ्य सुविधा का बहुत अभाव है। चुनाव के समय में अवश्य ट्रॉमा सैंटर का चार वर्ष के बाद इस सरकार ने शिलान्यास किया। वर्ष 2018 में इसकी घोषणा हुई थी और चुनाव के दौरान इसका शिलान्यास किया गया लेकिन मैं समझता हूं कि डॉक्टर के नाम पर, पैरा मैडिकल स्टाफ के नाम पर एक भी व्यक्ति की आज तक कोटाखाई हॉस्पिटल में ज्वाइनिंग नहीं हुई है। यह दर्शाता है कि कहीं न कहीं सोच में कमी है।

अध्यक्ष महोदय, जो हमारे होर्टिकल्चर और कृषि क्षेत्र हैं, ये बहुत महत्वपूर्ण क्षेत्र हैं। कोविड काल के दौरान भी हमारी प्रोग्रैस बाकी प्रदेशों से बेहतर है उसका कारण यही है कि हमारे एग्रीकल्चर और होर्टिकल्चर सैक्टर्ज़ ने अच्छा प्रदर्शन किया था लेकिन होर्टिकल्चर सैक्टर में भी वर्तमान में लगभग 3 करोड़ के आसपास की कटौती हुई है। अगर आप पिछले वर्ष से तुलना करेंगे, वर्ष 2021-22 में लगभग 543 करोड़ के लगभग प्रावधान था आज वह घटकर 540 करोड़ रह चुका है। लगभग 65 पोस्टें एची.डी.ओज़. की समस्त हिमाचल प्रदेश में रिक्त पड़ी हैं। इस तरह से आगे कैसे हमारा होर्टिकल्चर विभाग चल पाएगा? नुकसान का आकलन समय पर नहीं होता और राहत तो खैर दूर की बात है। जो भी उसमें विवरण दिया गया, चाहे प्रोसैसिंग प्लांट की बात हो, सी.ए.स्टोर्ज़ की बात हो, ग्रेडिंग/पैकिंग लाइन्ज़ की बात हो, ये सभी की सभी आपका जो 1134 करोड रुपये का जो होर्टिकल्चर का प्रोजैक्ट था, जो कांग्रेस सरकार की, वीरभद्र सिंह जी की, मैडम विद्या स्टोक्स जी की देन थी, उसके माध्यम से इसकी स्वीकृति प्राप्त हुई थी। इसी प्रकार कृषि क्षेत्र भी बहुत ही महत्वपूर्ण क्षेत्र है। जिस तरह से हमारे राष्ट्र के प्रथम प्रधान मंत्री कहा

करते थे कि "Everything can wait, but not agriculture'. मैं समझता हूं कि वर्तमान बजट में कृषि क्षेत्र की अनदेखी भी हुई है। लगभग 2/3 पोस्टें

09.03.2022/1220/KS/AS/3

ए.डी.ओज़. की हैं। वर्तमान में वे रिक्त चली हैं। जहां हमारा एक नारा हुआ करता था कि वर्ष 2022 में हमने किसानों की आय दोगुना करनी है, वह दोगुना तो नहीं हुई लेकिन आपने खादों के मूल्य अवश्य दो गुना हो चुके हैं। जो खाद का कट्टा पोटाश का साढ़े आठ सौ का मिला करता था, उसकी कीमत बढ़कर 1700 हो चुकी है। यही दशा 12-32-16, 15-15 सुफ़ला खाद, कैल्शियम नाइट्रेट की है। ये सब बातें भी वर्तमान में देखनी होंगी। यहां एक टारगेट दिया गया कि आने वाले समय में हमारे प्रदेश में प्राकृतिक खेती होगी। वह तो खुद ही हो चुकी है जब हमें खाद नहीं मिल रही है। फंफूद नाशक, कीटनाशक जो अनुदान पर दवाइयां मिला करती थीं, वो भी वर्तमान में रुक चुकी हैं। इसी तरह से अगर आप केंद्र के बजट की भी बात करेंगे तो जो भी जनता-जनार्दन से जुड़ी हुई योजनाएं हुआ करती थीं, चाहे फसल बीमा योजना की बात हो, मनरेगा की बात हो, फर्टिलाइज़र सबसिडी की बात हो, पैट्रोलियम सबसिडी की बात हो हर जगह उसमें भी कटौती की गई है।

अध्यक्ष महोदय, पशु-पालन के बारे में सिंघा साहब ने यहां पर बड़े विस्तार से पिछले कल बात रखी है।

श्रीमती अ0व0 द्वारा जारी---

09.03.2022/1225/av/as/1

श्री रोहित ठाकुर -----जारी

इस बजट में 'सबका साथ और सबका विकास' की बात कही गई है। लेकिन मैं चाहता हूं कि सबका साथ और सबका विकास केवल चुनाव तक सीमित न हो। मेरे चुनाव क्षेत्र में भी माह जुलाई, 2021 में जुब्बल और कोटखाई में उप मण्डल खोलने की घोषणा की गई थी।

हमने उसका स्वागत किया और उसके बारे में नोटिफिकेशन भी हुई। उस नोटिफिकेशन के अनुसार दोनों जगह के लिए 15-15 पोस्ट्स भी क्रिएट की गईं परंतु वहां आप स्टाफ से ज्वाईन करवाने में असमर्थ रहें। इस प्रकार की घोषणाएं करने के बारे में प्रदेश की जनता सब जानती है और आने वाले चुनाव में आपको वह सही जवाब देगी। यहां पर रोजगार देने की बात कही गई जिसमें पिछले और इस वर्ष यानी दोनों बार 30-30 हजार रोजगार देने की बात कही गई है। लेकिन राज्यपाल महोदय के अभिभाषण में गत तीन वर्षों में वर्तमान सरकार द्वारा दिए गए रोजगार के सही आंकड़ें सामने आए हैं जिसके अनुसार पिछले तीन वर्षों में मात्र 23,000 लोगों को रोजगार प्राप्त हुआ है। अगर इसको प्रति वर्ष के हिसाब से देखा जाए तो आपकी सरकार एक वर्ष में केवल 8000 रोजगार देने में समर्थ रही है। आज की डेट में प्रदेश का हर तीसरा स्नातक युवा बेरोजगार हो चुका है जोकि हम सबके लिए चिंता का विषय है। वर्तमान में सेवानिवृत्ति ज्यादा हो रही है और रोजगार कम मिल रहा है। मैं पिछले कल माननीय सदस्य श्री विनय कुमार का भाषण सुन रहा था जिसमें इन्होंने कहा था कि इनके चुनाव क्षेत्र में पड़ने वाली शिक्षा संस्थानों में लगभग 250 पोस्ट्स खाली हैं। इसी तरह से हमारे निर्वाचन क्षेत्र में भी विभिन्न शिक्षा संस्थानों में 511 पोस्ट्स खाली हैं। इस प्रकार की स्थिति वर्तमान सरकार की शिक्षा के प्रति अपनी सोच को दर्शाती है। ...व्यवधान... यहां पर जो कर्मचारियों के बारे में बात रखी गई थी तो उसके बारे में भी सरकार ने चुप्पी साधी हुई है। यहां पर ओ0पी0एस0 और आउटसोर्स का विषय हो या करूणामूलक आधार पर मिलने वाले रोजगार का विषय हो; सरकार किसी की बात नहीं सुन रही है। करूणामूलक आधार पर नौकरी पाने के लिए लोग पिछले एक साल से भूख हड़ताल

09.03.2022/1225/av/as/2

पर बैठे हुए हैं मगर उनको कोई नहीं सुन रहा है। यहां पर सरकार द्वारा एस0एम0सी0 की बात कही गई है। अभी तक तो उनके भविष्य पर तलवार लटकी हुई थी मगर अब जब सरकार का जाने का समय आ गया है तो आप 5वें वर्ष एस0एम0सी0 पॉलिसी लाने की बात

कर रहे हैं। हालांकि पूर्व मुख्य मंत्री श्री प्रेम कुमार धूमल के समय में इसमें कुछ नियुक्तियां हुई थीं। इसके अतिरिक्त, आने वाले वर्ष में आपके लोन पेमैंट की राशि दोगुनी हो जाएगी। पहले वह राशि 6.64 प्रतिशत थी जोकि अब बढ़कर 11 प्रतिशत तक पहुंच गई है। विकास के लिए आपके पास वर्तमान बजट में लगभग 43 प्रतिशत पैसा था जोकि अब घटकर 29 प्रतिशत रह जाएगा। यहां पर माननीय सदस्य श्री हर्षवर्धन चौहान, श्री आशीष बुटेल और श्री भवानी सिंह पठानिया ने इस बारे में सारे आंकड़ें पेश किए हैं। आंकड़ों के अनुसार इसी वित्तीय वर्ष में हिमाचल प्रदेश के हर व्यक्ति पर लगभग 96,000 रुपये लोन होगा जो अगले वित्तीय वर्ष 2022-23 में बढ़कर 1.08 लाख रुपये हो जाएगा। आपकी पर कैपिटा इंकम 2.01 लाख रुपये हैं। आप चाहे केंद्र सरकार द्वारा चलाई जा रही योजनाओं की बात करें; आपकी इस प्रकार की असमानता बढ़ती जा रही है। अगर भारतीय जनता पार्टी के पिछले 5 वर्षों के कार्यकाल को देखें तो देश में लगभग 23 करोड़ लोग बी0पी0एल0 में आए हैं जोकि चिंता का विषय है। इसके अतिरिक्त, सरकार द्वारा रिसोर्स मोबलाईजेशन के संदर्भ में कोई बात नहीं रखी गई है। यहां पर माननीय मुख्य मंत्री ने अपने बजट भाषण में कई शेर पढ़ें और सत्ता पक्ष व विपक्ष के बहुत सारे साथियों ने भी अपनी-अपनी बात रखते हुए कई शेर पढ़ें। मैं भी एक किसान-बागवान हूं इसलिए मैं भी अपनी बात एक शेर पढ़कर समाप्त करना चाहता हूं जोकि इस प्रकार है :-

फसल काटने का मतलब किसानों से पूछो,
पसीना बनकर बदन से लहू निकलता है।
ज़मीन और मुक़दर की एक फितरत है,
जो भी बोया है, वही हू-ब-हू निकलता है।।

09.03.2022/1225/av/as/3

आपकी सरकार बोने में कुछ कमी रख रही है और आपके समक्ष इसके परिणाम वर्ष 2022 में होने वाले विधान सभा चुनाव के दौरान आएंगे जब कांग्रेस पार्टी प्रचंड बहुमत के साथ जीतकर आएगी। अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे बोलने का समय दिया, आपका धन्यवाद।

समाप्त

अध्यक्ष : माननीय सदस्य, आपने निर्धारित समय के अंदर अपनी बात समाप्त की है इसलिए आपका भी धन्यवाद। अब इस चर्चा में माननीय सदस्य श्री अरुण कुमार भाग लेंगे।

श्री अरुण कुमार**टी सी द्वारा जारी**

09/03/2022/1230/टी0सी0वी0/डी0सी0/1

श्री अरुण कुमार : अध्यक्ष महोदय, 4 मार्च, 2022 को मुख्य मंत्री, श्री जय राम ठाकुर जी ने इस माननीय सदन में 5वां बजट रखा। इससे पहले भी चार बजट इस माननीय सदन में रखे हैं। प्रदेश के गरीब व वंचित वर्गों को प्रतीक्षा होती है कि आने वाले बजट में मुख्य मंत्री जी उनके लिए क्या-क्या देने वाले हैं? मैं विपक्ष के माननीय सदस्यों के लिए कुछ पंक्तियां कहना चाहता हूं ?

फ़र्क बहुत है तुम्हारी और मेरी राजनैतिक तालीम में,
तुमने परिवावाद से सीखा है और मैंने हालातों से।

अध्यक्ष महोदय, हमारे बुजुर्ग कहते थे कि सुबह का सपना सच होता है। आज सुबह मैंने सपना देखा कि विपक्ष से आधे सदस्य गायब हैं। आप लोग तो जागती आंखों से सपने देख रहे हैं। मैं तो यहां पर सीखने के लिए आया हूं और मुझे इन चार वर्षों में बहुत कुछ सीखने को मिला। मैंने मुख्य मंत्री जी के पांच बजटों का अध्ययन किया और पूर्व में रहे हमारे मुख्य मंत्री, स्वर्गीय श्री वीरभद्र सिंह जी के बजटों का भी अध्ययन किया। आज उनके आशीर्वाद से बहुत-सारे लोग इस माननीय सदन (पक्ष/विपक्ष) में हैं। उनकी लोकप्रियता के कदमों पर चलकर आज मुख्य मंत्री, श्री जय राम ठाकुर जी इस माननीय सदन में हैं। मुझे वह समय याद है, जब श्री जय राम ठाकुर जी प्रदेश के मुख्य मंत्री बनें और राजा वीरभद्र सिंह जी के घर गए तथा उन्होंने उनके साथ प्रदेश के हालातों के बारे में चर्चा की। मैंने पिछले बजट का अध्ययन किया और पाया कि विपक्ष हमेशा बजट को नकारात्मक दृष्टि से देखता है। आज प्रदेश के जो हालात है, उनके अनुसार आज बहुत सारी योजनाएं गरीब और वंचित

वर्ग के लिए शुरू की गईं हैं। विपरीत परिस्थितयां होते हुए भी महिलाओं, बुजुर्गों और विकलांगजनों व समाज के सभी वर्गों के लिए सामाजिक सुरक्षा पेंशन की आयु सीमा 60 वर्ष की है। अगर आप आंकड़ों पर जाएंगे तो आपको पता चलेगा कि कितना अमाउंट बढ़ाया है। हर वह वर्ग जो इस बजट की प्रतीक्षा करता है चाहे वह कर्मचारी वर्ग है, चाहे वह हमारे बुजुर्ग हैं, चाहे पंयाचती राज संस्थाओं में प्रधान, उपप्रधान या पंच हैं, सभी हमारी तरह ही अपने-अपने क्षेत्र में सेवा देते हैं। राजा वीरभद्र सिंह जी के समय में आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं

09/03/2022/1230/टी0सी0वी0/डी0सी0/1

को मु0 2600 रुपये मिलता था। इन 5 वर्षों में मुख्य मंत्री जी ने उनका मानदेय मु0 9000 रुपये किया है। पिछले दो सालों में हिमाचल प्रदेश ही नहीं पूरा देश व दुनिया कोरोना वायरस की चपेट में आई है। ऐसे समय में हम रिसोर्सिज कहां से पैदा करेंगे और प्रदेश को कैसे आर्थिक आधार पर मजबूत करेंगे? क्योंकि हिमाचल प्रदेश एक छोटा-सा प्रदेश है। इस प्रदेश के अंदर 70 प्रतिशत जंगल हैं।

एन0एस0 द्वारा जारी .....

09-03-2022/1235/NS/DC/1

श्री अरुण कुमार .....जारी

हमारी अर्थव्यवस्था कहां से होगी? कल श्री भवानी जी यहां पर बता रहे थे तो सुन कर अच्छा लगा क्योंकि इन्होंने कंपनी में एम0डी0 के तौर पर काम किया है। इन्होंने यहां पर बताया कि उद्योगपति और बिजनसमैन उसी समय काम करता है। अगर इंडस्ट्री घाटे में चल रही हो तो वह मैन पॉवर कम कर देगा। उस विषय को श्री रविन्द्र कुमार जी ने कंपाइल करके बताया। अध्यक्ष महोदय, सत्ता और राजनीति में ऐसा नहीं होता है। हम जिस काम के लिए इस सदन में बैठे हैं यहां पर ऐसा नहीं कर सकते हैं चाहे साधन हों या न हों। हमें उन वर्गों के लिए प्रयास करने हैं और ये करने ही पड़ेंगे। जो राजनीतिक हालात बनते जा रहे हैं और ये हालात पूरे देश के अंदर बने हुए हैं न कि हिमाचल प्रदेश में बने हुए

हैं । लोगों ने बहुत सोच समझ कर हमें इस सदन में भेजा है और हम जिम्मेदार व्यक्ति हैं। मुझे इस सदन में आने का पहली बार सौभाग्य प्राप्त हुआ है। हमें यह सुनिश्चित करना चाहिए कि हम ऐसा कोई काम न करें जिससे कल प्रदेश को और आने वाली पीढ़ी को संकट पैदा हो। मुख्य मंत्री सभी का काम करना चाहते हैं। ये पहले मुख्य मंत्री हैं जो हर वर्ग की सुनते हैं और अपने अधिकारियों को आदेश करते हैं कि इनका समाधान करना है। मुख्य मंत्री जी ओ0पी0एस0 के बारे में सोच रहे हैं। अध्यक्ष महोदय, मुख्य मंत्री जी के पास हर वर्ग उम्मीद लेकर आता है। यहां तक कि विपक्ष के माननीय सदस्य भी मुख्य मंत्री जी के पास उम्मीद लेकर जाते हैं। हम लोगों को ऐसे मुख्य मंत्री सौभाग्य से प्राप्त हुए हैं। सारा प्रदेश इनके सरल स्वभाव के बारे में जानता है। इन्होंने हर व्यक्ति का काम करने की पूरी कोशिश की है और आगे भी करेंगे।

अध्यक्ष महोदय, यहां पर श्री मुकेश अग्निहोत्री जी , श्री जगत सिंह नेगी जी और श्री हर्षवर्धन चौहान जी ने जिस तरीके से इस बजट को बताया है तो यह बजट उस तरीके से नहीं है। आप ईमानदारी के साथ बताएं कि क्या आपके जो भी क्षेत्र हैं उनमें चार वर्षों के अंदर विकास नहीं हुआ? मैं आपको खुले मन से चैलेंज करता हूं। मैं यहां पहली बार चुन कर आया हूं लेकिन आप लोग इतने लंबे समय से राजनीति में हैं और आज इतना समय व्यतीत हो जाने के बाद भी गांवों में पानी, बिजली की व्यवस्था और सड़कें नहीं हैं। हमने इन सब विषयों पर काम किया है।

09-03-2022/1235/NS/DC/2

आपकी सरकार के समय में 60 वर्षो के अंदर 7 लाख नलकों के कनैक्शन लगे हैं और मुख्य मंत्री जी और जल शक्ति मंत्री के सहयोग से पूरे प्रदेश में नलकों के 8.35 लाख कनैक्शन्ज़ लगे हैं। अध्यक्ष महोदय, यहां पर पाइपों के बारे में कहा गया। मैं आपको कहना चाहूंगा कि पहले पाइपें बिछेंगी फिर नलके लगेंगे और उसके बाद पानी का प्रावधान होगा। पाइपें ऐसे ही नहीं डाली जा रही हैं। हमने भी एक वर्ष के अंदर चुनाव लड़ने हैं। अगर हम पानी पहुंचाएंगे तभी लोगों के पास जाएंगे। आप इसकी चिंता न करें। आपको मुख्य मंत्री जी और मंत्री जी का धन्यवाद करना चाहिए। मुझे पता है और मैं स्वयं चुनावों के दौरान श्री जी0 एस0 बाली जी के साथ 15 सालों तक रहा हूं। उनके पास जब चुनावों के दौरान लोग आते थे तो वे दो पाइपें उठा कर दे देते थे। आज गरीब लोगों को 25-30 पाइपें दी जा रहीं हैं। गरीब वर्ग इन पाइपों को देखता था और जिंदगी में सोच नहीं सकता था उन लोगों के

घरों तक पाइपें पहुंचेंगी। आज मुख्य मंत्री जी और मंत्री जी के आशीर्वाद से ये संभव हुआ है। पाइपों की फिटिंग का सारा मटीरियल सरकार ने मुहैया करवाया है। इस प्रकार के कई विकास के काम हो रहे हैं। कांग्रेस की सरकार ने 60 सालों में कोई काम नहीं किए हैं।

अध्यक्ष महोदय, यहां पर बेरोज़गारी की बात कही गई है। मैं इसके कुछ आंकड़ें यहां पर रखना चाहूंगा जोकि विभाग के माध्यम से आए हैं। वर्ष 2011-12 में रिसेशन 08.39 लाख थी और इसमें इंप्लॉयमैंट 11,620 दी गई।

श्री आर0 के0 एस0 द्वारा जारी।

09.03.2022/1240/बी.एस./एच0के0/-1

श्री अरुण कुमार जारी...

जो वर्ष 2012-13 था, उसमें 8,61,314 थी और हमारे समय में 8,82,269 है, जिसमें हमने 15-20 हजार नौकरियां दी हैं, इसके बावजूद कुछ नौकरियों के मामले कोर्ट में फंसे हैं। हम 30 हजार और लोगों को नौकरियां देने जा रहे है। आदरणीय वीरभद्र सिंह जी के समम के अंतिम बजट में आपने 150 करोड़ रुपए बेरोजगारी भत्ते के लिए रखे थे और उसमें कहा कि आप 1500 रुपए के हिसाब से बेरोजगारों को भत्ता देंगे। उस वक्त 12 लाख से ऊपर प्रदेश में बेरोजगार थे अगर अपनी घोषणा के हिसाब से आप पैसा देते तो आपको 84 करोड़ 85 लाख रुपया एक महीने में देना पड़ना। आप कहां पर लोगों को भ्रमित करते हैं। अगर आप 12 लाख बेरोजगारों को भत्ता देते तो 120 करोड़ रुपया एक महीने में चला जाना था। हमने इंवेस्टर मीट की उसके अन्दर जो ग्राउंड ब्रेकिंग हुई उसमें हमारे 703 एम0ओ0यू0 साइन हुए हैं और इसमें हमारे एक लाख 98 हजार नौजवानों को नौकरी मिलनी थी, आज आप सरकारी सैक्टर में इतना रोजगार नहीं दे सकते हैं। आप लोगों को गुमरा मत कीजिए। हमें हर हाल में प्राइवेट सैक्टर की तरफ जाना पड़ेगा। हमने ये सारे आंकड़े आदरणीय मुकेश जी को दे दिए हैं, आप इसे पढ़े कि आपके समय में क्या था। अभी समय की कमी है, क्योंकि आदरणीय मुख्य मंत्री जी ने आज विस्तारपूर्वक आपको सारी चीजें बतानी है। आप फिजूलखर्ची की बात करते हैं, आपने मुख्य मंत्री जी के बजट को सरकारी कार्यक्रम बताया है। मैं आपके कार्यकाल की बात करना चाहता हूं। आपकी जिला ऊना में दिनांक 25.6.2015 को रैली हुई, उसमें 501 बसें गईं, उसका साढ़े पांच करोड़ रुपए बना, दिल्ली में

आपकी बसें बईं, उसमें आपका दो लाख 56 हजार 614 रुपए बना, टोटल आपके 9,79,04,031 रुपए बने, जिसमें आपने कितने पैसे दिए? आठ करोड़ 50 हजार रुपया दिया और अभी तक आपने 12 लाख 54 हजार रुपया सरकार को देना था। आपने चैक दिया, कांग्रेस पार्टी चैक देती है और वह चैक आपका वाउंस हो जाता है। आप झूठा चैक सरकार को दे रहे हैं। मण्डी में 7 अक्तूबर, 2017 को आदरणीय राहुल जी आए थे, वे तो कोई केन्द्रीय मंत्री नहीं थे।

अध्यक्ष : माननीय सदस्य कृपया समाप्त करें।

09.03.2022/1240/बी.एस./एच0के0/-2

श्री अरुण कुमार : जिसमें 72,12,617 रुपए आपने देने थे, वह आपने नहीं दिए। अभी हाल ही मैं मुख्य मंत्री जी का धन्यवाद करना चाहूंगा कि इन्होंने वह पैसा जमा करवाया है।

चलो आज थोड़ा सा मुस्कुराया जाए,
बिना माचिस के कुछ लोगों को जलाया जाए॥

इस प्रदेश के अन्दर आज जो परिस्थितियां बनी हैं, उन परिस्थितियों के लिए कांग्रेस पार्टी पूरी तरह से जिम्मेवार है। आज अगर देश और प्रदेश में बेरोजगार रोजगार की तलाश में भटक रहा है तो वह आपकी वजह से है। आज आप उनकी चिंता कर रहे हैं। आप सबसे लम्बे समय तक सत्ता में रहे हैं। आपने इस देश को दोनों हाथों से नहीं लूटा होता तो प्रदेश की दशा कुछ और होती। मैं आपको मोटा-मोट आंकड़ा बताना चाहता हूं। आपने 6,99,92,4,000 करोड़ रुपए का घपला किया है, आपने मोटे-मोटे घपले किए हैं। मैं आपको ये दस्तावेज दे दूंगा और इसमें लिखा है कि कांग्रेस के किन-किन नेताओं ने घपले किए हैं।

श्री एन0 जी0 द्वारा जारी...

09-03-2022/1245/एच.के.-एन.जी. /1

श्री अरुण कुमार ..... जारी

आप के नेताओं ने लगभग 7 लाख करोड़ रुपये के घोटाले किए हैं।

अध्यक्ष : माननीय सदस्य अब वाइंडअप कर दीजिए। विपक्ष के माननीय सदस्य ने अच्छी शुरूआत करते हुए अपनी बात को केवल 15 मिनट में पूरा किया था। अभी बोलने वालों की लम्बी सूची है और माननीय मुख्य मंत्री जी ने 4.00 बजे इस चर्चा का उत्तर भी देना है। अब बहुत हो गया, अब वांइडअप कर दीजिए।

श्री अरुण कुमार : अध्यक्ष महोदय, मैं कहना चाहता हूं कि :-

औकात नहीं है आंख से आंख मिलाने की,
और बात करते हैं हमारा नाम मिटाने की।
समय गूंगा नहीं बस मौन है,
वक्त आने पर बता देगा, किसका कौन है।
ऐसा अब और नहीं होगा कि
वे दिल लगाकर हमारे दिलों से खेलते रहें,
हम सिर झूकाकर हर सित्तम को झेलते रहें।

मेरा विपक्ष के लोगों को कहना है कि आप लोग जितना मर्जी जुमलेबाजी की बातें करते रहें।

अध्यक्ष : माननीय सदस्य अब बहुत हो गया है। सभी के लिए समय निर्धारित है। यदि आप ज्यादा समय लेंगे तो विपक्ष के माननीय सदस्य भी ज्यादा समय देने की बात करेंगें। माननीय सदस्य आधा मिनट में अपनी बात वाइंडअप कर दीजिए।

09-03-2022/1245/एच.के.-एन.जी. /2

श्री अरुण कुमार : अध्यक्ष महोदय, मैं विपक्ष के लोगों के लिए बहुत सारे कागज़ लेकर आया था। यहां पर माननीय श्री मुकेश अग्निहोत्री जी ने बहुत सारी बातें की हैं। ...व्यवधान... मैं आपको दिखा रहा हूं कि (न्यूज़ कटिंग दिखाते हुए) यह वर्ष-2003 में आपके द्वारा किया गया कंडक्टर भर्ती घोटाला है। आप लोगों ने ऐसे बस अड्डे नीलाम कर दिए जिनसे एक करोड़ रुपये प्रति माह पैसा आता था और आपने उन्हें 40 लाख रुपये में नीलाम कर दिया। ...व्यवधान... माननीय सदस्य श्री रोहित ठाकुर जी आपके तो नेता भी इटली से आते हैं और सेब के पौधे भी इटली से आते थे। मुझे यदि बोलने के लिए पांच मिनट का समय और देंगे तो मैं सेब के ऊपर भी बता सकता हूं। प्रदेश में एंटी हेलनेट माननीय प्रो0 प्रेम कुमार धूमल जी लेकर आए थे। ...व्यवधान... मैंने बहुत स्टडी की है और मैं आप लोगों की हर बात का जवाब देने के लिए तैयार हूं। मैं जो भी बोलूंगा तथ्यों सहित बोलूंगा। मेरे जिले में कांगड़ा से लेकर बरोट तक का आलु चिप्स फैक्टरी में जाता है। लेकिन मैंने आपके नेता की आलु से सोना बनाने वाली बात सुनी तो मैं थोड़ा रुक गया कि अब चिप्स फैक्टरी में आलु क्यों भेजना, अब तो सोने के लिए भेजेंगे। ...व्यवधान... बजट के लिए तो आपको पूरी किताब दे दी है।

अध्यक्ष : माननीय सदस्य श्री अरुण कुमार जी कृपया अपनी बात आधे मिनट में समाप्त कीजिए।

श्री अरुण कुमार : अध्यक्ष महोदय, मैं विपक्ष के लोगों को एक अंतिम बात कहना चाहता हूं कि :-

कब्र पर बैठा हूं अब्र होकर,
जमीन भी मिली तो गज होकर,
ख्वाहिश तो थी आसमां होने की,
पर आसमां भी मिला तो सफेद कफन होकर।

09-03-2022/1245/एच.के.-एन.जी. /3

आप लोग जो जागते हुए स्वपन देख रहे हैं वे कभी भी पूरे नहीं होंगे। अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे बोलने का समय दिया और इस माननीय सदन में सभी ने मेरी बातें बहुत अच्छे तरीके से सुनी, मैं सभी का धन्यवाद करता हूं। इस प्रदेश की आर्थिक स्थिति को मजबूत करने के लिए यदि विपक्ष के लोग सुझाव देंगे तो अच्छा होगा। आप लोग इस बजट की प्रशंसा अपने दिल से तो कर रहे हैं लेकिन आप अपने मुख से भी इसकी प्रशंसा करेंगे तो बेहतर होगा। अध्यक्ष महोदय, मैं इस बजट का पूरी तरह से समर्थन करता हूं। धन्यवाद।

समाप्त/-

अध्यक्ष : अब इस चर्चा में माननीय सदस्य श्री इन्द्र दत्त लखनपाल जी भाग लेंगे।

श्री इन्द्र दत्त लखनपाल ....श्री जे.एस. द्वारा जारी.....

09.03.2022/1250/JS/YK/1

श्री इन्द्र दत्त लखनपाल (बड़सर): अध्यक्ष महोदय, वर्ष 2022-23 के लिए माननीय मुख्य मंत्री महोदय ने जो बजट अनुमान यहां पर प्रस्तुत किए, उसमें सामान्य चर्चा में बोलने के लिए मैं भी अपने आपको शामिल करता हूं। आपने बोलने का समय दिया, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।

अध्यक्ष महोदय, बजट सत्र पर काफी लम्बी चर्चा हो गई है। यह चर्चा 3-4 दिन से लगातार चली है। एक अनुमान था कि सत्ता पक्ष की ओर से जो बजट चुनावी वर्ष में प्रस्तुत होना है, वही देखने को मिलेगा। अगर देखा जाए तो इस बजट में कोई नया नहीं है। पिछले बजट में माननीय मुख्य मंत्री जी ने "नई राहें नई मंजिलें योजना" चलाई थी। उस सन्दर्भ में मैं यही कहना चाहूंगा कि सत्ता पक्ष के लोग नई मंजिलों की ओर बढ़े लेकिन वे राहों में भटक गए और वापिस वहीं पहुंच गए। उनको न कोई मंजिल मिली न कोई राह मिली। दूसरे, आज

अरुण कुमार जी बड़े जोर-जोर से बोल रहे थे, राष्ट्रीय और प्रादेशिक बात इन्होंने यहां पर कही। इस सन्दर्भ में मैं इतना ही कहना चाहूंगा किः-

सियासत इस कदर आवाम पे एहसान करती है,
पहले आंखें छीन लेती है, फिर चश्में बांटती है।

यह आप लोगों का काम है। मैं शायर तो नहीं हूं। माननीय मुख्य मंत्री महोदय ने पिछले चार वर्षों में बजट भाषणों में इतने शेर बोल दिए कि ये सदन चर्चा/परिचर्चा का सदन न होते हुए शेरो-शायरी की गोष्ठी हो गया। शेरो-शायरी से इस प्रदेश की जनता का भला होने वाला नहीं है। ये सारे शेर ही गाते रहेंगे, क्या करें जब खाने को नहीं मिलेगा,नौकरी नहीं मिलेगी तो शेर ही गुनगुनाएंगे।

माननीय अध्यक्ष जी, मैं यहां पर ज्यादा बात नहीं करूंगा क्योंकि समय भी कम है। बजट में आपने कुछ अच्छी चीजें दी हैं, उनका हम स्वागत करते हैं। विधायक निधि आपने बढ़ाई, उसके लिए धन्यवाद। लेकिन विधायक निधि आपने जिस रेशो से बढ़ाई है, आज मंहगाई कहां पर पहुंच गई है? हम सब लोग यहां पर विधायक हैं,

09.03.2022/1250/JS/YK/2

आप लोग भी विधायक हैं। हमारी जिम्मेदारियां भी जनता के प्रति बहुत होती हैं। आप देखिये पीछे कोविड काल में हमारा जो नुकसान हुआ, हमारी विधायक निधि जारी नहीं हुई और जो हमारे अधूरे काम पड़े हुए हैं, उन अधूरे कामों के लिए हम लोगों ने और आप लोगों ने पैसा आबंटित करना है, क्या वे काम अब पूरे हो जाएंगे? आपने एक वर्ष के अन्दर 2 करोड़ रुपये देने हैं। ज्यादा-से-ज्यादा चुनावी वर्ष में हमें दो किश्तें ही मिल पाएंगी। आप एकमुश्त में इस राशि को जारी कर दें। अप्रैल माह में सरकार घोषणा करें, अधिसूचना जारी करें कि जो भी विधायक निधि दी गई है वह अप्रैल में मिल जाएगी ताकि जो हमारे अधूरे काम पड़े हुए हैं, जिनको हमने पैसे दिए हुए हैं। कोई महिला मण्डलों के भवन है, कोई सामुदायिक भवन हैं, कोई शमशानघाट हैं, कोई अधूरी सड़कें पड़ी हुई हैं और ग्रामीण सड़कें हैं, उनके काम पूरे हो सकें। मैं समझता हूं कि यह कम-से-कम 3 करोड़ रुपये तक होना चाहिए था। जिस प्रकार से हमारे जो काम चले हुए हैं और जिस प्रकार से

अभी रूस और यूक्रेन का युद्ध चला हुआ है, उससे आप लोगों को तो बहाना हो गया कि अब तेल मंहगा हो जाएगा, मंहगाई हो जाएगी। अब तो सब कुछ ही मंहगा हो जाएगा। तब तो यह पैसा किसी भी काम नहीं आएगा। इस बारे में आपको गम्भीरता से चर्चा करनी चाहिए और इसको और ज्यादा बढ़ाए जाने की कोशिश की जानी चाहिए। अगर आप इसे 3 करोड़ नहीं करना चाहते तो कम-से-कम इसे ढाई करोड़ तक करें। दूसरे, आपने हमारी ऐच्छिक निधि बढ़ाई, उसके लिए भी हम आपको बधाई देते हैं और आपका धन्यवाद भी करते हैं। आपने 12 लाख रुपये किए, ये भी कम हैं। वैसे तो जितनी मर्ज़ी बढ़ाते जाओ इच्छा पूरी नहीं होती लेकिन व्यवहारिक समस्या क्या है? आपने देखा होगा और हम तो रोज़ ही देखते हैं कि इतने लोग बीमार हो रहे हैं, उनमें सबसे ज्यादा कैंसर के पेशैंट हैं। उनके उपचार में भारी-भरकम पैसा लगता है। कैंसर के किडनी के मरीज दिन-प्रतिदिन बढ़ते जा रहे हैं।

श्री एस.एस. द्वारा जारी----

09.03.2022/1255/SS-YK/1

श्री इन्द्र दत्त लखनपाल क्रमागत :

किसी को पैरालाइज हो रहा है। उनके अभिभावक जो गरीब होते हैं या उनके साथ परिवार के सदस्य होते हैं वे हमारे पास आते हैं तो हम उनको मात्र 10 हजार से 20 हजार रुपया दे पाते हैं। इसलिए मैं चाहता हूं कि हमारी ऐच्छिक निधि 20 लाख रुपये तक होनी चाहिए। इसमें और भी बहुत से काम समेटे जाते हैं। कोई मंदिर, खेल मैदान या व्यक्तिगत रिटेनिंग वॉल के लिए पैसा मांगता है तो वह पैसा कम पड़ता है।

अध्यक्ष महोदय, दूसरी जितनी भी सविधाएं आपने यहां पर दी हैं चाहे आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं, आशा वर्कर्ज, पंचायत चौकीदारों, जल शक्ति विभाग के अंदर पैरा फीटर्ज, पम्प ऑपरेटर, वॉटर कैरियर और वॉटर गार्ड इत्यादि की दीं; वे सुविधाएं नाममात्र हैं। अगर आप पूरा बजट देखें तो जो एलोकेशन आपने बजट की है उसमें सारा बजट आपने काट दिया है। हमारी स्कीमों के लिए बजट के अंदर जो पहले प्रावधान थे उनसे आपने

सारा पैसा काट करके इस तरफ को बढ़ा दिया। फिर आपने बजट में नया क्या किया? आपकी डबल इंजन की सरकार है इसलिए होना यह चाहिए था कि आप कोई स्पेशल बजट या पैकेज दिल्ली से लाते तब तो हम आपको मानते। जो आपने यहां पर बजट प्रस्तुत किया है उसमें आपने सारी स्कीमों में जहां हमें 1 लाख रुपया बजट मिलता था वहां 25 हजार रुपये दे दिए। जिस स्कीम के लिए 1 करोड़ रुपया मिलना चाहिए था वहां 25 लाख रुपये कर दिए। जहां 25 लाख रुपये मिलने थे वहां पर 5 लाख रुपये कर दिए। अगर आप इस सारे बजट को पढ़ेंगे तो आपको पता लगेगा कि जो आपने प्रावधान किए हैं वे कम हैं। जनता की वाहवाही लूटने के लिए जो आपने कुछ घोषणाएं की हैं उसमें एक तरफ आपने बजट बढ़ा दिया और दूसरी तरफ कम कर दिया है। बाकी इस बजट में कोई नई बात नहीं है। केन्द्र सरकार से आप क्या लेकर आ रहे हैं उसकी इसमें कोई चर्चा नहीं है। जल शक्ति मंत्री जी सामने बैठे हैं और अभी अरुण कुमार जी बड़े जोर से बोल रहे थे कि हमने 7 लाख नलके लगा दिए। आपको इसके लिए बधाई हो। लेकिन जब उन

09.03.2022/1255/SS-YK/2

नलकों में पानी आएगा तब हम आपसे बात करेंगे। उनमें पानी नहीं आएगा। नल विदाउट जल होगा। आपने जनता के साथ जो छल किया है उसका आपको नतीजा भुगतना पड़ेगा। अध्यक्ष महोदय, मेरे विधान सभा क्षेत्र में 52 पंचायतें और एक नगर पंचायत है तथा लगातार आप उसमें पाइपें बिछा रहे हैं। हम भी चाहते हैं कि पानी की लाइनें बिछनी चाहिएं, नलके लगने चाहिएं। आप बोल रहे हैं कि पहले 74 वर्षों में कुछ नहीं हुआ। 25 वर्ष आपकी सरकार को भी हो गए हैं। आप लोग तो हिमाचल प्रदेश को बनाना भी नहीं चाहते थे। आप इस बात को छोड़िए। आप लोग 'स्टेट हुड मारो ठूड' बोला करते थे। आप उस बात को याद करिए। जिस समय यह प्रदेश बना था उस समय क्या हालात थे उनके बारे में सबको पता है। आप (श्री अरुण कुमार) नए हैं इसलिए आपको इसके बारे में कुछ पता नहीं है। आप रटी-रटाई और सीखी-सिखाई बातें यहां पर बोलते हैं।

मंत्री महोदय, हमारे गांव में आज भी 5-5 और 6-6 दिन पानी नहीं आता है। हमारे विधान सभा क्षेत्र के अंदर 4 जे0ई0 नहीं हैं। वहां पर एक जे0ई0 6 महीने से ज्यादा समय नहीं काटता है। उसका क्या कारण है? 6 महीने के बाद जब जे0ई0 आएगा और पूरे इलाके में घूमेंगा तो उसे पता नहीं लगेगा कि लाइन कहां बिछ रही है, क्या करना है और क्या नहीं करना है। मैं यह नहीं कहता कि आपकी योजना बुरी है या आपकी मंशा बुरी है लेकिन धरातल पर क्या हो रहा है आप इसको चैक करिए। बहुत बुरे हाल हैं। भ्रष्टाचार पूरी चरमसीमा पर है। 5-5 लाख रुपये के काम 10-10 लाख रुपये में अवार्ड हो रहे हैं। आप ऑनलाइन टैंडरिंग करते हैं उसके अंदर पूलिंग हो रही है और तीन-चार चहेते ठेकेदारों को काम दिए जा रहे हैं

जारी श्रीमती के0एस0

09.03.2022/1300/KS/AS/1

श्री इंद्र दत्त लखनपाल जारी----

और गुणवत्ता के बारे में देखिए। जो उस लाइन की डिगिंग होनी चाहिए, वह नहीं हो रही है। कहीं पाइपें हवा में ही लटकाई जा रही हैं। आप इसके बारे में देखिए। अगर आपको पाइपें मिल गई हैं तो उनका दुरुपयोग मत करिए। जब 5-6 साल के बाद जब आपकी भण्डारण क्षमता बढ़ेगी, उनमें पानी आएगा तो वे टूट जाएंगी, उनमें जंग लग जाएगा, सड़ जाएंगी। हमारे क्षेत्र में ब्यास से जो पानी की स्कीम आ रही है, चार-पांच साल पहले उसकी पाइपें बिछ गईं, पानी की स्कीम बाद में शुरू हुई तो वे जगह-जगह से फट रही हैं, ब्लॉक हो गई हैं, कहीं उनमें पत्थर फंस गए हैं। इस प्रकार आप लाइनें बिछाने में जोर मत दें। पहले भण्डारण क्षमता बढ़ाएं, टैंक बनाए। आपकी स्टोरेज केपेसिटी ज्यादा होनी चाहिए। उसके बाद आप बिछाए, हमें कोई आपत्ति नहीं है लेकिन जो इसकी आड़ में, आप बोलते हैं कि हम 40-40 पाइपें दे रहे हैं, विभाग के पास जब आम व्यक्ति जाता है तो उसको कहा जाता है कि आपको सिर्फ 5 पाइपें मिलेंगी बाकी अपनी जेब से लाओ। इसी विधान सभा में इस

बारे में जब मैंने प्रश्न किया था, मुझे बताया गया था कि जितनी भी पाइपें लगेंगी, हम देंगे लेकिन आज भी नहीं मिल रही हैं। सिर्फ उनको मिल रही हैं जिनके बारे में टैलीफोन चला जाता है कि इस व्यक्ति को 30 पाइपें, 35 पाइपें दे दो तो यह आपका कैसा एडमिनिस्ट्रेशन है और किस प्रकार की आप लोगों को सुविधा दे रहे हैं, यह देखने वाली बात है। ...व्यवधान.... कूका जी, अभी भी लोग ऐसे ही घूम रहे हैं। अभी भी बंदरबांट ही हो रही है। ज्यादा श्रेय लेने की बात मत करें। जो सच्चाई है, मैं वही बता रहा हूं। अगर इसमें कोई कमी होगी तो मंत्री जी, आप मेरे विधान सभा क्षेत्र का दौरा कर लें। लेकिन मेरा यह निवेदन रहेगा कि आप वहां पर भेष बदलकर जाएं। फिर आपको सच्चाई का पता लगेगा। आज भी हमारे लोग टैंकरों से पानी भर रहे हैं और अब गर्मी आने वाली है। हमारी जो पहले 5-6 पंचायतों के लिए ब्यास की स्कीम बनी थी, उसमें पानी सूख गया है। ब्यास का प्रवाह बदल गया है। पानी नहीं आ रहा है। कहने का

09.03.2022/1300/KS/AS/2

मतलब यह है कि या तो आपके अधिकारी आपके पास सही तरीके से बात नहीं रखते या फिर आप लोग इसमें गम्भीर नहीं हैं।

अध्यक्ष महोदय, सड़कों के लिए एस.सी. कम्पोनेंट में जो पैसा मिलता था, जिस सड़क के लिए हमें 40 लाख रुपये चाहिए, वहां हमें 5 लाख रुपये दे रहे हैं। जिस सड़क के लिए 50 लाख रुपये चाहिए, वहां 50 हजार रुपये दे रहे हैं तो सड़कें कैसे बनेंगी?

स्वास्थ्य विभाग में हमारे ग्रामीण क्षेत्रों के हैल्थ सब सैंटर्ज़ में मेल व फीमेल हैल्थ वर्कर्ज़ नहीं हैं, ताले लगे हुए हैं। लगातार चार वर्षों से मुख्य मंत्री महोदय, मैंने आपके समक्ष भी यह बात रखी है कि हमारे जो आयुर्वेदिक संस्थान हैं, उनमें तीन संस्थान हमारी पूर्व सरकार के समय में खुले थे, अभी तक उनमें फंक्शनल पोस्टें ही नहीं हैं। न डॉक्टर की पोस्ट है, न फार्मासिस्ट की है और न अन्य पोस्टे हैं। ....व्यवधान... मुख्य मंत्री महोदय, यह तो कोई जवाब नहीं हुआ कि खोले क्यों थे? आप भी तो खोल रहे हैं तो कल को हम भी यही पूछेंगे

कि आपने खोले क्यों थे? यह तो कोई जवाब नहीं दिया आपने कि खोले क्यों थे? जब उनको खोल दिया तो क्या उनको चलाना सरकार की जिम्मेवारी नहीं है? ...व्यवधान... यह कोई जवाब नहीं है। यह जिम्मेवार सरकार का कोई जवाब है? आप क्या बात करते हैं। आपके समय में जो खुल रहे हैं क्या वहां पर सारी पोस्टें भर गई हैं? आप चुप रहिए। जब आप बोल रहे थे तो हमने बीच में कुछ नहीं बोला। हमने खोले थे तो उनको चलाइए। जब हमने उनके बारे में बात रखी तो उनको चला देना चाहिए था।

अध्यक्षः माननीय सदस्य, आधे मिनट में वाइंड अप करें।

श्री इन्द्र दत्त लखनपालः अध्यक्ष महोदय, सत्ता पक्ष की तरफ से माननीय सदस्य 20-20 मिनट बोल रहे हैं, मेरे तो अभी 15 मिनट भी नहीं हुए।

अध्यक्षः सभी ने समय का ध्यान रखा है। आप आधे मिनट में वाइंड अप करें।

09.03.2022/1300/KS/AS/3

श्री इन्द्र दत्त लखनपालः आप किसी भी विभाग में देख लीजिए हर जगह अफरा-तफरी पड़ी हुई है। आप पी.डब्ल्यू.डी. विभाग में देखिए। पिछले चार वर्षों से मैं लगातार जो हमारे क्षेत्र में रैस्टहाउसिज़ बने हुए हैं, उनके जीर्णोद्धार की बात कर रहा हूं। विधायक प्राथमिकता में हम उसके बारे में लिख कर भेजते हैं लेकिन पता नहीं वह कहां गुम हो जाते हैं? रैस्ट हाउसों की इतनी बूरी हालत है कि आज तक वहां फर्निचर चेंज नहीं हो रहा है। वहां पर सोने लायक स्थिति नहीं है। हम यह नहीं समझ रहे हैं कि आप योजना किस प्रकार से बनाते हैं, किस प्रकार से बजट एलोकेशन करते हैं? विधायक जो प्लानिंग की मीटिंग में आपके सामने चर्चा करते हैं, विधायक प्राथमिकता में लिखित में देते हैं, उसके ऊपर तो काम ही नहीं होता।

श्रीमती अ0व0 द्वारा जारी---

09.03.2022/1305/av/as/1

श्री इन्द्र दत्त लखनपाल-----जारी

आपने मेरे निर्वाचन क्षेत्र में 6 रूट्स पास किए हुए हैं मगर आपकी सारी बसिज बंद हैं। उन रूट्स पर एक भी बस नहीं चल रही है। उन रूट्स पर दो दिन बस चलाई जाती है और तीसरे दिन बोल दिया जाता है कि पैसा नहीं है तथा आर0एम0 द्वारा उस बस को बंद कर दिया जाता है। ...व्यवधान... माननीय मुख्य मंत्री जी, आप मेरे निर्वाचन क्षेत्र से संबंधित समस्याओं पर गंभीरता से विचार करें। वैसे तो आपका समय निकल ही गया है क्योंकि 2-3 महीनें आपने नगर निगम शिमला के चुनाव में लगा देने। उसके बाद विधान सभा चुनाव की आचार संहिता लग जाएगी तो इस प्रकार से आपने जितनी भी घोषणाएं की हैं; ये सारी-की-सारी बजट बुक में ही रह जाएंगी। इसलिए मैं यह कहना चाहता हूं कि आपका यह बजट दिशाहीन है। आपने लोगों की वाहवाही लूटने के लिए इसमें जो थोड़ी-बहुत बढ़ोतरियां की हैं; वे नाकाफी हैं। प्रदेश की जनता आपसे खुश नहीं है, आपने चाहे आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं का मानदेय बढ़ाया या आशा वर्कर्ज का बढ़ाया; इसमें सबका यही कहना है कि हमें 400-500 रुपये की बढ़ोतरी नहीं चाहिए बल्कि सरकार की नियमित नौकरी चाहिए। आपने बजट में वोकेशनल टीचर्स के बारे में तो कोई बात ही नहीं कही है। ...घंटी... मैं इस बजट का समर्थन करने में असमर्थ हूं क्योंकि इसमें प्रदेश की जनता के लिए कुछ भी नहीं दिया गया है। अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे बोलने का समय दिया, आपका धन्यवाद।

09.03.2022/1305/av/as/2

अध्यक्ष : माननीय जल शक्ति मंत्री, आप कुछ कहना चाहते हैं?

जल शक्ति मंत्री : अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने अपनी बात में यह कहा है कि इनके चुनाव क्षेत्र में कोई काम नहीं हो रहे हैं। मैं इनको आश्वस्त करना चाहता हूं कि मैं निश्चित तौर पर आपके निर्वाचन क्षेत्र में आऊंगा तथा वहां पर जितनी भी स्कीम्ज चलाई गई हैं

उनका निरीक्षण करूंगा और वहां पर आम लोगों से मिलूंगा। वहां पर जितनी भी स्कीम्ज चलाई गई हैं उनका निरीक्षण करने के साथ-साथ मैं वहां की जनता को यह भी बताऊंगा कि आपके यहां ये-ये काम किए जा रहे हैं। अध्यक्ष महोदय, इनके निर्वाचन क्षेत्र में एक बहुत बड़ी स्कीम बनकर उद्घाटन के लिए तैयार है। हम उसके लिए माननीय मुख्य मंत्री से समय लेंगे और उसका उद्घाटन करवाएंगे। इसके अतिरिक्त, वहां के लिए हमने ए0डी0बी0 से एक बड़ी योजना स्वीकृत करवाई हुई है और उसी दिन माननीय मुख्य मंत्री के कर-कमलों द्वारा उसका भी शिलान्यास करवाएंगे।

समाप्त

अध्यक्ष : माननीय सदस्य श्री अरुण कुमार, बोलिए। ...व्यवधान... आप बोलिए।

श्री अरुण कुमार (नगरोटा) : अध्यक्ष महोदय, मैं यह कहना चाहूंगा कि इस बजट में मेरे विपक्ष के साथियों को अच्छी किस्म के चश्में देने का भी प्रावधान किया जाए।

अध्यक्ष : अब इस माननीय सदन की बैठक दोपहर के भोजनावकाश के लिए 02.00 बजे (अपराह्न) तक स्थगित की जाती है।

09/03/2022/1415/टी0सी0वी0/डी0सी0/1

(माननीय सदन की बैठक दोपहर के भोजनोपरान्त 2.15 बज़े अपराह्न पुनः आरम्भ हुई)

अध्यक्ष : अब इस चर्चा में माननीय सदस्य, श्री रमेश चंद ध्वाला जी भाग लेंगे।

श्री रमेश चंद ध्वाला (ज्वालामुखी) : अध्यक्ष महोदय, मुख्य मंत्री जी द्वारा प्रस्तुत बजट का आकार मु0 51,365 करोड़ रुपये प्रस्तावित है। वर्ष 2021-22 के दौरान प्रदेश की अर्थव्यवस्था में 8.3 प्रतिशत की वृद्धि होने का अनुमान है। वर्ष 2021-22 के दौरान सकल घरेलू उत्पाद (जी0डी0पी0) 9.2 प्रतिशत रहने का अनुमान है। वर्ष 2021-22 में प्रति व्यक्ति आए मु0 2,01,854 रुपये आंकी गई है जोकि राष्ट्रीय स्तर पर अनुमानित प्रति व्यक्ति आय से मु0 51,528 रुपये अधिक है। मुख्य मंत्री जी ने लोगों की दुःखती नब्ज पकड़ी है और वे

लोगों की समस्याओं के प्रति पहले से ही सजग व संवेदनशील हैं। इसके लिए मैं इनका धन्यवाद करता हूं। प्रदेश में जब आपदा आती है तो सभी का नैतिक कर्त्तव्य बनता है कि हम उसका मुकाबला इकट्ठे होकर करें। आप सभी माननीय सदस्यों ने भी अपनी सैलरी में से 30 प्रतिशत राशि इस कोरोना बीमारी से निपटने के लिए एक साल तक दी है। इसके लिए आपका धन्यवाद। बजट भाषण पर चर्चा में आप सभी ने विभिन्न विषयों पर इस माननीय सदन में अपने विचार रखें। हमारे प्रधान मंत्री जी ने यूक्रेन से 18,000 बच्चों को वापिस लाकर बहुत बड़ा काम किया है। ...व्यवधान... ऐसा नहीं है, छह घंटे युद्ध बन्द करके, बसें लगा करके उन बच्चों को हैलीपेड से घर-घर पहुंचाया है। मैडम जी, पाकिस्तान के बच्चे भी हिन्दुस्तान के झण्डे तले हिन्दुस्तान में आए हैं। आप न माने तो हम उसमें कुछ नहीं कर सकते। लेकिन अपने-अपने लीडर पर विश्वास होता है।

एन0एस0 द्वारा जारी ...

09-03-2022/1420/NS/DC/1

श्री रमेश चंद ध्वाला.....जारी

आज पूरे विश्व में हमारे यशस्वी प्रधान मंत्री जी की प्रशंसा हो रही है। ये आपके भी प्रधान मंत्री हैं लेकिन आप मानते नहीं हैं। आप उसको मानते हैं जिसने राजस्थान में घोषणा की थी कि मैं सभी का कर्ज़ माफ़ कर दूंगा। क्या आपने आज तक ये कर्ज़ माफ़ किए? अध्यक्ष महोदय, 40 सालों से भूतपूर्व सैनिकों की पेंशन का 'वन रेंक, वन पेंशन' मुद्दा कई वर्षों से चला हुआ था। जो भूतपूर्व सैनिक 2900 रुपये पेंशन लेते थे वे आज 29,000 रुपये पेंशन ले रहे हैं। डॉ0 मनमोहन सिंह जी ने जो किया है उस बारे में आप सभी जानते हैं कि आपको 15 सालों में मेचिंग ग्रांट नहीं मिली। इसे भी हमारी सरकार ने किया है। आपको 15 सालों तक 60:40, 80:20 और 70:30 की रेशो से राशि नहीं मिलती थी और कोई विकास नहीं होता था। माननीय प्रधान मंत्री जी ने हमारे पहाड़ी प्रदेशों को 90:10 की रेशो से मेचिंग ग्रांट दी है। आपने जो घोषणाएं की हैं उसके लिए मैं आपको एक चुटकुला सुनाने जा रहा हूं। एक बड़ा अमीर आदमी था और एक गरीब आदमी था। किसी ज्योतिषी ने उसे चक्र में डाल दिया कि आप समुद्र के किनारे जाओ और वहां जा करके शंखनाद की पूजा कीजिए। वह

हरिद्वार के किनारे चला गया और वहां पर बहुत दिनों तक शंखनाद की पूजा करता रहा। बहुत दिनों के बाद शंखनाद जी प्रचंड हुए और बोले, मांगों क्या चाहते हो? तब उसने बोला कि मुझे पैसे चाहिए। शंखनाद ने कहा कि कितने पैसे चाहिए? तब उसने कहा कि मुझे चार लाख रुपये चाहिए। शंखनाद ने कहा कि और मांगों तब उसने कहा कि आठ लाख रुपये। इस पर शंखनाद ने कहा कि और मांगों और उसने 10 लाख बोला। तब शंखनाद ने कहा कि और मांगो तब उसने 15 लाख रुपये बोल दिए। तब उसने कहा शंखनाद जी आप देंगे भी कि आश्वासन ही करते रहेंगे। तब शंखनाद ने बोला कि मैं तो गप्पोड़ शंख हूं। अध्यक्ष महोदय, ये भी गप्पोड़ शंख थे। आपने कुछ नहीं दिया। इसलिए मैं यह कहना चाहूंगा कि सूखे दरख्त का पक्षी भी परित्याग करके चले जाते हैं। आज आपके पास क्या है? जिसके लिए आप यहां पर हाय-तौबा कर रहे हैं यह सत्ता का नशा है और यह नशा शराब के नशे से भी ज्यादा होता है। आपको अब सत्ता का नशा लगा है। इसलिए आप उथल-पुथल कर रहे हैं। मैं आपसे इतना ही निवेदन करना चाहूंगा कि आप ठीक को ठीक कहें और गलत को गलत कहें। अध्यक्ष महोदय, इनकी पार्टी लीडरलैस पार्टी है इसलिए आपके साथ कौन चलेगा? जब श्रीमती इन्दिरा गांधी का देहांत हुआ था तब श्री राजीव गांधी ने 486

09-03-2022/1420/NS/DC/2

एम0पीज0 के साथ सरकार बनाई थी। आज 44 एम0पी0 रह गए हैं। इसका क्या कारण है, कोई-न-कोई कमी तो होगी? ...व्यवधान... हम दो थे और अब 303 एम0पी0 बन गए हैं। आप घट रहें हैं और हम बढ़ रहे हैं। अध्यक्ष महोदय, ये इनके लीडरों की कमज़ोरी है। ...व्यवधान... मुख्य मंत्री जी ने आपकी दुखती नब्ज़ पकड़ी है। आप बताओ जिसको बीमारी के इलाज के लिए 5 लाख रुपये मिलेगा वह आपके साथ क्यों चलेगा?

श्री आर0 के0 एस0 द्वारा जारी।

09.03.2022/1425/RKS/एचके-1

श्री रमेश चंद ध्वाला...जारी

प्रधानमंत्री किसान सम्मान योजना के तहत किसानों को 6 हजार रुपये मिल रहे हैं। क्या किसान इस चीज को भी भूल जाएंगे?...व्यवधान... श्री जगत सिंह नेगी जी मेरे परम मित्र हैं। मेरे कहने का मतलब यह है कि सरकार द्वारा जो सुविधा उपलब्ध करवाई जा रही है

उसके लिए लोग हमें कभी नहीं भूल सकते। जब कोई गृहिणी अपने गैस चूल्हे को जलाएगी तो वह जरूर याद करेगी कि यह सौगात हमें माननीय प्रधान मंत्री और माननीय मुख्य मंत्री द्वारा प्रदान की गई है। अगर आपकी दृष्टि सही काम न करे तो हम कुछ नहीं कह सकते। लेकिन हमेशा सही को सही और गलत को गलत कहना चाहिए। अगर कोई कमियां होंगी तो उन्हें हम आपके सहयोग से दूर करने का प्रयास करेंगे। आप कह रहे हैं कि बेरोज़गारी का आंकड़ा 16 लाख के पार हो गया है। क्या आप 16 लाख लोगों को एक साथ रोज़गार दे सकते हैं? इसके लिए हमें अपने रिसोर्स जनरेट करने होंगे। हमें अपने राजस्व को बढ़ाने के लिए संसाधन तलाशने होंगे। आज प्रदेश को भारी कर्ज का बोझ उठाना पड़ रहा है। हमें इसकी चिंता करने की आवश्यकता है। माननीय वन मंत्री जी ने खैर के पेड़ों को काटने की अनुमति का आश्वासन दिया है। अगर हमें खैर के पेड़ों को काटने की अनुमति मिल जाती है तो इससे भी हम अपना आधा कर्ज़ चुका सकते हैं। हम अपने संसाधनों को जनरेट करके प्रदेश की आर्थिकी को सुदृढ़ कर सकते हैं। मैंने स्वर्गीय श्री वीरभद्र सिंह को कहा था कि मैं आपको समर्थन तो दे दूं लेकिन यह सरकार कैसे चलेगी? जगह-जगह मजदूर व कर्मचारी नारे लगा रहे हैं। उन्होंने कहा कि आप इसकी चिंता मत कीजिए, मैं आय के साधन बढ़ाने के लिए देवदार के पेड़ो को काटने की अनुमति शुरू कर दूंगा। इस बजट में माननीय मुख्य मंत्री जी ने कमजोर वर्ग को छूआ है। विभिन्न श्रेणियों के डेढ़ लाख कर्मचारियों का मानदेय बढ़ाया गया है। क्या यह भी झूठ है? बजट तो अपने घर के लिए भी बनाया जाता है। एक प्लान बजट होता है और दूसरा नॉन प्लान। नॉन प्लान बजट वह होता है जब किसी रिश्तेदार की शादी आ जाए और उसमें हमें पैसा खर्च करना पड़ जाए। जो बजट हमने

09.03.2022/1425/RKS/एचके-2

अपने बेटे की शादी और मकान के लिए बनाया था उसके अलावा हमें इस शादी के लिए और पैसों का इंतजाम करना पड़ेगा। यह हमारे घर का बजट होता है। इसी तरह इस बजट में भी कई प्रकार के प्रावधान किए गए हैं। नौजवानों को सही मार्ग दर्शन देना हमारा कर्त्तव्य है।

अध्यक्ष : माननीय सदस्य कृपया समय का ध्यान रखें।

श्री रमेश चंद ध्वाला : अध्यक्ष महोदय, मैं इनको एक शेर सुनाना चाहूंगाः-

दर्द दिल में हो तो दवा दीजिए,
दिल ही जब दर्द हो तो क्या कीजिए।

अगर आपके दिल में खोट है तो हम कुछ नहीं कर सकते। हमें बच्चों को सही मार्ग दर्शन देना होगा। अगर हम सड़कों के किनारे फलदार पेड़ लगवा दें तो इससे भी हमारे बच्चों को रोजगार के साधन खुलेंगे।

श्री बी.एस. द्वारा... जारी

09.03.2022/1430/बी.एस./एच0के0/-1

श्री रमेश चंद ध्वाला जारी...

अगर हम इन सड़कों के किनारे प्लांट लगा दें, फलदार पेड़ लगा दें, पहले भी वे पेड़ होते थे। अगर इनमें बच्चों का 50-50 हो जाए, तो वे मान जाएंगे। मैं कहना चाहता हूं कि बेरोजगारी की आने वाले समय में बहुत भंयकर आग होगी। वे हमारी ओर देख रहे हैं कि हमें कौन नौकरी देंगे? इसलिए युवाओं को कुछ काम धंधा करना ही पड़ेगा। हमारा कृषि क्षेत्र सिकुड़ता जा रहा है, आज पशु सड़कों पर घूम रहे हैं, हमारी आर्थिकी इनसे चलती थी। एक लड़के से मैंने पूछा तो उसने बताया कि उसने 15 भैंसे एक गाय और पांच उनके बच्चें पाले हैं। उसने दो सालों में 16 लाख रुपए कमाया है। क्या हम बच्चों को ऐसी शिक्षा नहीं दे सकते? हमारा भी यह दायित्व बनता है कि बच्चों का मार्गदर्शन अवश्य करें, चाहे यह कृषि क्षेत्र में हो, चाहे उद्यान क्षेत्र में हो। मैं ठाकुर साहब का धन्यवाद करना चाहता हूं कि मेरे वहां भी इन्होंने शिवा प्रोजैक्ट लगाया है। इस प्रोजैक्ट के द्वारा जो भी पौधे लगाए गए हैं वे सभी सरवाइव कर गए हैं और वे सभी फलदार पौधें हैं। वहां उनकी ड्रिप इरिगेशन के द्वारा पानी दिया जा रहा है। यदि हम आज बच्चों को रोजगार नहीं दिला पाए तो वे दिन दूर नहीं जब हम पेंशन ले करके जाएंगे तो वे रास्ते में खड़े हो जाएंगे और कहेंगे कि

निकालों जेब में कितने पैसे हैं? यह मुद्दा बड़ा गंभीर है, इसपर हम सभी को बैठ करके चर्चा करनी चाहिए कि इस समस्या का हल कैसे हो सकता है।

अध्यक्ष : माननीय सदस्य कृपया समाप्त करें, जो चर्चा के लिए निर्धारित समय है, वह समाप्त हो चुका है।

श्री रमेश चंद ध्वाला :

मरहम लगा सको तो किसी गरीब के जख्मों में लगा देना,
हकीम बहुत है बाजार में, अमीरों के इलाज के लिए॥

लोकतंत्र लोंगो की राय से चलता है, इसमे किन्तु, प्रन्तु जरूरी है। मैं अंत में एक और शेर अर्ज कर रहा हूं।

09.03.2022/1430/बी.एस./एच0के0/-2

भला बुरा नहीं होता है, कोई,
रूप से नजर का भेद ही गुण दोष को बताता है॥
कोई कमल की कली देखता है कीचड़ में,
और किसी को चांद में भी दाग नजर आता है॥

इस बजट में किसी भी वर्ग को नहीं छोड़ा गया है, जिनके लिए माननीय मुख्य मंत्री जी ने प्रयास नहीं किया है। यह ठीक है कि यह वन विभाग, उद्यान विभाग, कृषि विभागों में रोजगार बढ़ाने होंगे। परंतु यहां से कहा जाता है कि हम आते ही आपको नौकरियां दें देंगे। क्या यह संभव है? माननीय अध्यक्ष जी आपने समय दिया आपका बहुत-बहुत धन्यवाद॥

09.03.2022/1430/बी.एस./एच0के0/-3

अध्यक्ष : अब माननीय सदस्या श्रीमती आशा कुमारी जी चर्चा में भाग लेंगी।

श्रीमती आशा कुमारी, डलहौजी : अध्यक्ष महोदय, 18 मिनट आदरणीय ध्वाला जी ने बोला है, कल अन्तर्राट्रीय दिवस था, मैं कल निजी कारणों से हाउस में नहीं थी। मुझे उम्मीद है कि आप मुझे 18 मिनट तक तो नहीं रोकेंगे। मैं यहां पर अकेली महिला हूं।

श्री एन0 जी0 द्वारा जारी...

09-03-2022/1435/वाई.के.-एन.जी. /1

श्रीमती आशा कुमारी ..... जारी

सत्तापक्ष की ओर तो मेरी बहुत बहनें बैठी हैं। अध्यक्ष महोदय, वित्तीय वर्ष 2022-2023 के बजट अनुमानों को माननीय मुख्य मंत्री जी ने दिनांक 04-03-2022 को इस माननीय सदन में प्रस्तुत किया था और आज मैं उसकी चर्चा में भाग लेने के लिए खड़ी हुई हूं। आपने मुझे बोलने का समय दिया आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। अध्यक्ष महोदय, इस बजट अनुमान के मुताबिक revenue expenditure is expected to be 40,278 crores, revenue receipts 36,375 crores, revenue deficit जो बजट एस्टिमेट में हैं i.e. 3,903 crores and fiscal deficit 9,602 करोड़ रुपये हैं। यानि की it is expected to be 4.98 of the GSDP.

अध्यक्ष महोदय, माननीय मुख्य मंत्री जी ने जो बजट भाषण पढ़ा है उसमें उन्होंने पैरा नम्बर-213 में कहा है कि भारत सरकार ने सभी राज्यों को Fiscal Responsibility and Budget Management (FRBM) Act में संशोधन करके GDP के 3 प्रतिशत से अधिक ऋण लेने की अनुमति प्रदान की है। अध्यक्ष महोदय, इस माननीय सदन में पिछली बार FRBM Act को संशोधन करने के लिए प्रस्ताव लाया गया था और हमने उसका विरोध किया था। हमने उस वक्त भी कहा था कि आगे की borrowings के लिए यह बुनियाद रखी जा रही है। आप पिछले साल पहले से ही 4.05 प्रतिशत का fiscal deficit कर चुके हैं जबकि आपको अनुमति केवल 3 प्रतिशत की है। उसके बाद अब आप प्रस्ताव लेकर आ रहे हैं कि FRBM Act को संशोधन करना है। माननीय मुख्य मंत्री जी के भाषण में यह पेज नम्बर-60 के पैरा नम्बर-213 पर लिखा हुआ है। आपने borrowing पहले कर ली है और

अब आप हाऊस में लेकर आ रहे हो कि हमारी borrowings पर अपना ठप्पा लगा दीजिए। आप इसे पास भी कर देंगे क्यों कि आपकी सदन में brute majority है।

09-03-2022/1435/वाई.के.-एन.जी. /2

आप मुझे यह बताइए कि your borrowings is expected to be higher. Why did you not bring this Act before the Budget? Why you are brining it after the Budget? And in the Budget you have a projection of 4.98 per cent and in subsequent years, it will go up to 7.5 per cent. अध्यक्ष महोदय, मैं सारे कागज़ात निकाल कर फिर से यहां पर रखूं तो उसका कोई सैंस नहीं बनता है। Budget brief in the Budget documents में आप देखेंगे तो तीन साल का fiscal plan होता है। In that it is projected to be 7.5 per cent. अभी माननीय श्री मुकेश अग्निहोत्री जी ने भी कहा कि इससे आप की borrowings कहां पर जाएंगी। आपने यहां पर लगभग 63,000 करोड़ रुपये का फिगर दिया है। यहां पर आपने without giving the revised estimate by saying that we will remain within the FRBM और यह नहीं कहा है कि FRBM का क्या होगा? क्योंकि आप अभी संशोधन लाने वाले हैं। आप संशोधन लाएंगे और borrowings को बढ़ाने का काम करेंगे। निश्चित तौर पर इस current Financial Year में 69 से 70 हज़ार करोड़ रुपये कर्ज जाएगा। जब आप सरकार छोड़ेंगे और जनता आपसे छुड़वाएगी तब आप यहां जो छोड़ कर जाएंगे percentage it will exceed और उसके बाद आप फिर से FRBM में संशोधन लेकर आएंगे। क्या आप हर बार ऐसा ही करेंगे? आप खर्चा कर लेते हैं, आप borrowings कर लेते हैं और फिर माननीय सदन को कहते हैं कि इस पर ठप्पा लगा दो। This is bad fiscal management. And I am sorry to say, it is not in the interest of the State. Question is not of a Congress or BJP, question is of Himachal Pradesh. हिमाचल प्रदेश के लिए यह बहुत बुरा ट्रेंड है। मैं नहीं समझती की इसे इस प्रकार से करना चाहिए। आपने इस बजट में कैपिटल आऊटले 20 per cent decrease कर दिया। आप इसे लगभग 7 हज़ार करोड़ रुपये कम करके 5,647 करोड़ पर ले आए।

इससे प्रदेश में स्कूल, अस्पताल, सड़कें बननी हैं और जितने भी विकासात्मक कार्य होने हैं वे सभी इसी पैसे से किया जाना है और आपने इसे 20 per cent decrease कर दिया, यह मैं नहीं बोल रही हूं,

09-03-2022/1435/वाई.के.-एन.जी. /3

आपका डॉक्यूमेंट बोल रहा है। आप लोगों ने इसे पढ़ा ही नहीं हैं। माननीय सदस्य श्री अरुण कुमार जी ने तो बिलकुल भी नहीं पढ़ा है और इन्हें जो पकड़ा दिया गया उसे ये यहां पर लहराने लग पड़े। राज्यपाल महोदय के अभिभाषण की चर्चा के समय भी ये इसी प्रकार कर रहे थे और आज भी यही कर रहे हैं। यह हिमाचल प्रदेश की आर्थिकी का सवाल है। आप आर्थिकी की बात करते हैं today the dollar is Rs. 77, highest ever in the history of the Country, Rs. 77 to a dollar,

श्री जे.एस. द्वारा जारी.....

09.03.2022/1440/JS/YK/1

श्रीमती आशा कुमारीः-----जारी------

बैरल जो अक्रूड ऑयल का आज 135 डॉलर पहूंच गया है। आप क्या सोचते हैं कि उसका हम पर असर नहीं होगा। उसका एक ही तरीका है कि आप लोग अपने यशस्वी प्रधान मंत्री को कहें कि जो ऑयल रिजर्व, उसको रिलीज किया जाए। Please, don't disturb me. अध्यक्ष महोदय, मेरा इनसे निवेदन है कि ये गवर्नमैंट ऑफ इण्डिया को सजैशन दें कि जो ऑयल रिजर्व में है, उसको अभी रिलीज किया जाए क्योंकि जिस तरह से अमेरिका ने सैक्शन्ज लगा दी हैं, जिससे ऑयल की कीमतें और ऊपर जाएंगी। ये जो पेट्रोल और डीजल की कीमतें इसलिए नहीं बढ़ी क्योंकि पांच राज्यों के चुनाव थे और जो चार सीटें हम हिमाचल प्रदेश में जीत कर लाए हैं उसका असर हुआ। उसकी वज़ह से पेट्रोल-डीजल की कीमतें कम हुई। मगर यह पता नहीं है कि अगले पांच-सात दिनों में क्या होने वाला है? इसका पूरे देश में असर होता है। मण्डी पार्लियामैंट से 4 लाख कवर करके हम जीत

करके आए we are proud of our Party. यहां पर कूका जी कह रहे थे और मैं आपको यह कहना चाहती हूं। यह कांग्रेस के बारे में मैं यह कह रही हूं। यह अल्लामा इकबाल का शेर है:-

कुछ बात है हस्ती मिटती नहीं हमारी,

सदियों रहा है, दुश्मन हमारा।

ये कांग्रेस है। We are proud of our leadership. We are proud of our Party. You don't have to tell me whoever was saying from here that we are Leader less. जैसी आपकी लिडरशिप है, वैसी लिडरशिप हमको नहीं चाहिए। We are proud of our leadership. अध्यक्ष महोदय, बड़े दुख की बात है कि किन सेक्टर्ज में बजट कम हुआ है। हमारे सदस्य, श्री आशीष बुटेल जी ने कहा था कि स्वास्थ्य के सेक्टर में -5 प्रतिशत, एग्रीकल्चर सेक्टर में -6 प्रतिशत, water supply and sanitation -23 प्रतिशत, आप यह कहेंगे कि जल शक्ति मिशन का पैसा अलग से आ रहा है, इसलिए हुआ है। ऐसा नहीं है, सैनिटेशन भी इसी में है, सीवरेज सिस्टम भी इसी में है और जो रूरल वॉटर सप्लाई है, वह

09.03.2022/1440/JS/YK/2

भी इसी में है। आंकड़ों का जाल बिछा करके आप दुनिया को ठग नहीं सकते हैं। आपने अर्बन डवल्पमैंट में -14 प्रतिशत कर दिया। स्मार्ट सिटी आज नहीं आई है। स्मार्ट सिटी के प्रोग्राम बहुत पहले से चल रहे हैं। माननीय मंत्री, श्री सुरेश भारद्वाजा जी मेरे मामा जी हैं, अभी वे यहां पर नहीं हैं। पहले जे.आर.यू.एम. में आया था उसके बाद कन्वर्ट हो करके इसमें आया। कोई AMRUT भी आ रहा है और आपका -14 प्रतिशत हो गया। अध्यक्ष महोदय, पैंशन के बारे में मैं इसलिए नहीं बोलूंगी कि इसमें पूरी चर्चा हो चुकी है। बार-बार एक ही बात को रिपीट करना ठीक नहीं है मगर जो मेरे साथी सदस्यों ने कहा मैं उनके साथ बिल्कुल सहमत हूं। पैंशन का स्लैब एक ही होना चाहिए वह चाहे किसी भी स्कीम में हो। मेरा मुख्य मंत्री महोदय से यह आग्रह जरूर रहेगा कि जो "सहारा योजना" आपने चलाई है, उसमें आप 3 हजार से बढ़ा करके 5 हजार करते तो अच्छा होता। अभी भी आप

कर सकते हैं। हम आपको उसके लिए आग्रह करते हैं। यह अच्छी योजना है। इस योजना में अगर आप धन बढ़ाएंगे तो it is good because असहारा लोगो के लिए है। माननीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री जी यहां पर बैठे हुए हैं। आपका धन्यवाद वह एम.आर.आई. की मशीन मेरे वहां पर पहुंच गई है। सिटी स्कैन भी शायद आपने चालू कर दिया है मगर समस्या यह है कि वहां पर स्टाफ ही नहीं है। रेडियोग्राफर नहीं है। गाइनाक्लोजिस्ट नहीं है। अरूण कुमार जी आप क्यों बोल रहे हैं। आपसे कोई बात भी नहीं कर रहा है। Why you are talking, who are you to say anything to me. मंत्री जी आपका धन्यवाद आपकी वह मशीन पहुंच गई। मेरा आपसे आग्रह रहेगा कि वहां पर स्टाफ की बहुत ज्यादा कमी है। नॉर्मल एक्स्रे भी होते हैं, नॉर्मल सिटी स्कैन के लिए भी लोग आते हैं। एक-एक, दो-दो महीने की देर होगी तो जिन लोगों को सीरियस बीमारियां हैं, उनको फिर प्राइवेट में ही जाना पड़ेगा। लेकिन आप जो बैनिफिट देना चाहते हैं उससे लोगों को कोई फायदा नहीं हो रहा है। अभी अखबारों में आपने देखा होगा। आप मंत्री हैं, आप तक वह अखबार भी पहुंची होगी। जो आपके विभाग के बारे में कहा जाता है, वह आपको पुट अप होता ही होगा। मेरा तो यही एक्सपीरियंस रहा है जब मैं मंत्री थी तो जब हमारे विभाग के बारे में छपता था वह अच्छा हो या बुरा वह हमें

09.03.2022/1440/JS/YK/3

पुट अप होता था। चम्बा में गाइनोक्लोजिस्ट की कमी होने के कारण वे मरीज टांडा रैफर होते हैं। टांडा में भी इन्क्युवेटर्ज नहीं है यदि कोई प्री-मैच्योर बेबी पैदा होता है वहां न इन्क्युवेटर्ज नहीं है फिर वे पी.जी.आई. रैफर होते हैं। पी.जी.आई. में यदि वे यूज़ में हो तो वे कहते हैं कि 16 सेक्टर में जाओ, 32 सेक्टर में जाओ। कम-से-कम यह बेसिक सुविधा जो गर्भवती महिलाओं के लिए है या इसको प्रदान करने का मेरा आपसे आग्रह रहेगा कि इसको आप करें। अध्यक्ष महोदय, मेरा प्रश्न 8 मार्च को लगा हुआ था कि मेरे चुनाव क्षेत्र में हैल्थ इंस्टिच्युशन को ले करके लगा हुआ था। मेरे चुनाव क्षेत्र में 35 हैल्थ इंस्टिच्युशन्ज हैं।

श्री एस.एस. द्वारा जारी-----

09.03.2022/1445/SS-AG/1

श्रीमती आशा कुमारी क्रमागत :

आपने हर हॉस्पिटल में डॉक्टर दे रखे हैं। परन्तु आपके कुछ ऐसे प्राईमरी हैल्थ सेंटर्ज हैं जहां पर सिर्फ डॉक्टर्ज ही हैं। वहां पर क्लास-IV भी नहीं है। नर्सिज नहीं हैं। आपका यह रिप्लाई है कि इन 35 इंस्ट्रियूशन्ज़ में 274 पोस्टों में से 156 पोस्टें खाली हैं। मेरा आपसे आग्रह रहेगा कि अगर लोगों को सुविधा देनी है खास करके जो सब-सेंटर्ज हैं वहां पर पोस्टें भरी जाएं। मेरे चुनाव क्षेत्र में 22 सब-सेंटर्ज हैं। 22 सब-सेंटर्ज में से 18 सब-सेंटर्ज में मेल हैल्थ वर्कर्ज वेकैंट हैं। 14 सब-सेंटर्ज में फीमेल हैल्थ वर्कर्ज वेकैंट हैं। आप मुझे बताइए कि ये सब-सेंटर्ज खुले हैं या नहीं खुले हैं?

अध्यक्ष महोदय, मैंने पिछले बजट स्पीच भी सुनी है। पिछली स्पीचिज में मुख्य मंत्री जी ने कहा कि 30 हजार भर्तियां होंगी। आपके आंकड़े यह कहते हैं कि 5 साल में आपने कुल 29000 भर्तियां की हैं। यह बात आपका बजट कहता है, मैं नहीं कह रही। आप हर बार 30 हजार कहते हैं लेकिन करते कुछ नहीं हैं। मैं मुकेश जी की बात को दोहराती हूं कि तीस मारखां हैं। कर्मचारी सड़कों पर हैं। मैं अशोक गहलोत जी का धन्यवाद करना चाहूंगी जिन्होंने राजस्थान में ओल्ड पेंशन स्कीम दी। आज छत्तीसगढ़ सरकार का धन्यवाद करना चाहूंगी जिन्होंने छत्तीसगढ़ में भी ओल्ड पेंशन स्कीम लागू कर दी। मैं इसलिए भी धन्यवाद करना चाहूंगी क्योंकि मेरे भाई भी उस कैबिनेट में मंत्री हैं। आज यहां पर मामा जी (श्री सुरेश भारद्वाज जी) नहीं हैं लेकिन जुब्बल वाले उपस्थित हैं। जुब्बल वालों के हम भांजे-भांजी हैं। We are proud of our Himachali blood also. ...व्यवधान... Will you stop it? अध्यक्ष महोदय, इन्होंने जो 30 हजार भर्तियों की बात की, मेरा एक प्रश्न एग्रीकल्चर पर लगा हुआ था। संबंधित माननीय मंत्री जी यहां पर बैठे हैं। आपने उसका जवाब दिया कि 50 प्रतिशत से ज्यादा पोस्टें खाली हैं। क्या ये जो 30 हजार भर्तियां हो रही हैं इसमें आपका विभाग भी कंसीडर होगा? एग्रीकल्चर एक्सटेंशन ऑफिसर की यह हालत है कि अगर उनकी 7 पोस्टें हैं तो

सारी ही वेकैंट हैं। यह सलूणी और तीसा में हालत है। मुझे नहीं मालूम कि आज हमारे उपाध्यक्ष महोदय कहां हैं। मगर तीसा में यही हाल है। सात पोस्टें हैं और सातों वेकैंट हैं। क्या ऐसे आपका एग्रीकल्चर डिपार्टमैंट चलेगा? निश्चित तौर पर आप माइनस में जाएंगे। निश्चित तौर पर आपकी ग्रोथ घटेगी।

अध्यक्ष महोदय, इसी तरह से मुकेश अग्निहोत्री जी ने एक बात कही कि फ्लावर मंडी के नाम पर परवाणू में एक कमरा बनाया है। इस तरह का भद्दा मजाक हिमाचल प्रदेश के साथ मत करिए। ध्वाला जी ने ठीक बोला कि अगर हम युवाओं और ग्रामीणों को प्रोत्साहित करेंगे और उनकी इंकम एश्योर्ड होगी चाहे फूल लगाने की बात हो, चाहे पौधे लगाने की बात या सीड्स की बात हो परन्तु अगर हम उनको प्रोत्साहित करेंगे तब ही लोग हमारे साथ आगे आएंगे। अब आप एक कमरा बनाकर बोल दें कि फ्लावर मंडी बन गई तो ऐसे काम नहीं बनेगा।

ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री : आप सैशन के बाद वहां पर घूमकर आना। मैं उसका उद्घाटन करके आया हूं। वहां पर एक कमरा नहीं बल्कि 10 कमरे बने हुए हैं।

श्रीमती आशा कुमारी : मैं उस रास्ते रोज़ ही जाती हूं। अध्यक्ष महोदय, मंत्री जी का टाइम मेरे टाइम में से काट लिया जाए। मंत्री जी, आप एग्रीकल्चर की पोस्टें भरो, बाकी बाद में बात करेंगे।

अध्यक्ष महोदय, मुख्य मंत्री महोदय ने कहा कि लोकल व्हीट और मेज़ को प्रोत्साहित करने के लिए 5 करोड़ रुपये से 10 करोड़ रुपये की राशि बढ़ाई गई है। मैं इनसे आग्रह करना चाहूंगी, वैसे मैंने प्रश्न पहले एग्रीकल्चर पर लगाया था लेकिन जो स्कीम जी0आई0 स्टेट्स के लिए गई हुई है चम्बा में हमारा भांदल का इलाका है, लाल कुकड़ी, सफेद कुकड़ी, उसको ऊंची बोलते हैं, दो-तीन तरह की मेज़ की वैराइटीज़ हैं उनको for variety of seed

के लिए नेशनल अवार्ड मिला। जी0आई0 स्टेट्स के लिए हमारा चेन्नई में केस पैंडिंग है। मुख्य मंत्री जी उपस्थित नहीं हैं तो माननीय मंत्री

09.03.2022/1445/SS-AG/3

श्री महेन्द्र सिंह जी मौजूद हैं। हिमकॉस्ट करके आपका आई0टी0 का एक विंग है उसके थ्रू यह चेन्नई जी0आई0 स्टेट्स के लिए गया है। अगर आपको जी0आई0 स्टेट्स मिल जाता है तो निश्चित आपके यहां के सीड्स ब्रांडिड हो जाएंगे। वे रैकोग्नाइज्ड हो जाएंगे। इसमें आप हमारी मदद करें और इसको करवाएं।

अध्यक्ष : माननीय सदस्या अब वाइंड अप करिए।

श्रीमती आशा कुमारी : अध्यक्ष महोदय, महेन्द्र सिंह जी से तो हम कट मोशन पर बात कर लेंगे। उसमें मुझे नहीं बोलना है। लेकिन एक-दो बातों पर मुझे बहुत जरूरी बोलना है आप मुझे अलाऊ करेंगे।

जारी श्रीमती के0एस0

09.03.2022/1450/KS/AG/1

श्रीमती आशा कुमारी जारी---

मैं तो सिर्फ बजट पर बोल रही हूं। मैं बी.जे.पी. या औरों के बारे में नहीं बोल रही हूं।

अध्यक्षः प्लीज़ आशा जी, वाइंड अप करिए।

श्रीमती आशा कुमारीः अध्यक्ष महोदय, दो मिनट प्लीज़। मेरा यह भी निवेदन है कि ऑफ सीज़न वेजिटेबल्ज़ के लिए आप चम्बा के सैंटर के एरिया में जैसे देवीदेरा है, वहां नहीं बनाना है क्योंकि वह मेरा चुनाव क्षेत्र पड़ता है तो नैनीखड्ड या तुनुहट्टी आदि जगह पर बना दें ताकि जहां से लोग अपनी सब्जियां ले कर आते हैं तो उनको कष्ट न हो। आढ़ती अमृतसर और नीचे के इलाकों से आते हैं।

अध्यक्ष महोदय, मैं ग्राम रोज़गार सेवकों के बारे में एक बहुत जरूरी बात करना चाहूंगी। ग्राम रोज़गार सेवकों को तीन-तीन महीने से सैलरी नहीं मिली है। आप जानते हैं कि मनरेगा का काम, सर्टिफिकेट्स बनाने का काम, सारा काम वे ही करते हैं। उनको सैलरी नहीं मिलेगी तो वे काम क्यों करेंगे? आपका यह कहना है कि मनरेगा के फंड सैंटर से नहीं आ रहे हैं। सैंटर से कहां से आएंगे जब वहां पर कट लगा दिया? सैंटर ने मनरेगा पर कट लगा दिया है और मंत्री जी को अच्छी तरह से पता है कि मनरेगा ही वह स्कीम है जिसकी वजह से हम डॉ0 मनमोहन सिंह और सोनिया गांधी जी के फिर धन्यवादी हैं कि उन्होंने मनरेगा लाया और उसकी वजह से ही कोरोना काल में लोगों को कुछ रोज़गार मिला और मेरा आपसे भी निवेदन रहेगा कि आपने मजदूरों की दिहाड़ी 50 रुपये बढ़ाई है। आप जितना भी बढ़ाओ हमेशा अच्छी बात होती है मगर यह बात बताओ कि आप मनरेगा में बढ़ाएंगे या नहीं? आज सबसे ज्यादा लेबर मनरेगा में है। उसकी दिहाड़ी महज 203 रुपये है। क्या आप उसको बढ़ाएंगे?

अध्यक्ष महोदय, मुझे दो बातें और कहनी हैं। एक स्ट्रे कैटल की बात आई थी। बलबीर सिंह वर्मा जी और डॉ0 राजीव बिन्दल जी आज दोनों ही यहां पर नहीं हैं,

09.03.2022/1450/KS/AG/2

उन्होंने कहा कि पहली बार, मैं सिर्फ इस बात को करैकट करने के लिए बोल रही हूं कि पहली बार जो इस हाउस में एक्ट लाया था, माननीय मुख्य मंत्री शांता कुमार जी ने 1979 में लाया था और दूसरी बार जो पॉलिसी लाई थी 6 जून, 2014 को उस समय के माननीय मुख्यमंत्री राजा वीरभद्र सिंह जी ने लाई थी। तो पहली बार कहां हो गया? आप शांता कुमार जी और वीरभद्र सिंह जी की सोच को आगे ले जाएं, अच्छी बात है लेकिन यहां पर गलत बातें नहीं रखें। वर्ष 1979 में मेरे ख्याल में वे ही चीफ मिनिस्ट थे तो पहली बार कैटल को ले कर शांता कुमार जी के समय में एक्ट आया था।

अध्यक्ष महोदय, एक बहुत ज़रूरी बात करना चाहूंगी। खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले मंत्री जी यहां नहीं हैं। घटिया क्वालिटी का राशन राशन की दुकानों में मिल रहा है। एक तोता नामक तेल जिसकी ये चर्चा कर रहे थे कि सरसों का तेल 225 नहीं, हम 170 रुपये में दे रहे थे। तोता उड़, चिड़िया उड़ बीच में गधा उड़। अगर अध्यक्ष जी, आप मुझे अलाउ करें तो मैं सचिव, विधान सभा के जरिए यहां पर हाउस में उस विडियो को जो कि नूरपुर का है, जब उस तेल को एक मलमल का कपड़ा लगाकर साफ किया जा रहा है तो उसमें चर्बी जैसी कोई चीज़ ऊपर आ रही है और पैकेट ऑफ्टर पैकेट आ रही है। यह कौन सा तोता आया है? पी. मार्का तेल आप क्यों नहीं देते? क्यों आप standardized तेल दे रहे हैं? लोगों को क्यों मार रहे हैं। नमक डालो पीली दाल वैसे ही काली हो जाती है। आपका राशन सब स्टैंडर्ड है।

अध्यक्षः माननीय सदस्या, कृपया वाइंड अप करें।

श्रीमती आशा कुमारीः बस दो मिनट अध्यक्ष महोदय। मेरा आपसे यह निवेदन रहेगा कि आप सरसों का तेल सही क्वालिटी का दें और आपने उज्ज्वला योजना में गैस के तीन

09.03.2022/1450/KS/AG/3

सिलेंडर देने हैं चार देने हैं, जो मर्जी दीजिए मगर राहत देने के लिए गैस सिलेंडर पर सबसिडी दीजिए।

अध्यक्ष महोदय, वाटर सप्लाई पर मैं नहीं बोलूंगी। आपने रोड्ज़ पर 150 करोड़ की बात कही। हमें उम्मीद है कि आप हमारे चुनाव क्षेत्रों की डी.पी.आर्ज़. भी बनवाएंगे। मेरा एक प्रश्न लगा था, पिछले कई सालों से हमारे डलहौजी डिविज़न में माननीय साथी सदस्यों की डी.पी.आर्ज़. तो बन रही हैं, हमारी नहीं बन रही है। तो मेरा निवेदन है कि हमारी डी.पी.आर्ज़. भी बनवाई जाए।

टूरिज्म के बारे में मुझे एक बात कहनी थी कि ए.डी.बी. बैंक के साथ आप जो 2098 करोड़ रुपये का प्रोजैक्ट कह रहे हैं, इसमें चंबा को भी उचित स्थान मिलेगा। इसी तरह से आर्ट

गैलरी कांगड़ा की चर्चा हुई। जो आर्ट गैलरी बनी, उसकी बिल्डिंग का आपने उद्घाटन कर दिया उसमें आर्ट गैलरी का तो कुछ लगाया ही नहीं। What sort of art gallery it is? It is just a building. आप उसका क्या करेंगे?

अध्यक्ष महोदय, अगर हमने टूरिज्म को बढ़ावा देना है, मेरे भाई सुन्दर ठाकुर जी भी यहां बैठे हैं, Film City and Film Policy 2019 में लाई गई थी, उसका क्या हुआ? मेरा प्रश्न लगा हुआ था उसके जवाब में आया कि अभी कोई सूचना या प्रपोज़ल नहीं है। आपने तो उसके लिए कमेटी बनानी थी corpus बनाने के लिए, आपने तो कमेटी भी नोटिफाई नहीं की। वह चीफ सैक्रेटरी की अध्यक्षा में बननी थी, वर्ष 2019 से 2022 आ गया, आपके जाने का समय आ गया, अगर आप फिल्म सिटी बनाने की कोशिश कुल्लू या मनाली, चम्बा, डलहौजी, सुलह या पालमपुर में करेंगे, कम से कम उससे टूरिज्म को बढ़ावा मिलेगा।

श्रीमती अ0व0 द्वारा जारी--

09.03.2022/1455/av/as/1

श्रीमती आशा कुमारी-----जारी

I am seriously saying this. मैं अब युवा सेवाएं एवं खेल के बारे में बोलना चाहूंगी। आपने बजट में क्रिकेट, कबड्डी के बारे में बात की है। हमारे हिमाचल प्रदेश के नवयुवक श्री वरुण कुमार ने ओलम्पिक्स में यहां ब्रॉन्ज मैडल जीतकर लाया। अभी यहां पर मंत्री जी बैठे नहीं है मगर हमने आपसे पहले भी निवेदन किया था कि प्रदेश में हॉकी को भी प्रोत्साहन दिया जाए। जिला चम्बा में जनरेड़ा नामक स्थान पर स्थानीय युवाओं ने खुद एक बहुत बड़ा खेल मैदान बनाया है। इसलिए मैं यह पूछना चाहती हूं कि क्या सरकार चम्बा में भी एक हॉकी फील्ड बनाने का विचार रखती है? मैं जनरेड़ा की बात इसलिए कर रही हूं क्योंकि वहां पर लैंड उपलब्ध है। मैं अब अपना लास्ट प्वाइंट रखना चाहती हूं। यहां पर ट्राइबल प्लान की बात की गई है 'for the welfare of tribal in non-tribal area' एक्शन प्लान बनाएंगे। मेरा यह कहना है कि एक्शन प्लान की बात नहीं है बल्कि आपको बजट देना चाहिए। मेरा आपसे निवेदन रहेगा कि हमें माननीय सदस्य श्री जगत सिंह नेगी का ट्राइबल का बजट

काटकर न दिया जाए, हमें एडिशनल बजट दिया जाए for tribal living in non tribal area के लिए। ऐसा न करें कि ट्राइबल का बजट काट कर हमें दे दिया जाए और उसमें लड़ाई वाली बात हो जाए। सबसे ज्यादा tribal living in non tribal area माननीय सदस्य श्री बिक्रम सिंह जरयाल और मेरे चुनाव क्षेत्र में हैं। इसलिए हमारा निवेदन रहेगा कि इसको जरूर पूरा किया जाए। अध्यक्ष महोदय, यहां बजट पढ़ते वक्त माननीय मुख्य मंत्री और दूसरे कई माननीय सदस्यों ने अपने-अपने भाषण में काफी शेरो-शायरी की है। वैसे तो माननीय सदस्य श्री इन्द्र दत्त लखनपाल ने एक अच्छा सुझाव दिया है कि इसके लिए आप एक अलग से सैशन बुला लीजिए; उसमें संगोष्ठी कर लेंगे। अगर आपने शेरो-शायरी ही करनी थी तो आप अपनी पार्टी के पूर्व मुख्य मंत्री श्री प्रेम कुमार धूमल जी से कर लेते। श्री प्रेम कुमार धूमल जी एक अच्छे शायर हैं। अंत में, मैं यह कहना चाहती हूं कि इस बजट के बारे में चर्चाएं बहुत थीं। इसलिए मैं भी यहां पर ग़ालिब का एक शेर पेश करना चाहूंगी जोकि इस प्रकार है :-

09.03.2022/1455/av/as/2

थी खबर गर्म कि ग़ालिब के उड़ेंगे पुर्जे।
देखने हम भी गए थे तमाशा, पर तमाशा ही न हुआ॥

एक और शेर कहना चाहूंगी जो कि शौक बहराइची ने लिखा है। बहराइची जगह गुजरात राज्य में पड़ती है और ये वहां के शायर थे। उनका असली नाम तो रियासत हुसैन रिज़वी था। मैं चाहूंगी कि यहां पर कोई भी मेरी बात का बुरा नहीं मानेंगे परंतु यहां पर जिस तरह से आपकी ब्यूरोक्रेसी एडवाइस दे रही है और जिस तरह से आपका इन-पुट है; मैं उसके बारे में यह कहना चाहूंगी किः-

'बर्बाद गुलिस्तां करने को बस एक ही उल्लू काफ़ी है।
हर शाख पे उल्लू बैठें हैं, अंजाम-ऐ-गुलिस्तां क्या होगा॥

अभी माननीय मुख्य मंत्री सदन के अंदर नहीं बैठे हैं। आजकल मुख्य मंत्री जी को बहुत गुस्सा आता है, इसलिए मैं यहां पर उनके लिए एक शेर पढ़ना चाहती हूं कि :-

हमने देखा है ज़माने का बदलना।
लेकिन उनके बदले-बदले तेवर हमसे देखे नहीं जाते॥

अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे बोलने का समय दिया, आपका धन्यवाद।

समाप्त

अध्यक्ष : अब माननीय सदस्य श्री बिक्रम सिंह जरयाल चर्चा में हिस्सा लेंगे।

अगले वक्ता टी सी द्वारा जारी

09/03/2022/1500/टी0सी0वी0/डी0सी0/1

श्री बिक्रम सिंह जरयाल, भटियात : अध्यक्ष महोदय, 4 मार्च, 2022 को हमारे आदरणीय मुख्य मंत्री, श्री जय राम ठाकुर जी ने मु0 51,365 करोड़ रुपये का बजट पारित किया। उसकी पूरा प्रदेश भूरि-भूरि प्रशंसा कर रहा है। विपक्ष का रोल इस प्रकार से हैं:-

'जैसे नई नवेली दुल्हन की तरह सरकार पकवान रूपी बजट पेश करती है, लेकिन विपक्ष सासू मां की तरह बहुत-सारी खामियां निकलता है।'

अध्यक्ष महोदय, आदरणीय मुख्य मंत्री जी ने जो बजट पेश किया है उससे आंगनबाड़ी, आशा वर्कर्ज, मिड-डे मील वर्कर्ज, आउटसोर्स कर्मचारी, चौकीदार और एस0एम0सी0 शिक्षकों की बल्ले-बल्ले हुई है और मुख्य मंत्री जी की चर्चा आज पूरे हिमाचल प्रदेश में हो रही है। माननीय सदस्या, मेरी बड़ी बहन (श्रीमती आशा कुमारी जी की ओर इशारा करते हुए) कह रही थी कि बिक्रम सिंह जरयाल की डी0पी0आर्ज0 बहुत बन रहीं हैं लेकिन डी0पी0आर्ज0 बनाने के लिए हमें खुद भी कोशिश करनी चाहिए। मेरे चुनाव क्षेत्र में एफ0आर0ए0 के 48 केस सैंक्शन होकर आए हैं। यहां पर लीडरशिप की बात हो रही थी। इनके लीडर कहते हैं कि हम आलू से सोना निकालेंगे। एक तरफ से आलू डालेंगे और

दूसरी तरफ से सोना निकलेगा। मनरेगा कांग्रेस के समय में शुरू हुआ था लेकिन आज प्रधान मंत्री, आदरणीय नरेन्द्र मोदी जी ने मनरेगा शहरी क्षेत्रों में भी शुरू कर दिया

(माननीय सभापति, कर्नल इन्द्र सिंह पदासीन हुए)

है और उसकी रेशो 60:40 से बढ़ाकर 80:20 कर दी है। श्री जय राम ठाकुर जी ने अंतिम पंक्ति में जो व्यक्ति खड़ा है उसके लिए यह बजट प्रस्तुत किया है। मैं लीडरशिप की बात करना चाहूंगा क्योंकि बजट पर सभी ने बोल दिया है।

अगर आपका राष्ट्र नेता मजबूत नहीं है तो शरणार्थी बनने में देर नहीं लगती।
महंगाई कोई मुद्दा नहीं है, सुरक्षा और राष्ट्र सबसे बड़ा मुद्दा है।
जब हम रहेंगे तो महंगाई की मार झेलेंगे,
जब रहेंगे ही नहीं तो महंगाई की मार कौन झेलेगा।

एन0एस0 द्वारा जारी ..

09-03-2022/1505/NS/DC /1

श्री बिक्रम सिंह जरयाल.....जारी

हम तो खुशियां उधार देने का कारोबार करते हैं साहिब,

कोई वक्त पर लौटाता नहीं जैसे आप नहीं लौटाते,

इसलिए घाटे में चल रहे हैं।

जिंदगी के सफ़र से बस इतना ही सीखा है, सहारा कोई नहीं देता।

जैसे मुख्य मंत्री जी गरीबों को सहारा दे रहे हैं,

धक्का देने के लिए आप जैसे बहुत खड़े हैं।

सभापति महोदय, बजट सभी का बढ़ाया गया है चाहे वे पंचायत चौकीदार हों। मुख्य मंत्री जी ने बजट में सब वर्गों को छुआ है। यहां पर विपक्ष वाले बोल रहे थे कि कहां है? आप बहस या चर्चा तब करो अगर यह लागू नहीं होता। मैं यहां पर कुछ कहना चाहूंगा कि

जैसे उबलते पानी में कभी परछाई नहीं दिखती

ठीक उसी प्रकार इस बजट में विपक्ष को कुछ नहीं दिखता।

शांत होकर देखिए, सभी समस्याओं का हल हो जाएगा।

सभापति महोदय, यहां पर स्कीमों के बारे में भी कहा गया। मैं, मुख्य मंत्री जी और उनके सभी सहयोगी मंत्रियों का धन्यवाद करता हूं। पिछले चार वर्षों में 97 नई योजनाएं प्रदेश में लागू हुईं हैं। यहां पर माननीय सदस्यों ने बताया है कि बढ़ी हुई पेंशन से सभी खुश हैं। गौवंश का भी हमारी सरकार ने ध्यान रखा है। सरकार हमारी गायों के लिए भी उत्कृष्ठ फार्म स्थापित करने जा रही है। गाय के चारे के लिए 500 से 700 रुपये प्रति गाय चारे में बढ़ौतरी की है। इसके लिए शराब की बोतल पर टैक्स एक रुपये से बढ़ा करके दो रुपये प्रति बोतल किया गया है। गरीब लोगों का तो इस बजट में ध्यान रखा ही गया है लेकिन बेजुवान पशुओं का भी ध्यान रखा गया है।

सभापति महोदय, यहां पर कहा गया कि हम कर्मचारियों का ध्यान नहीं रखते हैं। कर्मचारी सड़कों पर हैं और रो रहे हैं तथा चिल्ला रहे हैं। हमारी सरकार ने कर्मचारियों के लिए पंजाब के पे-स्केल के हिसाब से 15 प्रतिशत बढ़ौतरी की है। पहले

09-03-2022/1505/NS/DC /2

किसी भी स्टेट में ऐसा नहीं हुआ है। इसके लिए मैं मुख्य मंत्री जी का धन्यवाद करता हूं। हमारी सरकार ने दूध के दाम भी बढ़ा दिए हैं। इसके अतिरिक्त 4.50 लाख लोगों के बिजली यूनिट कम किए हैं। लोगों को 60 यूनिट तक बिजली मुफ्त मिलेगी और कोई बिल नहीं आएगा, उनका मीटर बिल भी नहीं आएगा। इसके साथ ही जो उपभोक्ता 125 यूनिट तक बिजली कंज्यूम करता है उसका 1.90 रुपये से घटा कर रेट 1.00 रुपये कर दिया गया है। किसानों की बिजली का रेट प्रति यूनिट 30 पैसे कर दिया है जोकि पहले 50 पैसे होता था। सबसे बड़ी बात गरीब और वृद्ध लोग पेंशन के लिए हाथ फैलाते थे और पटवारी 35,000 रुपये से नीचे इनकम नहीं लिखता था। इस क्रायटेरिया को बढ़ा कर मुख्य मंत्री जी ने 50,000 रुपये कर दिया है। इसके लिए मैं मुख्य मंत्री जी का धन्यवाद करता हूं।

सभापति महोदय, ग्रोथ ऑफ एग्रीकल्चर 3.9 से बढ़ कर 9.0 तक पहुंच गई है। इसके लिए मैं मंत्री जी का धन्यवाद करता हूं। सभापति महोदय, यहां पर 'जल शक्ति मिशन' और वैक्सीन की बात कर रहे थे। इतनी बड़ी महामारी में मुफ्त में वैक्सीन सिर्फ़ हिन्दुस्तान में लगी है। मेरे विधान सभा क्षेत्र की एक पंचायत में लोगों ने वैक्सीन लगवाने और टैस्ट करवाने से मना कर दिया। मैंने पूछा कि आप ऐसा क्यों कह रहे हैं? इस पर वे

कहने लगे कि मोदी जी टैस्ट करेंगे और हमें कोरोना पोजिटिव निकालेंगे, अस्पताल में दाखिल करेंगे और मार देंगे। ऐसी-ऐसी भ्रांतियां कांग्रेस ने फैलाईं थीं। जब से वैक्सीन निकली वही लोग सबसे पहले वैक्सीन लगवाने आए और बोले कि हमें वैक्सीन पहले लगाओ कहीं हम मर न जाएं। पूरे भारत वर्ष में हिमाचल प्रदेश इसमें प्रथम रहा है और इसके लिए मैं, मुख्य मंत्री जी को बधाई देता हूं।

सभापति महोदय, हिमकेयर योजना के कार्ड की तीन साल तक वेलिडिटी होगी और हर साल व हर दिन यह कार्ड रिन्यू होगा।

श्री आर0 के0 एस0 द्वारा जारी।

09.03.2022/1510/RKS/डीसी-1

श्री बिक्रम सिंह जरयाल... जारी

इसके लिए मैं श्री जय राम ठाकुर जी का धन्यवाद करता हूं। मुख्यमंत्री सहारा योजना के अंतर्गत लोगों को घर बैठे तीन हजार रुपये मिल रहे हैं। सांसद मोबाइल वैन के माध्यम से घर-घर जाकर 40 टैस्ट मुफ्त करवाए जा रहे हैं। मुख्यमंत्री मोबाइल क्लिनिक योजना के अंतर्गत प्रदेश के प्रत्येक विधान सभा क्षेत्र में एक मोबाइल क्लिनिक चलाया जाएगा जिससे गरीब लोगों को बहुत बड़ी राहत मिलेगी। कई बड़े स्वास्थ्य संस्थान प्रदेश में स्थापित किए गए हैं। 300 दवाइयां और 56 टैस्ट मुफ्त करवाए जा रहे हैं। आप प्रदेश में क्रियान्वित योजना के तहत पांच लाख रुपये तक फ्री ट्रीटमेंट करवा सकते हैं। आधुनिक आंगनवाड़िया, उत्कृष्ट विद्यालय और महाविद्यालय स्थापित किए जा रहे हैं। हर स्कूल में पर्याप्त स्टाफ है। इस सरकार द्वारा प्रदेश में प्री-नर्सरी व नर्सरी की कक्षाएं भी शुरू कर दी हैं ताकि गरीब लोग भी अपने बच्चों को सरकारी स्कूल में प्री-नर्सरी व नर्सरी की शिक्षा दे सकें। गृहिणी सुविधा योजना के तहत 5 लाख मुफ्त कनैक्शन दिए गए हैं। अब हम इस योजना के तहत तीन मुफ्त सिलेंडर दे रहे हैं। मुख्य मंत्री आवास योजना के तहत 20,000 नये भवन बनाए जाएंगे। नई आंगनवाड़ियां स्थापित करने के लिए 70 करोड़ रुपये का

बजट प्रावधान किया गया है। उन्नत और जैविक खेती के लिए 1.50 लाख किसानों को पंजीकृत किया गया है। इस खेती को हर पंचायत में लागू किया जाएगा। स्वावलंबन योजना के तहत 8 हजार नौजवानों ने अपना रोजगार स्थापित किया है और वे इसमें आगे और लोगों को भी रोजगार मुहैया करवा रहे हैं। इस योजना के तहत महिलाओं के लिए 35 प्रतिशत और एस.सी./एस.टी. व ओ.बी.सी. के लिए 30 प्रतिशत अनुदान राशि प्रदान की जा रही है। स्वयं सहायत समूह के लिए 25 हजार रिवोल्विंग फंड 4 प्रतिशत ब्याज में दिया जाएगा। जल जीवन मिशन के अंतर्गत 17,28,000 ग्रामीण परिवारों में से 15, 79,000 हजार परिवारों को पेयजल कनैक्शन्ज प्रदान कर दिए गए हैं। इस तरह जल शक्ति, पी.डब्ल्यू.डी, ऊर्जा और स्वास्थ्य विभाग में करोड़ों रुपये की योजनाएं चल रही हैं। कुछ लोग कह रहे थे कि

09.03.2022/1510/RKS/डीसी-2

नलकों में पानी नहीं आता। आप पानी ढूंढ रहे हैं लेकिन हमारी सरकार स्वच्छ जल उपलब्ध करवा रही है। एस.सी., एस.टी. और ओ.बी.सी. के लिए लिए जो कोर्पोरेशन ऋण लेने के लिए 12 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है उसे माफ करने की भी बात कही गई है। पहले हमारे प्रदेश की जी.डी.पी. साढ़े तीन प्रतिशत थी जो अब बढ़कर 8.50 प्रतिशत हो गई है। पंचायती राज राजनीति की रीढ़ है। पंचायती राज में जिला परिषद् से लेकर सभी पंचायत प्रतिनिधियों के मानदेय को बढ़ाया गया है। आज वे सभी जन प्रतिनिधि खुश हैं। विधायक ऐच्छिक निधि को 10 लाख रुपये से बढ़ाकर 12 लाख रुपये कर दिया है। विधायक क्षेत्र विकास निधि योजना को 1.80 करोड़ रुपये से बढ़ाकर दो करोड़ रुपये किया गया है। मैं अंत में एक शेर कहना चाहूंगाः-

कहने वालों को कहने दो कोई बड़ी बात नहीं,
कहने वाले कहते जाएंगे क्योंकि इससे ज्यादा इनकी सोच नहीं।

सभापति महोदय, आपने मुझे बोलने का समय दिया, आपका धन्यवाद।

सभापति : अब माननीय सदस्य डॉ. (कर्नल) धनी राम शांडिल जी चर्चा में भाग लेंगे।

श्री बी.एस. द्वारा... जारी

09.03.2022/1515/बी.एस./एच0के0/-1

डॉ0 (कर्नल) धनी राम शांडिल : सभापति महोदय, मुख्य मंत्री जी द्वारा 4 मार्च, 2022 को जो बजट इस सम्माननीय सदन में प्रस्तुत किया गया है, उस पर बोलने के लिए मैं खड़ा हुआ हूं। आपने बोलने का समय दिया, आपका धन्यवाद। सभी माननीय सदस्यों ने यहां पर बात रखी है, यह बजट ऐसे समय में प्रस्तुत किया जा रहा है, जब चुनावी वर्ष है। मैं मुख्य मंत्री महोदय का धन्यवाद करता हूं कि इन्होंने विधायक क्षेत्र विकास निधि में एक करोड़ 80 लाख रुपए से बढ़ा करके इसे दो करोड़ रुपए कर दिया है और जो discretionary grant है उसे 10 लाख से 12 लाख कर दिया है। इस पर आज सुबह ही माननीय सदस्य लखनपाल जी ने कुछ सुझाव दिए थे और मैं समझता हूं कि आप के सन्दर्भ में अगर उन पर विचार किया जाए तो यह सब के हित में होगा। जहां हम इन सभी कदमों की प्रशंसा करने से चूक नहीं सकते वहीं सभापति महोदय, जब ध्यान से इस बजट को पढ़े तो यह प्रस्तुती करण बड़े सुन्दर तरीके से हुआ है और इसकी शैली भी मन लुभावनी शैली के रूप में पस्तुत हुई है। शेरो-शायरी की भी काफी महक रही है। But I feel that the overall Budget has presented a rosy picture which is slightly away from the facts on the ground. इसे जब दोबारा पढ़ा जाएगा और इसका अवलोकन दोबारा किया जाएगा तो कुछेक ग्लेयरिंग तथ्यों में लगता है कि उनमें आंकड़ों का ही माया जाल है और वह सब नजर भी आता है। मान्यवर, पहली बात जो मैं इस मान्य सदन में बताना चाहता हूं कि किस प्रकार से केन्द्र सरकार से बजट आता है and how do we define it? It is a consolidated fund of India और उसमें हम सभी राज्य पूरे देश के अपनाप-अपना हिस्सा जरूर लेते हैं और जहां की जो भी भौगोलिक परिस्थितियां होती हैं, राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक परिस्थितियां होती हैं उनके अनुसार इस consolidated fund of India को हम हर राज्य में खर्च करते हैं। यहां इसके दो घटक बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। एक

रेवेन्यू और दूसरी केपिटल साइड। जब इसका थोड़ा गहन अध्ययन करेंगे और इसकी प्लानिंग और कैलुक्लेशन में जाएंगे तो इस बजट को ध्यान से पढ़ने के बाद लगेगा कि हम डवलपमेंट साइड, जोकि आपका capital expenditure में आता है, वह सिर्फ 29

09.03.2022/1515/बी.एस./एच0के0/-2

प्रतिशत ही अलॉटमेंट में आता है। बाकी का एक बड़ा हिस्सा revenue expenditure में चला जाता है। यह संतुलन कहीं-न-कहीं पूरे स्पेट्रम को डिसटर्व करता है। सभापति महोदय, मेरा यह मानना है कि इस विषय पर माननीय नेता प्रतिपक्ष ने बड़े विस्तार से चर्चा की है और यह भी सुझाया कि हमने वह कौन से कदम उठाए हैं what are our steps for resource generation? क्योंकि

श्री एन0 जी0 द्वारा जारी...

09-03-2022/1520/एच.के.-एन.जी. /1

डॉ0 (कर्नल) धनी राम शांडिल ..... जारी

जब तक आय में वृद्धि नहीं होगी, resource generation management को ध्यान में नहीं रखा जाएगा तब तक मैं समझता हूं कि जी.डी.पी. ग्रोथ 9.2 प्रतिशत हो जाएगी तो ये तर्क से दूर है। सभापति महोदय, इस वैश्विक महामारी का हमारे समाज ने, हमारे देश ने और पूरे विश्व ने सामना किया है। इस महामारी के कारण पूरे विश्व की आर्थिकी नीचे हुई है। जो बहुत एडवांस देश हैं उन्होंने भी इसके दुष्प्रभावों का सामना किया है।

सभापति महोदय, मैं कर्ज को लेकर कहना चाहता हूं। हमारी सरकार के समय में कर्ज का आंकड़ा लगभग 35,000 करोड़ रुपये था। The present Government has taken it to Rs. 75000 crores. जब तक ये सरकार on the way out होगी तब यह आंकड़ा 85,000 करोड़ रुपये को भी पार कर सकता है। यह आर्थिकी की अच्छी स्थिति नहीं है। इसे आर्थिकी की बदहाली भी कहा जा सकता है।

सभापति महोदय, अब मैं कर्मचारियों की बात करना चाहता हूं। यहां पर सभी माननीय सदस्यों ने कहा कि डबल इंजन की सरकार ने जब कर्मचारियों को डील किया और जब उनकी समस्याओं को देखने का समय आया तब उनके हितों को नज़रअंदाज कर दिया गया। मैंने राज्यपाल महोदय के अभिभाषण की चर्चा के दौरान भी कहा था कि आऊटसोर्स कर्मचारियों की एक ही मांग है कि वे इस महंगाई के दौर में अपना घर ठीक प्रकार से नहीं चला पा रहे हैं और उनके लिए एक पॉलिसी बनाई जाए। अब सरकार बहुत सारी भर्तियां आऊटसोर्स आधार पर ही कर रही है। उनकी एक मांग और भी है कि जब भी दैनिक वेतनभोगी का वेतन बढ़े तब उनका भी वेतन बढ़ना चाहिए। They will come some sort of stabilize form. इसी के साथ कुछ कर्मचारी ओ.पी.एस. की भी मांग कर रहे हैं। ओ.पी.एस. की मांग को लेकर विधान सभा परिसर के बाहर आए कर्मचारियों के साथ सौतेला व्यवहार किया गया है। उन पर पानी की बौछारें भी फैंकी गई हैं। जब हम इसकी तुलना धर्मशाला के एपिसोड से करेंगे तो दोनों में बहुत अंतर मिलेगा। वहां पर सुरक्षा के सभी नियमों का कड़ा पालन करते हुए माननीय मुख्य मंत्री जी उनकी बात सुनने बाहर

09-03-2022/1520/एच.के.-एन.जी. /2

तक गए परंतु यहां पर ऐसा नहीं हुआ। मैंने स्वयं देखा है कि वे लोग काफी ठंड में शाम तक बाहर बैठे हुए थे और उनकी हालत भी ठीक नहीं थी। मैं समझता हूं कि यह अच्छी बात नहीं थी। सबसे हैरानी की बात तो यह है कि बजट भाषण में ओ.पी.एस. के लिए एक भी शब्द पढ़ने को नहीं मिला। कर्मचारी वर्ग का हमारे साशन-प्रशासन में और हमारी सरकारों के संचालन में बहुत अहम योगदान होता है। यहां पर अधिकारी दीर्घा में हमारे बहुत ही वरिष्ठ अधिकारीगण बैठे हुए हैं और ये जानते हैं कि कर्मचारियों के बिना कोई भी सरकार आगे नहीं बढ़ सकती। कर्मचारियों के प्रति सरकार का जो रुख देखा गया है उसके लिए मैं कहना चाहता हूं कि इस सरकार ने कर्मचारियों के पक्ष में कदम नहीं उठाए हैं। इसी प्रकार जब करूणामूलक आधार पर नौकरियों की लिस्ट देखी गई तो यह भी एक चिंता का विषय है कि A very huge waiting list is there to be cleared and I feel that our attention

should be towards these people क्योंकि जो कर्मचारी वर्ग इस संसार में नहीं रहे हैं उन्होंने भी अपना योगदान किसी-न-किसी सरकार को चलाने में दिया है। यहां पर हमारे भैया जी बैठे हैं, जहां हमारे माननीय मंत्री,

श्री जे.एस. द्वारा जारी.....

09.03.2022/1525/JS/YK/1

डॉ0 (कर्नल) धनी राम शांडिलः------जारी------

श्री महेन्द्र सिंह जी यहां पर बैठे हैं। मैं स्वयं इनके पास 4 कर्मचारियों को लेकर गया था और इन्होंने वायदा भी किया था कि उनको कहीं-न-कहीं लगा लिया जाएगा। वहां पर उन्होंने 18 महीने काम भी किया। उन्हें न तो वहां पर पे मिली और न ही रखा गया। यह बड़े दुख से कहना पड़ रहा है। बेरोजगारों का आंकड़ा 14 लाख से पार हो गया है। मैंने जो चार लोग इनके पास लाए थे उनको नौकरी नहीं मिली। I am sure Hon'ble Minister, Shri Mahender Singhji will take note of it. भर्तियों में पारदर्शिता होना बहुत जरूरी है। अगर भर्तियों में पारदर्शिता नहीं होगी तो लोग कन्फ्यूज़ करेंगे कि किसी दूसरे तरीके से भर्तियां हो। चोर दरवाजे से भर्तियां हो जाएंगी, जो मैं समझता हूं। यह किसी भी रूप से हमारे हित में नहीं है। मेहरबानी, बेरोजगारी और इस प्रकार का जो यह आलम बना हुआ है, इसमें यह तो बहुत ज्यादा है लेकिन घोषणाओं की भी साथ-साथ में कमी नहीं है। मैं देख रहा था कि छात्र-छात्राओं को लैप टॉप भी नहीं मिले हैं। हैरानी की बात यह है कि पूरे बजट में बढ़ती मंहगाई और बेरोजगारी किस प्रकार से दूर की जाए, इसका यहां पर कोई जिक्र नहीं है। I have not found any word in this entire document that how we will deal with this serious condition. ये सब रिर्सोस जैनरेशन कैसे किए जाएं और हम इससे किस प्रकार से निपट सकें, इसका होना बहुत जरूरी था। यहां पर पर्यटन के बारे में बहुत सी बातें होती हैं। मेरा मानना है कि अभी तक हम पर्यटन का इस नैसर्गिक में ज्यादा दोहन नहीं कर पाये हैं। यहां पर प्रकृति की कितनी ज्यादा महिमा है। माँ प्रकृति का हमें

वरदान है, उसका बहुत कम प्रतिशत हम दोहन कर पाए हैं, ऐसा मेरा मानना है। धार्मिक सांस्कृतिक प्रोग्राम हो, एडवेंचर टूरिज्म हो, हर्बल टूरिज्म हो, ग्रामीण के परिवेश में टूरिज्म हो जिसका दोहन करना अनिवार्य है। वह भी इस बजट में देखने को नहीं मिला।

Chairman: Please, wind up.

09.03.2022/1525/JS/YK/2

डॉ0 (कर्नल) धनी राम शांडिलः समय की मांग है कि हम एक प्रोफैशनल ट्रेनिंग सेन्टर बनाए और टूरिज्म का पूरा दोहन करके बेरोजगार युवकों को कुछ-न-कुछ अच्छे दिन दिखाने की ओर ले जाएं। Law & Order situation is also not very good. Last time we mentioned the number of rape cases and murder. Accidents are increasing in the State. Chairman, Sir, I also want to bring one more point into the notice of Hon'ble Chief Minister, because I was not given opportunity by the Hon'ble Speaker to speak under Rule-62. यह ध्यानाकर्षण मैंने इसलिए लाया था कि नगर निगम, सोलन में हमने कहा था कि 100 रुपये लेंगे जब तक एक उपभोक्ता 12,500 लीटर्ज़ पानी इस्तेमाल करेगा, उसके बाद उसे और लोगों की तरह ही पैसा देना होगा। परन्तु इसको बहुत ही अजीब तरीके से डायरैक्टर साहब ने सस्पैंड कर दिया, जो लोकहित में नहीं है। मेरी मंत्री महोदय से प्रार्थना है कि हमने जो यह काम किया था यह बड़े सोच-समझ करके किया था। बड़े डेलिबरेशन के बाद सोचा था कि पानी के लिए डिसिप्लेन होगा, पानी सबको मिलेगा और लोग प्रेरित होंगे कि हम उतना ही पानी इस्तेमाल करेंगे ताकि ज्यादा वेस्टेज़ न हो। इन सभी बातों को पूरा करने के लिए hoardings towers and various other things हम कैसे रिर्सोस जैनरेट करेंगे। किस प्रकार से नगर निगम को 100 रुपये में पानी देंगे। मुझे ऐसा लगा कि राजनीतिक दबाव में यह काम किया गया है। This is not a very happy situation.

श्री एस.एस. द्वारा जारी----

09.03.2022/1530/SS-YK/1

डॉ0 (कर्नल) धनी राम शांडिल क्रमागत :

Before I conclude, I want to once again say about Police Station Shyari Bungalow.यह पुलिस स्टेशन ब्रिटिश काल से लेकर बहुत अच्छे तरीके से चल रहा था, अब एक पुलिस पोस्ट के रूप में रख दिया। न जाने क्यों ऐसा किया? जबकि श्री संजय कुंडू, डी0जी0पी0 साहब स्वयं मेरे साथ गए। मैं समझता हूं कि he is a very efficient and capable officer. He visited that place with me and he also found that there is need of a Police Station. So before I conclude, Hon'ble Chairman, Sir, I wish Hon'ble Chief Minister will reconsider it. मैं अंत में यही कहूंगा कि सरकार खजाना खाली है। घाटे के इस बजट में लोगों को लुभाने का प्रयास किया गया है। कोरी घोषणाओं को कैसे पूरा किया जाएगा यह भविष्य के गर्भ में छुपा रहेगा। संसाधन और रिसोर्स मैनेजमैंट को हम किस प्रकार से जनरेट करेंगे, इस ओर ध्यान देना होगा। 51365 करोड़ रुपये के इस बजट का मैं किस प्रकार से अनुमोदन करूं, इसी भ्रम में मैं पड़ा हूं। इसलिए मैं आपके इस बजट का समर्थन करने में असमर्थ हूं।

सभापति महोदय, आपका धन्यवाद, जय हिन्द, जय हिमाचल।

09.03.2022/1530/SS-YK/2

कर्नल इन्द्र सिंह, सभापति : अब इस चर्चा में माननीय सदस्य श्री जवाहर ठाकुर जी भाग लेंगे।

श्री जवाहर ठाकुर (दरंग) : सभापति महोदय, श्री जय राम ठाकुर जी की सरकार ने 4 मार्च, 2022 को वित्तीय वर्ष 2022-23 का 51365 करोड़ रुपये का बजट पेश किया है। मैं समझता हूं कि गरीब, मजदूर, महिलाएं, युवा, किसान, बागवान, कर्मचारी, चुने हुए जन प्रतिनिधि, हर क्षेत्र व हर वर्ग के लिए करमुक्त बजट पेश किया है। मैं इसके लिए मुख्य मंत्री जी का धन्यवाद करना चाहता हूं और पूरे प्रदेशवासियों को बधाई देना चाहता हूं।

सभापति महोदय, आर्थिक तौर पर सबसे कमजोर मजदूर होता है जो दिहाड़ी लगाकर अपने परिवार का पालन-पोषण करता है। उसकी बचत न के बराबर होती है। श्री जय राम ठाकुर जी की सरकार ने 50 रुपये की एफ0डी0 शुरू करके आज उन मजदूरों को मासिक 1500 रुपये का लाभ प्रदान किया है। प्रदेश में कोई ऐसा वर्ग नहीं है जो इस बजट से अछूता रहा है। उसमें वॉटर कैरियर, पंचायतों के चौकीदार, पैरा पम्प ऑपरेटर, राजस्व चौकीदार, सिलाई अध्यापिका, मिड डे मील वर्कर, जल रक्षक, आंगनबाड़ी सहायिका, नम्बरदार इत्यादि 10 ऐसी कैटेगिरीज हैं जिनको सीधे 900 रुपये की मासिक बढ़ोतरी हुई है। मैं समझता हूं कि इसमें कई परिवार के लोगों को लाभ मिला है। इसके साथ आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, आशा वर्कर्ज जो गांव-गांव जाकर सरकार की योजनाओं का लाभ हर परिवार तक पहुंचाती हैं उसमें आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को 1700 रुपये और आशा वर्कर को 1825 रुपये का मासिक लाभ होगा। इसके साथ-साथ जो हमारे एस0एम0सी0 के अध्यापक हैं उनके लिए भी 1000 रुपये की बढ़ोतरी करके उनकी सेवा को बहाल रखा है। उसके लिए हम मुख्य मंत्री जी के धन्यवादी हैं।

सभापति महोदय, आज चाहे गांव की बात हो या शहर की बात हो, जितने भी हमारे चुने हुए प्रतिनिधि हैं उनको भी हमारी सरकार ने इस बजट में बहुत बड़ी सौगात दी है। नगर पंचायतों के मेम्बर को 500 रुपये बढ़ोतरी के साथ 3000 रुपया प्रतिमाह मिलेगा। प्रधान, नगर पंचायत को 1000 रुपये की बढ़ोतरी हुई है। साथ में नगर-निगमों में पार्षद से लेकर महापौर के मानदेय भत्ते में 500 रुपये से 3000 रुपये प्रतिमाह की बढ़ोतरी हुई है।

जारी श्रीमती के0एस0

09.03.2022/1535/KS/AG/1

श्री जवाहर ठाकुर जारी----

जिला परिषद सदस्यों, अध्यक्ष व उपाध्यक्षों की 1000 से 3000 रुपये की बढ़ौत्तरी हुई है। आउटसोर्स पर लगे हुए कर्मचारियों को भी हमारी सरकार ने 1500 रुपये मासिक की बढ़ौत्तरी की है मैं समझता हूं कि इससे उपरोक्त सभी वर्गों को बहुत बड़ी सौगात मिली है। इसके अलावा बेरोज़गार नौजवानों को लगभग 30,000 बेरोज़गारों को आने वाले समय में

कहीं न कहीं नौकरी का प्रावधान होगा और प्रदेश की सेवा करने का मौका मिलेगा। मैं समझता हूं कि जय राम जी की सरकार हमेशा गरीब, वृद्ध व महिलाओं और ऐसे वंचित लोग जो अपना जीवन बसर करने में असमर्थ होते हैं, सरकार ने वर्ष 2017 से आज तक ऐसे बहुत से लोगों की मदद की है। खासकर वृद्धावस्था पैंशन के लिए आयु सीमा में छूट दी है। 80 वर्ष से 60 वर्ष किया है और आने वाले समय में 40000 पात्र लोगों को इसका लाभ मिलेगा। इस पैंशन में 1000 से 1500 और 1700 की वृद्धि करना श्री जय राम ठाकुर जी की सरकार ने एक बहुत ही पुण्य का काम किया है जिसके लिए मैं इनका धन्यवाद करना चाहता हूं।

सभापति जी, स्वास्थ्य के क्षेत्र में चाहे हिम केयर व आयुष्मान योजना गरीब मरीज लोगों को वरदान साबित हुई है। हिमकेयर में नए परिवारों का पंजीकरण अब पूरे वर्ष होता रहेगा साथ में नवीनीकरण की अवधि तीन साल बढ़ाई जाएगी। जो यह घोषणा हुई है यह बहुत अच्छा काम किया गया है। गांव में कुछ लोगों को पता नहीं होता था कि हमारा नवीनीकरण कब तक है, ऐसे लोगों को इस योजना का बहुत लाभ मिलेगा। इस योजना से 2 लाख 40 हजार लोगों के निशुल्क इलाज पर 218 करोड़ रुपये सरकार खर्च कर रही है। मैं केन्द्र सरकार का धन्यवाद करना चाहता हूं कि वर्ष 2021-22 में 419 करोड़ रुपये और वर्ष 2022-23 में 848 करोड़ रुपये को मिलाकर 1267 करोड़ रुपये की सहायता इस योजना के माध्यम से प्रदान की है। हमारा प्रदेश पहाड़ी प्रदेश है और

09.03.2022/1535/KS/AG/2

भिन्न-भिन्न भौगोलिक परिस्थितियों में विभिन्न क्षेत्रों में हमारे लोग रहते हैं। मैं मुख्य मंत्री जी का धन्यवाद करना चाहता हूं कि आज एक नई योजना, खासकर दूर-दराज के क्षेत्रों में रहने वाले हमारे लोगों को मुख्य मंत्री मोबाइल क्लीनिक योजना शुरू हुई है, उससे स्वास्थ्य की दृष्टि से हमारे बेसहारा लोगों को बहुत लाभ मिलेगा।

सभापति महोदय, वर्ष 2022-23 में प्रत्येक स्वास्थ्य खंडों में एक मॉडल प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र खोला जाएगा और 50 नई एम्बुलेंस खरीदने का भी प्रावधान किया गया है जिसके लिए 15 करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे। मैं समझता हूं कि 500 नए जो डॉक्टरों के पद भरे जा रहे हैं, जो बहुत सारे नए स्वास्थ्य संस्थान खुले हैं लेकिन डॉक्टरों की वजह से दूर-दराज के स्वास्थ्य संस्थान रिक्त चल रहे हैं, उसके लिए भी मुख्य मंत्री जी का धन्यवाद करते हैं कि वर्ष 2022-23 में 2772 करोड़ रुपये के बजट का प्रावधान किया है।

मुख्य मंत्री रोशनी योजना के माध्यम से 12765 गरीब परिवार ऐसे हैं जिनको आने वाले समय में निशुल्क बिजली प्रदान की जाएगी। इस योजना के अंतर्गत वर्ष 2022-23 में 5000 परिवारों को कनैक्शन दिए जाएंगे। मैं समझता हूं कि 1 अप्रैल, 2022 से गरीब परिवारों को 60 युनिट तक ज़ीरो बिल आने वाला है। इसके साथ 61-125 युनिट तक 1 रुपये प्रति युनिट की दर से बिजली का बिल देना पड़ेगा। मैं समझता हूं कि यह भी एक बड़ी सौगात गरीबों को मिली है।

श्रीमती अ0व0 द्वारा जारी...

09.03.2022/1540/av/as/1

जवाहर ठाकुर-----जारी

मेरे निर्वाचन क्षेत्र में ज्यादातर लोग कृषि से जुड़े हुए हैं। इस बजट के अनुसार किसानों को अपनी खेती-बाड़ी में इस्तेमाल होने वाली बिजली के लिए 30 पैसे प्रति यूनिट के हिसाब से बिल आएगा, यह हमारी सरकार द्वारा एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया गया है। इसी तरह से जल जीवन मिशन के अंतर्गत प्रदेश में 8.35 लाख नल के कनेक्शन दिए हैं। उसके बाद माह जनवरी, 2022 तक 17.28 लाख नल के कनेक्शन दे दिए जाएंगे और वर्ष 2022 के अंत तक प्रदेश के सभी परिवारों को पेयजल कनेक्शन दिए जाएंगे। इस योजना के अंतर्गत 1500 करोड़ रुपये की राशि व्यय की जाएगी। इस योजना को सफलतापूर्वक चलाने के लिए हिमाचल प्रदेश को पूरे भारतवर्ष में प्रथम स्थान मिला है। मैं इसके लिए मुख्य मंत्री जी

और जल शक्ति मंत्री जी को बधाई देना चाहता हूं। प्रदेश में जल शक्ति विभाग के अंतर्गत सिंचाई योजनाओं के लिए वित्तीय वर्ष 2022-23 में 2,772 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। इसी तरह से प्रदेश में सड़कों के निर्माण और उनके रख-रखाव हेतु लोक निर्माण विभाग के अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2022-23 में 4,373 करोड़ रुपये व्यय किए जाएंगे। इसके कारण आने वाले समय में 20 पंचायतों के अंतर्गत 80 गांवों को इस योजना से लाभ प्राप्त होगा। इसके अतिरिक्त, एच0आर0टी0सी0 के बेड़े में 220 नई बसें जोड़ने का लक्ष्य रखा गया है जिसमें इलैक्ट्रोनिक बसिज भी शामिल होंगी। इन बसों के चलने से प्रदेश के दूर-दराज के क्षेत्रों के लोगों को बहुत लाभ मिलेगा। हमें पर्यटन की दृष्टि से भी बहुत बड़ी सौगात मिली है। इसके अतिरिक्त, गृहिणी सुविधा योजना को आगे भी चालू रखने के साथ-साथ इसके अंतर्गत अब तीन निःशुल्क गैस सिलेंडर देने का प्रावधान किया गया है। शिक्षा के क्षेत्र में बच्चों को गुणवत्ता पूर्ण शिक्षा प्रदान करने के लिए 8,422 करोड़ रुपये खर्च करने का लक्ष्य रखा गया है। मैं यहां पर कृषि और बागवानी क्षेत्र की बात भी करना चाहूंगा और खासकर जैविक खेती के बारे में क्योंकि इस बार के बजट में इसके लिए 583 करोड़ रुपये की राशि का प्रावधान किया गया है

09.03.2022/1540/av/as/2

और मैं इसके लिए मुख्य मंत्री जी का धन्यवाद करना चाहता हूं। मुझे इस बात की खुशी है कि जब-जब भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार चाहे केंद्र में आई या प्रदेश में बनती है; हमारी पार्टी की सरकार हमेशा ही जन-कल्याण की योजनाएं लाती हैं और उनका लोगों तक लाभ पहुंचता है। मैं समझता हूं कि इस देश और हमारे प्रदेश में गरीब जनता का कल्याण तभी होता है जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार सत्ता में आती है। हमारे स्वर्गीय प्रधान मंत्री श्री राजीव गांधी जी ने एक बार कहा था कि हम केंद्र से किसी योजना के लिए अगर 1 रुपया भेजते हैं तो उसमें से गांव तक केवल 15 पैसे पहुंचते हैं। इनकी सरकार के समय में ऐसा होता होगा परंतु जब से केंद्र में माननीय श्री नरेन्द्र मोदी की सरकार बनी है तब से यदि 10 पैसे भी भेजते हैं तो वह सीधे हमारे गांवों तक पहुंचते हैं। हम इसके लिए माननीय प्रधान मंत्री का धन्यवाद करना चाहते हैं। मैं यहां यह भी कहना

चाहता हूं कि पूर्व में रहे प्रधान मंत्री स्वर्गीय श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी के भी हिमाचल प्रदेश से अच्छे संबंध थें और अब वर्तमान प्रधान मंत्री श्री नरेन्द्र मोदी का भी हमारे प्रदेश से विशेष लगाव है। हिमाचल प्रदेश में श्री नरेन्द्र मोदी जी एक बार नहीं बल्कि कई बार आ चुके हैं। मैं यहां यह भी कहना चाहता हूं कि पिछले 10 वर्षों तक लगातार आदरणीय श्री मनमोहन सिंह देश के प्रधान मंत्री रहें, परंतु मैं समझता हूं कि उनको तो पता भी नहीं होगा कि हिमाचल प्रदेश भी कोई स्टेट है। हमने उनको कभी हिमाचल प्रदेश आते नहीं देखा और न ही उन्होंने हमारे राज्य को कोई ऐसा तोहफा दिया जिसकी वजह से हम उन्हें याद करें। हमारी सरकार का नारा 'सबका साथ, सबका विकास' है जिसकी वजह से आज हम आगे बढ़ रहे हैं। हमें आज इस बात की खुशी है कि दिल्ली में एक बहुत बड़ा पॉवर ग्रिड है और आदरणीय श्री नरेन्द्र मोदी जी उसका वहां से संचालन कर रहे हैं। उसी तरह से यहां हिमाचल प्रदेश में उस पॉवर ग्रिड का संचालन श्री जय राम ठाकुर कर रहे हैं। पॉवर ग्रिड से गांवों तक बिजली पहुंचाने का कार्य 33 के0वी0 के स्टेशन करते हैं और हम विधायक रूपी स्टेशन उस पॉवर को प्रदेश के गांव-गांव तक पहुंचा रहे हैं। मैं इस सदन की कार्यवाही को वर्ष 1977 से देख रहा हूं। मैंने ऊपर दर्शक दीर्घा से कई बार इस माननीय सदन की कार्यवाही देखी है। जब ठाकुर सेन नेगी जी अध्यक्ष हुआ करते थे तो मैंने उस दौरान भी कई बार इस सदन की कार्यवाही देखी है।

टी सी द्वारा जारी

09/03/2022/1545/टी0सी0वी0/ए0एस0/1

श्री जवाहर ठाकुर... जारी

उस समय के सत्र में और आज के सत्र में बहुत अंतर है। आज तो ऐसा लगता है जैसे हम कहीं दंगल में बैठे हैं। मैं मुख्य मंत्री जी का धन्यवाद करना चाहता हूं कि जब पिछली सरकार के समय में हम गांव से आते थे, रातभर हम बसों में सफ़र करते थे और मुख्य मंत्री से मिलने के लिए सचिवालय में लाइन में खड़े रहना पड़ता था। आज ओक ओवर, विधान सभा और सचिवालय में गरीब लोगों के लिए बैठने का इंतजाम है। विधान सभा के बाहर भी जब लोगों को पासिज नहीं मिलते थे तो उनको कई-कई घंटों खड़े रहना पड़ता था लेकिन अब यहां पर भी लोगों को बैठने की व्यवस्था की गई है। यहां पर जिक्र किया गया कि जो उपचुनाव हुए उसमें हमने चार सीटें जीती हैं। मैं यह कहना चाहूंगा कि इस उपचुनाव में स्वर्गीय श्री वीरभद्र सिंह जी के नाम पर श्रद्धाजंलि का आखिरी वोट जनता ने मण्डी

संसदीय सीट के लिए दिया है। प्रदेश में जो और भी सीटें जीती हैं, उनको भी श्रद्धांजलि का वोट मिला है। इनको इस पर ज्यादा खुश नहीं होना चाहिए। श्री जय राम ठाकुर जी ने जो बजट पेश किया है, वह एक ऐतिहासिक बजट है। मैं इस विधान सभा में पहली बार आया हूं लेकिन मैं पंचायत का मैंबर रहने के बाद प्रधान और जिला परिषद का सदस्य भी रहा हूं। राजनीति का मुझे पहले से अनुभव है। यह पहला ऐसा बजट है जिससे आम आदमी को लाभ मिलेगा। मैं एक बात जरूर कहना चाहता हूं कि यहां पर स्टिरिंग श्री मुकेश अग्निहोत्री जी के पास है लेकिन बाहर जाकर श्री सुखविन्द्र सिंह सुक्खु जी और श्री जगत सिंह नेगी जी इनके टायर की हवा निकालते हैं। मैं इनको एक सुझाव देना चाहूंगा कि मण्डी में वर्ष 1977 मॉडल के बहुत बड़े नेता हैं, उनको आगे करके अपनी नैया पा लगाने का प्रयास करें। आने वाले समय में ऐसा विपक्ष और बने और श्री जय राम जी की सरकार को विकास के कार्य करने का मौका मिले।

सभापति महोदय, आपने मुझे बोलने के लिए समय दिया, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।

सभापति : माननीय सदस्य, धन्यवाद। अब इस चर्चा में माननीय सदस्य, श्री अनिरुद्ध सिंह जी भाग लेंगे।

09/03/2022/1545/टी0सी0वी0/ए0एस0/2

श्री अनिरुद्ध सिंह, कसुम्पटी : सभापति महोदय, आपने मुझे वर्ष 2022-23 के बजट पर बोलने का मौका दिया, आपका धन्यवाद। मैं आपके माध्यम से सरकार और हिमाचल प्रदेश की जनता को बताना चाहूंगा कि यह जो बजट है यह सिर्फ आईवॉश है। इसमें जो 8.3 प्रतिशत की अनुमानित बृद्धि बताई गई है, यह सिर्फ फिगर्ज को मैन्यूप्लेट करने वाली बात है। बजट में आंगनबाड़ी और पंचायती राज संस्थाओं के प्रतिनिधियों के कुछेक मानदेय बढ़ाये गये हैं। इसके अलावा इस बजट में कोई ऐसी बात नहीं है जिससे लोगों को फायदा मिल सकें। मैं कुछेक सुझाव देना चाहूंगा और मुख्य मंत्री जी से आग्रह करना चाहूंगा कि इनको बजट में इनक्लूड किया जाए। जिस तरह से विधायकों को नाबार्ड में रोपवे के लिए इनक्लूड किया गया है उसी तरह से सीवरेज कनैक्टिविटी भी विधायकों के लिए अलॉउड की जानी चाहिए। कुछेक ग्रामीण क्षेत्र ऐसे जहां सीवरेज कनैक्टिविटीज का कोई प्रावधान नहीं है। वे न तो टी0सी0पी0 में आते हैं और न ही कोई शहर है लेकिन वहां पर घनी

आबादी है। 'शहदी द्वार' के लिए विधायक अपने विधायक क्षेत्र विकास निधि से फंड दे सकेंगे। यह बहुत अच्छी बात है और इसकी हम सराहना भी करेंगे।

एन0एस0 द्वारा जारी ...

09-03-2022/1550/NS/AS/1

श्री अनिरूद्ध सिंह .....जारी

हर विधान सभा क्षेत्र में विधायक को अपने फंड से गेट बनाने की अनुमति होनी चाहिए। मैं विभागवार आऊंगा क्योंकि डिपार्टमेंट के हिसाब से मुख्य मंत्री जी और सदन के सामने सच्चाई रखना बहुत जरूरी है। सभापति महोदय, मैं एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट की बात करना चाहूंगा। यहां पर इसके लिए लंबा-चौड़ा भाषण दिया गया कि एग्रीकल्चर और होर्टिकल्चर डिपार्टमैंट में हमने यह काम किया है। मैं कहना चाहता हूं मुख्य मंत्री जी यह काम ग्राउंड में जीरो है। स्कीमज़ अवलेबल हैं पर इसके लिए एक ही साल होता है। मैं यहां पर मशोबरा ब्लॉक की बात करूंगा और वहां पर फाइल्ज ही आगे नहीं भेजी जाती हैं। वे अपने पास रखते हैं और बोलते हैं कि अभी बजट ही नहीं है। बजट तो सरकार ने उपलब्ध करवाना है आप फाइल्ज तो आगे कीजिए। इसके ऊपर जरूर चैक होना चाहिए। अगर अधिकारी अपने पास ही फाइल दबा कर रखेंगे तो यह उचित नहीं है।

सभापति महोदय, मेरे क्षेत्र में सब्जी मंडी, थरमटी कैंची फागू के समीप है। पिछली सरकार के समय में ही इस सब्जी मंडी का एफ0सी0ए0 हो गया था, पैसे अवलेबल थे और टैंडर बाद में लगाया गया था लेकिन यह आज तक नहीं खुली। इसके टैंडर हो गए थे,कटिंग कर दी, ऊपर से लैंडस्लाइड हुआ पेड़ गिर गए लेकिन अभी तक नहीं खुली। आप इसके ऊपर जरूर ध्यान दें। मैं मशोबरा ब्लॉक और टूटू ब्लॉक के बसंतपुर की बात करना चाहूंगा। पिछले वित्तीय वर्ष में होर्टिकल्चर में एक भी कैंची और अन्य उपकरण जैसे सीढ़ियां आदि नहीं मिली हैं। मुझे आशा है कि मंत्री जी इसके ऊपर चिंता व्यक्त करेंगे और ध्यान देंगें।

सभापति महोदय, अब मैं खाद की बात करूंगा। खाद डालने का सीजन अब निकल चुका है। खाद के रेट बढ़ चुके हैं। 12:32:16 खाद पहले 1400 रुपये बोरी थी अब 1700 रुपये की बोरी हो गई है। अभी तक खाद ब्लॉक्स, हिमफैड और सोसायटीज में उपलब्ध नहीं है। आप इसके ऊपर जरूर ध्यान दें।

सभापति महोदय, सीजन निकल जाता है और ब्लॉक्स के पास एच0डी0 बी0 सेब के पौधे और अन्य पौधे बाद में पहुंचते हैं। ये पौधे समय रहते ब्लॉक्स में आने चाहिए ताकि बागवान इनका फायदा उठा सकें। जो पौधे आते भी हैं उनको खुले में रखा जाता

09-03-2022/1550/NS/AS/2

है। इसके लिए एक व्यवस्था बनाई जाए कि जब नर्सरीज़ से ये पौधे आएं तो ब्लॉक्स में इन पौधों को दबाया जाए, पानी डाला जाए ताकि ये सूखने से बच जाएं। मैं कहना चाहूंगा कि ये नर्सरीज़ श्री वीरभद्र सिंह जी और परमार साहब के समय से बनी हुई हैं और अच्छा काम कर रही हैं। सभापति महोदय, मैं बड़ी प्रेक्टिकल सी बात कर रहा हूं। सेल ऑफ प्लांट्स सबसे पहले क्लस्टर को दिए जाते हैं और फिर ब्लॉक्स की रिक्वायरमैंट के लिए कहा जाता है तब जा करके ओपन सेल में लगते हैं। मैं हाल ही में बजौरा की नर्सरी में जाकर आया हूं। यह बहुत अच्छी नर्सरी है और वहां पर स्टॉफ भी बहुत अच्छा काम कर रहा है। मैंने उनसे पूछा कि वे किस तरह से काम कर रहे हैं? उन्होंने बताया कि सबसे पहले क्लस्टर को पौधे जाते हैं और फिर ब्लॉक्स को जाते हैं। मैंने ब्लॉक्स के हाल आपको बता दिए हैं वहां पर पौधे दबाने के लिए जगह नहीं है। जितने भी हमारे HDEO's लगे हैं और ये वैज्ञानिक हैं लेकिन आज ये दवाइयां और बीज बेचने और फाइलों को फॉरवर्ड करने का काम कर रहे हैं। उनके पास फील्ड में जाने का समय ही नहीं है। इसके अतिरिक्त जो Subject Matter Specialist (SMS) उसको अपना विषय ही भूल गया है और वह दूसरी लाइन पकड़ चुका है। सरकार इसके ऊपर जरूर ध्यान दे। प्लांट्स के लिए ये open to all होना चाहिए और पहले आओ और पहले पाओ के आधार पर होना चाहिए। लगभग अढ़ाई लाख प्लांट्स एक नर्सरी में बेचे जा रहे हैं और अच्छे पौधे हैं। इसके ऊपर जरूर ध्यान दें।

मैं पंचायती राज और रूरल डवलपमैंट की बात करूंगा

श्री आर0 के0 एस0 द्वारा जारी।

श्री बी0 एस0 द्वारा जारी।

09.03.2022/1555/RKS/डीसी-1

श्री अनिरूद्ध सिंह... जारी

मनरेगा वर्कर्स की अभी भी बहुत पेमेंट लंबित है। माननीय मुख्य मंत्री ने अगले बजट के लिए मनरेगा की दिहाड़ी बढ़ाई है लेकिन जो उनकी पिछली पेमेंट पेंडिंग है उसका क्या होगा? तकरीबन 200 करोड़ रुपये की पेमेंट देना देना अभी भी शेष है। मेरा आग्रह है कि लोगों की पिछली पेमेंट जल्द-से-जल्द दी जाए। जो हम पंचायतों से मनरेगा की स्कीम्ज मांग रहे हैं, उन्हें हम गिनती में मांग रहे हैं। क्योंकि मनरेगा एक स्कीम नहीं है, मनरेगा रोज़गार देने का एक्ट है। हम यह नहीं कह सकते कि हम एक पंचायत में एक आदमी को 10 या 15 दिन काम देंगे। मुझे मालूम है कि कुछ क्षेत्रों में लोग मनरेगा के तहत काम नहीं करते। वे मस्ट्रोल में तो अपना नाम लिखवा देते हैं लेकिन अपना काम गोरखों से करवाते हैं। ऐसा हर जगह होता है। लेकिन मेरा मानना है कि पात्र व्यक्ति को ही काम मिलना चाहिए। अगर हम शिक्षा की बात करें तो मैं जानना चाहूंगा कि गत चार वर्षों में कितने स्कूल अपग्रेड हुए हैं? जो भवन सही हालत में नहीं हैं उनकी मरम्मत के लिए कितनी धनराशि दी गई? धाल स्कूल में जब बच्चे लंच कर रहे थे तो उस बिल्डिंग का एक पोल उसी समय नीचे गिर गया। उस स्कूल की छत पहले ही गिर चुकी है। इस पर ध्यान देने की आवश्यकता है। जो अनसेफ बिल्डिंग्स हैं उनकी समय पर इंस्पेक्शन नहीं की जाती जबकि यह कार्य प्राथमिकता में होना चाहिए। इनकी रिपोर्ट समय में प्रस्तुत होनी चाहिए। मेरे विधान सभा के प्रश्न में उत्तर दिया गया था कि कोटी कॉलेज के भवन निर्माण के लिए 3 करोड़ की राशि पहले दी गई है और अभी और राशि का प्रावधान किया जा रहा है। लेकिन मैं पूछना चाहूंगा कि उस कॉलेज का काम क्यों नहीं शुरू हो रहा है? बच्चे शैड में बैठकर कक्षाएं लगा रहे हैं, सरकार को इस पर जरूर ध्यान देना चाहिए। यह बजट अगले वित्तीय वर्ष के लिए है लेकिन हम पिछले बजट के कार्यों को क्यों छोड़ रहे हैं? जो आपने पिछले बजट में लोगों के लिए घोषणाएं की हैं, उनके बारे में आपको जरूर पढ़ना चाहिए। क्यार-कोटि, चैड़ी, मशोबरा, जुनगा, बलदयां व पीरन स्कूल के भवन भी अनसेफ घोषित किए हैं। मेरा आग्रह है कि इन

09.03.2022/1555/RKS/डीसी-2

स्कूलों के जीर्णोद्धार के लिए भी फंड्स दिए जाएं। कसुम्पटी में प्राइमरी स्कूल को अनसेफ घोषित करने के बाद गिरा दिया गया था। इस स्कूल के साथ राजस्व विभाग की भूमि भी लगती थी। इन दोंनों विभागों की जमीन में अब एक शोपिंग कॉम्पलैक्स बना दिया गया है

जोकि उचित नहीं है। अगर आप उस स्थान में पार्किंग की व्यवस्था करते तो इससे लोगों को सुविधा मिल सकती थी। दुकानें बनाने से बिजनैसमैन्स के अलावा किसी को फायदा नहीं हो रहा है। मैंने मलयाणा में कॉलेज खोलने का आग्रह किया है। वहां पर कॉलेज खोलने के लिए 25 बीघा भूमि भी उपलब्ध है। आपने आज तक कितनी पी.एच.सीज. को अपग्रेड किया है? आई.जी.एम.सी. में मशीनरी तो उपलब्ध हैं लेकिन उनको ओप्रेट करने वाले तकनीशियन उपलब्ध नहीं हैं। कुछ करोड़ों की मशीनें धूल फांक रही हैं। दवाई के अभाव में ये मशीन नहीं चलाई जा रही हैं। जब मैंने उनसे पूछा तो यह कहा गया कि यह महंगी दवाई है और इसकी एक डोज 30,000 रुपये की आती है। इस मशीन को चलाने वाले तकनीशियन भी नहीं है। हमारे पूरे प्रदेश में पी.एच.सीज और सी.एच.सीज. में क्या सुविधाएं हैं? आई.जी.एम.सी. फेज-II जो चमयाना और सुराला में बनाया गया है, वह कब शुरू होगा? आई.जी.एम.सी., शिमला में ओ.पी.डी. का बहुत बड़ा ब्लॉक बना दिया गया है।

श्री बी.एस. द्वारा... जारी

09.03.2022/1600/बी.एस./डी0सी0/-1

श्री अनिरुद्ध सिंह जारी...

वह भी अब शुरू होने वाला है, कृपया देर न करें उसे दो-तीन महीनों में शुरू करें। वहां एक बैड के ऊपर चार-चार लोगों को सुलाया जा रहा है और मरीज कोरिडोर में सो रहे हैं। वहां पर जब कोई मंत्री या मुख्य मंत्री जाता है तो सफाई करके उन्हें सब कुछ अच्छा ही दिखाया जाता है। आप लोक सब कुछ जानते है कि सच्चाई क्या है आप भी विधायक से मंत्री बने हैं और आई0जी0एम0सी0 फैज-II के लिए हमने ऑल्टरानेट रोड की बात की है, आज वहां पर इतना ट्रेफिक रहता है कि आप भट्ठाकुफर चौक से अन्दर नहीं आ सकते। एन0एच0 जब आएगा तब आएगा, मुख्य मंत्री जी ने जवाब दिया था कि कैथली घाट से फोर नेल का कार्य आरंभ हो रहा है, परंतु वह कब शुरू होगा, उसके टैंडर कब होंगे? अभी तो उसमें land acquisition और हो रही है। उस पर पूरा काम नहीं हुआ है। मैंने मुख्य

मंत्री जी से निवेदन करना चाहता हूं कि आपने तो आई0जी0एम0सी0 के डॉक्टर्ज को कटघरे में खड़ा कर दिया है।

मुख्य मंत्री : किन कारणों से?

श्री अनुरुद्ध सिंह : अखबारों के माध्यम से पता चला है कि मुख्य मंत्री जी को इंजेक्शन से रिएक्शन हो गया था। । can show you,यह सब पेपर में है। एक मुख्य मंत्री को आई0जी0एम0सी0 के इंजेक्शन से रिएक्शन हो रहा है तो डॉक्टर्ज के ऊपर क्या कार्रवाई हुई है? या इंजेक्शन बनाने वालों के ऊपर क्या कार्रवाई हुई है? अब आप एम्ज, दिल्ली चेकअप के लिए जा रहे हैं। इससे हमारे प्रदेश के ऊपर एक प्रश्न उठता है, मैं किसी की आलोचना नहीं कर रहा हूं, अगर इस प्रकार से कुछ होगा तो लोग हम से प्रश्न पूछेंगे कि मुख्य मंत्री जी खुद दिल्ली जा करके इलाज करवा रहे हैं क्योंकि उन्हें रिएक्शन हो गया था। आप अंदाजा लगाइए कि आम आदमी का क्या हाल होगा?

सभापति : माननीय सदस्य कृपया अपनी बात समाप्त करें।

09.03.2022/1600/बी.एस./डी0सी0/-2

श्री अनिरुद्ध सिंह : मैं जल शक्ति विभाग की बात करूंगा, इसमें 7-8 पाइपें परिवार वाइज दी जा रही है। जिन लोगों के लिए फोन जा रहे हैं उनके लिए एक किलामीटर तक की लाइन भी बिछाई जा रही है। मैं यह भी नहीं बोलूंगा कि अधिकारी काम नहीं कर रहे हैं। इस पर अवश्य चैक होना चाहिए। मशोबरा में एक सिवरेज प्लांट है, माननीय भारद्वाज जी उसका शिलान्यास करके आए हैं। वहां अभी तक काम नहीं हुआ है। पंथाघाटी में काम चला हुआ है परंतु मेन काम उसका भी शुरू नहीं हो पाया है।

मैं लोक निर्माण विभाग की बात करूंगा, जो ब्लैक स्पोट्स हैं, उन्हे बढ़ाया जाए, ऐसा नहीं है कि इन पर काम नहीं हो रहा है, ये लग रहे हैं और हर सरकार में यह लगते हैं और बजट का प्रावधान भी होता है। जो नए क्रैश बेरियर नाहन में टैस्टिंग के लिए लगवा रहे हैं, आप उन्हें कम-से-कम शिमला शहर के नजदीक जरूर लगवाएं। जब सरकार बनी थी तो आपने 64 एन0एच0 रोड की बात की थी। आज वे रोड कहां है? इन्हें हम सपने में ही देख सकते हैं। उस वक्त इन रोड्ज की बड़ी-बड़ी बातें की गई थी। इसके ऊपर आप जरूर

ध्यान दें because these are important roads. हम हो हल्ला कर लेते हैं परंतु काम नहीं होता है और Annual Maintance Plan(AMP) हर चुनाव क्षेत्र के लिए होता है उसे बढ़ाना चाहिए यह बहुत कम है। मैंने पहले भी बोला था कि आप ए0एम0पी0 में हम एक-दो-दो किलोमीटर सड़कों को ले रहे हैं। जब तक वह ठीक होती है तो आगे वाली खराब हो जाती है। अगर सड़क की लम्बई पांच किलामीटर की है तो वह पूरी-की-पूरी तैयार होनी चाहिए। आज सड़कों की हालत ठीक नहीं है, पहले हम ऊपरी शिमला की बात करते थे कि वहां की सड़के ठीक नहीं है, परंतु शिमला सर्कुलर रोड़ की बात करें तो ठीक हालत नहीं है।

सभापति : माननीय सदस्य कृपया समाप्त करें।

श्री अनिरुद्ध सिंह : अगर हम पर्यटन की बात करें, तो इसकी हालत बहुत खराब हो चुकी है। इसका कारण यह है कि वह आपके पास है, आप इतने व्यस्त हैं कि उसके लिए समय ही नहीं दे पा रहे हैं। मैंने पहले भी कहा था कि आप इसे किसी अन्य मंत्री को दे दें। जो भी मुख्य मंत्री आता है, वह इस विभाग को अपने पास ही रखता है, मैं आपकी ही बात नहीं करता हूं, क्यों इसे अपने पास रखते हैं? इसका पता नहीं है। यह विभाग अगल से किसी के पास होना चाहिए।

श्री एन0 जी0 द्वारा जारी...

09-03-2022/1605/एच.के.-एन.जी. /1

श्री अनिरूद्ध सिंह..... जारी

अभी आपने ढ़ली हैलीपोर्ट का उद्घाटन किया और यह बहुत अच्छी बात है। इसका एफ.सी.ए. केस चार वर्ष पूर्व हो गया था और उस समय इसमें 7 करोड़ रुपये भी जारी हुए थे। उसके बाद इस सरकार ने भी इसके लिए धन का प्रावधान किया है। आज वह पूर्ण हो गया और यह बहुत अच्छी बात है। लेकिन इसमें फलाइट्स कैसे लैंड करेंगी उस पर कोई काम नहीं हुआ है। कहा जाता है कि हवाई चप्पल वाला भी हवाई जहाज में बैठ सकेगा लेकिन वहां पर उड़ान योजना के तहत केवल 2 सीटों का ही प्रावधान है। वहां पर रेगुलर

फलाइट्स के बारे में भी ध्यान दिया जाए। नोर्थ-ईस्ट में सरकार लोगों को फलाइट बुकिंग में सब्सिडी देती है उसी प्रकार यहां पर भी लोगों को सब्सिडी दी जानी चाहिए।

सभापति : माननीय सदस्य कृपया वाइंडअप कर दीजिए।

श्री अनिरूद्ध सिंह : सभापति महोदय, हर सरकार अपने हिसाब से बजट प्रस्तुत करती है। लेकिन इस बजट में करूणामूलक आधार पर नौकरी देने की कोई बात नहीं की गई है और उनकी पॉलिसी की भी कोई बात नहीं की गई है। ओल्ड पैंशन स्कीम देने की कोई बात नहीं की गई है। आऊटसोर्स कर्मचारियों को क्या लाभ देंगे उस पर भी कोई बात नहीं की गई है। पुलिस के जवानों को क्या देंगे उस पर भी कोई बात नहीं की गई है। वोकेशनल अध्यापकों के लिए कोई बात नहीं की गई है। इसके अलावा हमारे प्रैस के लोगों के लिए भी कोई बात नहीं की गई है। रात को 2 बजे भी कहीं पर कोई घटना हो जाए तो प्रैस के लोगों को वहां पर आना पड़ता है। पूर्व की सरकारें भी उन्हें समय-समय पर विभिन्न लाभ देती रही हैं लेकिन इस बजट में इनके लिए कोई बात नहीं की गई है। Administration of the Government is a total failure. यह क्यों है, इस पर आपको सोच-विचार करना होगा। It is a total failure. आज कोई भी कर्मचारी कार्यालायों में नहीं बैठता है और काम नहीं करना चाहता हैं।

09-03-2022/1605/एच.के.-एन.जी. /2

आज सुबह मुख्य सचिव महोदय को तो एक ऑर्डर इश्यू करना पड़ गया है क्योंकि अधिकारी विधान सभा में ही नहीं बैठ रहे हैं। आपको इस पर गहनता से चिंतन करना होगा। यह एक चुनावी वर्ष है और इस बजट में केवल मानदेय बढ़ाया गया है इसके अलावा लोगों को इस बजट का कुछ भी लाभ नहीं होने वाला है। सभापति महोदय, आपने मुझे बोलने का मौका दिया आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।

09-03-2022/1605/एच.के.-एन.जी. /3

सभापति : अब इस चर्चा में माननीय सदस्य श्री राजे ठाकुर जी भाग लेंगे।

श्री राजेश ठाकुर (गगरेट) : सभापति महोदय, आपने मुझे बजट पर चर्चा करने के लिए बोलने का समय दिया, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। माननीय मुख्य मंत्री श्री जय राम ठाकुर जी ने इस माननीय सदन में अपना 5वां बजट पेश किया है। मुझे याद है कि जब हम नए-नए विधायक बन कर आए थे तब माननीय मुख्य मंत्री जी का पहला बजट आया था। पहले बजट में हम सीखने वाले थे, यहां पर सारे माननीय विधायक बैठे हुए थे और विपक्ष के नेता माननीय श्री मुकेश अग्निहोत्री जी ने एक बात कही थी कि माननीय मुख्य मंत्री जी का स्टेरिंग किसी और के पास है, गेयर किसी और के पास है और अन्य बातों को लेकर भी इस माननीय सदन में चर्चा हुई थी।

(अध्यक्ष महोदय पदासीन हुए।)

अध्यक्ष महोदय, माननीय मुख्य मंत्री जी के चार साल की बेहतरीन कारगुजारियों से चारोंखाने चित हुए विपक्ष की हालत और सरकार की ताकत का अंदाजा इस 5वें बजट से पता चल जाता है। यहां मुद्दों पर चर्चा न करके अंदर व बाहर की चर्चा होती रही। अभी रविवार के दिन माननीय मुख्य मंत्री जी ने सभी 68 विधान सभा क्षेत्रों में वर्चुअल बैठक करके जनता को सम्बोधित किया और उन्हें बजट के बारे में विस्तार से बताया। उस बैठक के माध्यम से पता चलता है कि जनता ने माननीय मुख्य मंत्री जी के इस बजट को किस प्रकार से सराहा है। जनता ने माननीय मुख्य मंत्री जी के लिए दुआएं दी हैं। वहां पर चाहे आंगनवाड़ी कार्यकर्त्ता हो, मिनि आंगनवाड़ी कार्यकर्त्ता हो, आंगनवाड़ी सहायिका हो, आशा वर्कर्ज़ हो, पंचायत चौकीदार हो, सिलाई अध्यापिका हो, मिड-डे-मील वर्कर्ज़ हो, वाटर कैरियर हो, जल रक्षक हो, Multi Purpose Workers हो, पैरा फिटर या पम्प ऑपरेटर हो, राजस्व चौकीदार हो या नम्बरदार हो या दिहाड़ीदारों हो। अनेकों लोग वहां पर ऐसे आए हुए थे जिनको बुलाया ही नहीं गया था।

09-03-2022/1605/एच.के.-एन.जी. /4

मुझे प्रदेश के किसी भी सोशल मीडिया या अख़बारों में दिखा दीजिए जहां पर 100-200 लोग इक्कठा होकर कह रहे हों कि श्री जय राम ठाकुर जी का बजट अच्छा नहीं है। हर व्यक्ति ने यह कहा है कि श्री जय राम ठाकुर जी ने अपनी सरकार का अंतिम बजट ऐसा दिया है जो हिमाचल प्रदेश को उम्मीद ही नहीं थी। इस बजट के कारण विपक्ष के लोगों को नजर आ रहा है कि उनका आने वाला समय ठीक नहीं है।

श्री जे.एस. द्वारा जारी.....

09.03.2022/1610/JS/YK/1

श्री राजेश ठाकुरः----**जारी**----

तो उस पर मैं एक बात बताना चाहता हूं, ये भी हमारे साथी हैं, हमें तो इनसे सीखना है। इन्होंने भी 10 मार्च 2017 में पिछली सरकार में एक बजट की घोषणा की थी, वह इनका 5वां बजट था। उसमें सिलाई अध्यापिका की पात्रता को देखते हुए प्रोमोशन दी जाएगी,जो कि पेज नम्बर 63 में है। आपने कुछ नहीं किया। परन्तु हमारी सरकार ने उनके लिए मानदेय भी बढ़ाया और 20 परसेंट प्रोमोशन कोटा दे करके पंचायत सेक्रेटरी बनाने का काम किया है। ये सिलाई अध्यापिका के लिए हमारी सरकार की उपलब्धि है। कर्मचारियों की एक मास के अन्दर संचित निधि बढ़ाई जाएगी। इनके बजट में कोई नीति नहीं बनी लेकिन हमारी सरकार ने तीन मैम्बर्ज की कमेटी मंत्रि-मंडल में जल शक्ति मंत्री जी की अध्यक्षता में बनाई है। माननीय महेन्द्र सिंह ठाकुर जी उस कमेटी के अध्यक्ष हैं। आउटसोर्स के लिए हमारी सरकार ने काम किया है। अनुबन्ध कर्मचारियों का पिछली सरकार में जिनका 5 वर्ष का कार्यकाल था लेकिन हमारी सरकार ने उसको घटा कर दो वर्ष का किया। हमारी सरकार की उपलब्धियां बहुत हैं। इनका पता तब चलता है जब हम फील्ड में जाते हैं। हमारी डबल इंजन की सरकार है। मैं, माननीय मुख्य मंत्री जी को बधाई देना चाहता हूं कि जहां रेलवे लाइन का विस्तार तलवाड़ा की ओर हो रहा है वहां सबसे बड़ा

पुल लोहारली-चरडु ब्रिज जहां से विपक्ष के नेता के क्षेत्र की बसें भी आती हैं उसको आज सैंक्शन मिल चुकी है और वह कार्य अब टेंडर की ओर जा रहा है। जिसमें चिन्तपुरनी, गगरेट और हरोली को फायदा होने वाला है। यह तीन साल के अन्दर हुआ। हमारी यह डबल इंजन की सरकार है। इनके बोलने से श्री जय राम जी की सरकार कमजोर होने वाली नहीं है। मैं यहां पर कहना चाहता हूं किः-

औरों की राह पर कमजोर चला करते हैं,

आँधी हैं हम, रास्ता खुद बनाते हैं।

09.03.2022/1610/JS/YK/2

श्री जय राम ठाकुर जी ने अपना रास्ता खुद बनाया। पांच बार जीतने के बाद हिमाचल प्रदेश के मुख्य मंत्री बने। माननीय अध्यक्ष जी, हमारी सरकार पर एक भी दाग नहीं है। यदि कोई दाग है तो बताएं। हम यहां पर चुनाव क्षेत्रों की बात करके, ऊपर-नीचे की बात करके सदन का समय जितना मर्जी बर्बाद कर दें परन्तु सरकार ने 5 साल काम किया है। हमारी सरकार जनता के दिलो के अन्दर है। जब हम अपने क्षेत्रों में जाते हैं तो एक-एक पंचायत में 400 से ऊपर लाभार्थी हैं। इसके लिए मैं श्री जय राम जी को बधाई देता हूं कि माननीय मुख्य मंत्री जी की भगवान लम्बी आयु करें। हम अगले 2022 के चुनाव में माननीय जय राम ठाकुर जी की अध्यक्षता में फिर सरकार बनाएंगे, यह हमें दिखने वाला है। यह ठीक है कि सारी सरकारें काम करती हैं इनके वक्त में भी काम हुए, हमारे वक्त में भी काम हुए लेकिन फैसला जनता करती है। जनता 2022 में फैसला करेगी। हमारे माननीय प्रधान मंत्री जी की जो गरिमा आज विश्व में बनी है और वह तिरंगा जिसको लगा करके युक्रेन से छात्रों की बसें भर कर आई और किसी भी तरह का उनका कोई नुकसान नहीं हुआ। इस तिरंगें की ताकत आज प्रधान मंत्री जी के कारण बनी है। इसके लिए भी हम बधाई देते हैं। यह डबल इंजन की सरकार है। आज हमारे अनेको छात्रों के लिए चारो बॉर्डर पर हमारे मंत्री बैठे हैं और केन्द्र की सरकार ने यह स्टैप लिया कि छात्रों को युक्रेन से निकाला जाए। यह हमारी केन्द्र की सरकार की सबसे बड़ी उपलब्धि है। इनके वक्त में क्या होता था? इनके वक्त में ज्यादा ताकत उन लोगों को दी जाती थी जो देश व प्रदेश को तोड़ने वाले होते थे। जैसे

हिजबुल मुजाहिदीन, आफिज़ शाहिद, मुहम्मद अंसारी, मुल्ला उमर आदि ऐस लोग जिनको कश्मीर से जहाज पर दिल्ली लाया जाता था। उन लोगों की खातिरदारी की जाती थी। जो 56 इंच का सीना प्रधान मंत्री जी ने दिखाया है। वहां पर 370 धारा भी तोड़ी है और अब वे लोग नज़र नहीं आते हैं, जो लोग देश को तोड़ने की बात करते थे। यही हमारी उपलब्धि है। माननीय अध्यक्ष जी एक बात तो मैं साफ तौर पर कह देता हूं कि आज के युग में एक एम.पी. और एम.एल.ए. का वह सम्मान व इज्जत समाज में नहीं है। उसका कारण यही लोग है और 70 साल की राजनीति में जो भ्रष्टाचार, अलगाववाद, आतंकवाद आदि अनेकों कार्य इनके राज में हुए।

श्री एस.एस. द्वारा जारी-----

09.03.2022/1615/SS-YK/1

श्री राजेश ठाकुर क्रमागत :

उनके कारण आज हमारे पर चुटकुले आते हैं। एक कवि चुटकुला सुना रहा था और 10 हजार की भीड़ थी। उसने कहा कि मेरे देश का व्यक्ति 5 हजार डॉलर कमाता है और 4 हजार डॉलर खर्च कर देता है। वह कहता है कि 4 हजार खर्च कर देता है तो क्या आपको सरकार पूछती नहीं। वह कहता कि हमें कोई सरकार नहीं पूछती। एक हिन्दुस्तानी इनका साथी वहां बैठा था। वह कहता है कि मेरे देश का एम0पी0 और एम0एल0ए0 10 हजार रुपया कमाता है और एक करोड़ रुपया खर्च कर देता है। वह कहता क्या इनको भी सरकार नहीं पूछती? तो कहता है कि यहां भी कोई सरकार नहीं पूछती। इसी के कारण हमारी बदनामी हुई है। एम0पी0 और एम0एल0ए0 को ठीक नज़रों से देखा नहीं जाता। हमारा भ्रष्टाचार से मुक्त होने वाले देश बन चुका है। यह देश आज विश्व में अपना नाम कमाने जा रहा है। आज माननीय प्रधान मंत्री जी के 7 वर्ष और माननीय मुख्य मंत्री जी का 5वां वर्ष हमारे लिए प्रेरणादायक है। जिसके कारण आज हर विधायक की सोच व कद बढ़ा है। आज हम जब भी अपने गांव में जाते हैं तो हमें anti incumbency नज़र नहीं आती क्योंकि हमारे मुख्य मंत्री जी ने जोरदार काम किया है। 68 विधान सभाओं में जो घोषणाएं

की हैं वे हर गली व चौराहे तक पहुंची हैं। उसके कारण आज हमारे मुख्य मंत्री जी देश के ऐसे मुख्य मंत्री बने हैं जिनको टीकाकरण के मामले में प्रथम स्थान पर आने का इनाम मिला। यह भी हमारी एक उपलब्धि है। प्रदेश को काम का सम्मान मिलना बड़ी बात है। प्रदेश में मंडी में एक रैली हुई थी उसमें प्रधान मंत्री जी बोल कर गए हैं कि जो काम जय राम ठाकुर जी की सरकार ने किया वह उपलब्धियों भरा है। इस पांचवें साल के बाद सत्तापक्ष में कौन होगा और विपक्ष में कौन होगा, यह आने वाला समय तय करेगा। लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि श्री जय राम ठाकुर जी के नेतृत्व में पुनः भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी।

अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे बोलने का मौका दिया, उसके लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।

09.03.2022/1615/SS-YK/2

अध्यक्ष : अब इस चर्चा में माननीय सदस्य श्री विक्रमादित्य सिंह जी भाग लेंगे।

श्री विक्रमादित्य सिंह (शिमला ग्रामीण) : अध्यक्ष महोदय, माननीय मुख्य मंत्री ने वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए जो बजट प्रस्तुत किया है उस पर बोलने के लिए मैं खड़ा हुआ हूं। हमारे सभी सम्माननीय सदस्यों ने इस पर विस्तारपूर्वक बात रखी है। इसलिए मैं ज्यादा डिटेल में नहीं जाना चाहूंगा। मगर अभी जैसे यहां ट्रेजरी बैंचिज से बहुत से सदस्यों ने जो कुछ अच्छे कार्य इस बजट में किए गए हैं उनके ऊपर प्रकाश डाला। मैं उसके लिए सरकार को बधाई देना चाहूंगा और जो मजबूरी सरकार की चुनावों के परिप्रेक्ष्य में है उसको समझते हुए मैं यही कह सकता हूं कि अब नहीं करते तो कब करते। यह आखिरी समय था, आखिरी बजट था, इसलिए जैसा नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि एक अंतिम अरदास प्रदेश सरकार व माननीय मुख्य मंत्री ने जनता के बीच में रखी। उसमें बहुत-सी घोषणाएं की गईं। आपने आंगनबाड़ी सहायक, आशा वर्कर, सिलाई टीचर, मिड डे मील वर्कर, वाटर गार्ड इत्यादि का मानदेय बढ़ाया। डेली वेज को बढ़ाया। पंचायत चौकीदार के लिए

आपने पॉलिसी बनाने की बात कही और रेवेन्यू चौकीदार का भी मानदेय बढ़ाया। ये सब चीज़ें की गई हैं but we should also understand that all these employees and everybody in the State, we are not in living isolation. हमको उसको आज की जो हमारी वित्तीय परिस्थितियां हैं, हमारा इंफ्लैशन आज आसमान छू रहा है, महंगाई आज आसमान छू रही है particularly in the context of the COVID period that was there for the last two years.

जारी श्रीमती के0एस0

09.03.2022/1620/KS/YK/1

श्री विक्रमादित्य सिंह जारी----

जिस तरीके से आज मंहगाई चरम सीमा पर है, अगर उस परिप्रेक्ष्य से हम इस इन्क्रीज़ को देखें, इन इमॉल्युमैंट्स को देखें तो कुछ रिलीफ हमारे अलग-अलग कर्मचारी वर्गों को देने का जो एक प्रयास किया गया है, मैं यह नहीं कहूंगा कि अच्छा नहीं है। It is a good initiative और ऐसा भी नहीं है कि out of the box thinking को करते हुए इस चीज़ को इम्पलीमेंट किया गया। सक्सैसिव गवर्नमैंट्स के आप सारे पुराने बजट उठाकर देखें, सभी में थोड़ा-थोड़ा मानदेय बढ़ाया गया है। ठीक है, अच्छी बात है कि वह किया गया है, उसके लिए मैं बधाई देना चाहूंगा मगर आपकी जो वित्तीय परिस्थिति है, उसके बारे में नेता प्रतिपक्ष, आशा जी और मेरे बड़े भाई भवानी पठानिया जी ने कल विस्तारपूर्वक ज़िक्र किया है, मैं उसके डिटेल में नहीं जाना चाहूंगा मगर यह एक हकीकत है कि आज प्रदेश का जो फिस्कल डैफिसिट है, Fiscal deficit for 2022-23 is targeted and Rs. 9,602 crore which is 4.98 per cent of the GSDP. In 2021-22 as a revised estimate Fiscal deficit is expected to be 4.05 per cent of GSDP, which is lower than the budgeted estimate of 4.52 per cent of GSDP. आपका जो कैपिटल आउटले है, जो एक्सपैंडिचर आपने बिल्डिंग एंड इन्फ्रास्ट्रक्चर पर प्रदेश के अंदर करना है, मुख्य मंत्री

महोदय, आपको जो याद रखा जाएगा in the times to come because everybody wants to have a place in history. जब आप चले जाएंगे, आपकी सरकार चली जाएगी तो आप चाहेंगे, हर व्यक्ति चाहता है कि हमको किसी न किसी चीज़ के लिए याद रखा जाए। हमने क्या बनाया, कौन से हॉस्पिटल्ज़ बनाएं, इन्फ्रास्ट्रक्चर बनाया या कौन सा तथाकथित एयरपोर्ट प्रदेश के अंदर बना या कौन सा हाईवेज़ बनाया। प्रदेश के अंदर 69 नेशनल हाईवेज़ हैं। Everybody wants to be remembered for the good works a person has done. परन्तु भइया जब आपका कैपिटल आउटले ही आप कम कर रहे हैं तो आप किस तरीके से इन्फ्रास्ट्रक्चर बिल्डिंग के ऊपर ध्यान दे रहे हैं। Capital outlay in 2022-23 is estimated to be Rs. 5,647 crore, which is a decrease of a whopping 20 per cent over the revised estimate of 2021-22. आपका रेवन्यू एक्पैंडिचर बढ़ता

09.03.2022/1620/KS/YK/2

जा रहा है। निश्चित रूप से कर्मचारियों को खुश करना है, जोर का झटका धीरे से लगा है तो रेवन्यू एक्सपैंडिचर तो बढ़ा रहे हैं मगर जो कैपिटल एक्सपैंडिचर बढ़ाना चाहिए था, उसके ऊपर कोई ध्यान नहीं है। जैसे मैंने कहा कि वर्ष 2022-23 में 40,280 करोड़ रुपये आपका रेवन्यू एक्सपैंडिचर है which is an increase of 9 per cent over the revised estimate of 2021-22 i.e. Rs. 37,034 crore जो पिछले साल का था। जिसमें आपकी सैलरीज़, पैंशन, इंट्रस्ट पेमेंट्स, सबसिडी आदि-आदि आ गए जो आप प्रदेश के अंदर कर रहे हैं मगर इतना कुछ देने के बावजूद जो आप प्रयास कर रहे हैं, ठंडे दिमाग से सोचिए, आत्मचिंतन करते हुए सोचिए कि दावे के साथ आप कौन से वर्ग के लिए आज प्रदेश के अंदर कह सकते हैं कि यह वर्ग मुझसे खुश है। कौन सा वर्ग आज प्रदेश के अंदर है जो नारे नहीं लगा रहा है? आज किसान जमीन के ऊपर हैं, बागवान धरना-प्रदर्शन कर रहे हैं, आज कर्मचारी तो आपने देख ही लिया है और मैं सरकार के लोगों को कहूंगा कि जो भावनाएं पहाड़ी dialect की हैं, उससे आप चिंतित न हो। पहाड़ की अलग-अलग dialects हैं, ओल्ड हिमाचल की अलग हैं, बुशैहर रियासत की अलग है, कुल्लू की अलग है, चम्बा

की अलग है उसमें अगर कोई शब्दावली का इस्तेमाल किया जाता है तो that has to be taken in a good humor उससे नाराज हो जाना उससे 'huff and puff' में डिसिजन लेना, उससे नोटिफिकेशन निकाल देना, उससे कर्मचारियों की आवाज को दबाने का प्रयास करना,

श्रीमती अ0व0 द्वारा जारी---

09.03.2022/1625/av/ag/1

श्री विक्रमादित्य सिंह-----जारी

यह प्रदेश के इतिहास में एक अच्छी परिपाटी नहीं है। आप किसी को ऊपर से प्रैशराईज करने की बजाय प्रैशर कुकर की सिटी को निकालकर उनकी आवाज को सुनें। लेकिन यहां पर धड़ाधड़ नोटिफिकेशन्ज निकाली जा रही हैं। आप कभी ओ0पी0एस0 के बारे में निकाल रहे हैं, कभी आप आउटसोर्स कर्मचारियों की मांगों को दबाने के लिए बातें कर रहे हैं। आप उनके बारे में सुनें, यदि माननीय मुख्य मंत्री नहीं सुन सकते तो अधिकृत माननीय मंत्री उसके बारे में सुनें, मगर उनकी बातों की तरफ ध्यान दिया जाए। आप यहां पर क्लेम करते हैं कि प्रदेश के किसान-बागवान आपसे खुश हैं तो जो उनके द्वारा इतनी ज्यादा मांगें रखी गई हैं वह सदन के अंदर अच्छा बजट प्रस्तुत करने के बाद नहीं रखी जातीं। सभी फसलों के लिए न्यूनतम मूल्य तय करने के लिए कानूनी रूप से लागू होने की मांग और मण्डी मध्यस्थता योजना में ए0, बी0, सी0 ग्रेड सेब की 60, 44 और 24 रुपये प्रति किलोग्राम खरीदने की मांग है। आपके ए0पी0एम0सी0 को सख्ती से लागू करने और पर्दे की बोली को रोकने की मांग रखी गई है। आपके बैरियर्ज पर ली जा रही मार्किट फीस को रिवाईज करने की मांग आई है। आपके आढ़ती लदानियों के पास बकाया राशि के तुरंत भुगतान की मांग उठी है। आपके निजी कंपनियों के सी0ए0 स्टोर से बागवानों का 25प्रतिशत सेब खरीदने की मांग को लागू करवाने, आपके सेब की पैकेजिंग में इस्तेमाल होने वाली कार्टन्ज और ट्रे की बढ़ती कीमतों के बारे में उठाई गई मांगें; जिनके बारे में

पिछले साल बहुत हंगामा हुआ था। उसके बारे में प्रदेश सरकार ने इस बजट में कोई विचार विमर्श नहीं किया है। प्राकृतिक आपदा से हुए फसलों के नुकसान के मुआवजे की मांग आई है। प्रदेश में बढ़ती महंगाई और माल-भाड़े की बढ़ी हुई दरों को वापिस लेने की मांग भी उठी है। इसके अतिरिक्त, कीट नाशक दवाओं की सब्सिडी इस बजट में कम कर दी गई है, हालांकि उसके लिए तर्क यह दिया गया है कि हम प्रदेश में प्राकृतिक खेती की ओर बढ़ रहे हैं। मगर इसकी सब्सिडी जो कम की गई है, उसके लिए भी किसानों-बागवानों ने मांग रखी है। अतः इस ओर भी ध्यान देने की आवश्यकता है। आप खुद देखिए, महंगाई कहां जा रही है। प्रदेश में हरेक व्यक्ति ने

09.03.2022/1625/av/ag/2

घर बनाना है। उसमें आशा वर्कर्ज, ओल्ड पैंशन स्कीम की मांग करने वाले कर्मचारियों ने भी अपना-अपना मकान बनाना है। लेकिन आप देखिए रॉ मैटीरियल की कीमतें कहां जा रही है। प्रदेश में सीमेंट के रेट में एक महीने पहले बढ़ोतरी हुई है। प्रदेश में सीमेंट 425 प्रति प्रति बैग, 1,000 ईंटें 10,000 रुपये, रेत की गाड़ी 18,000 रुपये तथा बजरी की गाड़ी 17,000 रुपये में मिल रही है। पिछले सप्ताह प्रति क्विंटल सरिया 6,500 रुपये के हिसाब से मिल रहा था जिसकी कीमत अब बढ़कर 8,400 रुपये हो गई है। आपने एक तरफ तो बजट में मानदेय बढ़ाया है, आप लोग अलग-अलग ग्रांट्स देने की कोशिश कर रहे हैं या किसानों-बागवानों को डायरैक्ट बेनिफिट देने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन दूसरी तरफ महंगाई आसमान छू रही है। आपने पीछे पैट्रोल-डीज़ल के रेट तो चुनावों की वजह से कम किए हैं। कल चुनावों के परिणाम आएंगे और उसके बाद इनके दाम बढ़ेंगे तथा उसके लिए आप इंटरनेशनल क्राइसिज या रूस द्वारा यूक्रेन पर किए जा रहे आक्रमण का हवाला देंगे। यहां पर वरिष्ठ सदस्या श्रीमती आशा कुमारी ने डॉलर के मुकाबले हमारे रुपये की गिरती कीमत का हवाला दिया। आप खुद देख सकते हैं कि आज पूरे देश की ही नहीं बल्कि हमारे प्रदेश की अर्थ-व्यवस्था भी बिगड़ रही है। उसके बावजूद इस बार 8.2 प्रतिशत ग्रोथ दिखाने का प्रयास किया जा रहा है। यहां पर माननीय सदस्य श्री हर्षवर्धन चौहान ने

बिल्कुल सही कहा कि वर्ष 2018-19 में हमारा इंडस्ट्री, टूरिज्म, होर्टिकल्चर क्षेत्र इत्यादि पूरी तरह से हाईक पर थे और उस समय हमारा ग्रोथ रेट 4.2 प्रतिशत था। आज तो आपकी बैंड बजी हुई है, आपका इंफ्रास्ट्रक्चर शून्य है। टूरिज्म क्षेत्र पिछले दो वर्षों से रिकवर कर रहा है। आपका होर्टिकल्चर के बारे में क्या हाल है

टी सी द्वारा जारी

09/03/2022/1630/टी0सी0वी0/ए0जी01
श्री विक्रमादित्य सिंह... जारी

यह हमने डिमांडज के माध्यम से देख लिया है और आप कह रहे हैं कि हम प्रदेश के अंदर 8.3 प्रतिशत की ग्रोथ करेंगे। हम जानते हैं कि आप उस विचारधार से हैं जहां फेंकने में विश्वास रखते हैं लेकिन उतना फेंके जिसको प्रदेश के लोग डाइजैस्ट कर सकें। हवा में बातें करना और कैसल्ज बनाना आपका काम है। मैंने एन0जी0टी में भी कहा कि castles in the air बनाए जा रहे हैं। वह एक समिति समय के लिए था लेकिन इसमें भी हमें वही चीज देखने को मिली है। मैं शिमला के वर्ल्ड बैंक के प्रोजैक्ट के बारे में कहना चाहता हूं। शिमला राजधानी है, आपने भी पानी पीना है और हमने भी पानी पीना है। लेकिन ये राजनैतिक पानी ही पिलाई जा रहे हैं। जो शिमला बल्क वॉटर सप्लाई प्रोजैक्ट है, इसका शिलान्यास दिनांक 01-01-2020 को किया गया। The work has not been started after passage of two years and three months. 'सिस्टम इम्प्रूवमैंट प्लॉन' तीन बार देने के बावजूद भी अभी तक अप्रूव नहीं हुआ है। Staff from HPSEBL and HPPWD deputed in the Jal Prabandhan Nigam Limited, Shimla has no experience in water supplies. All R&P Rules are flouted to appoint Engineers who cannot decipher type of pipes and motor pump. That has to be implemented. Work was awarded for Rs. 331/- crores. Deviation proposed is Rs. 236/- crores without starting the work. Water is not being provided to Sunni and intermediate habitations. मैं यह कितनी बार कह चुका हूं कि जहां से पानी उठा रहे हैं, कम-से-कम दो बूंद पानी उन लोगों को भी दे दो। सुन्नी और उसके साथ लगती पंचायतें जहां से यह

पानी उठाया जा रहा है, at least some provision should be made for them. लेकिन वह नहीं हुआ। The CPD proposed will not be without water. If Bulk Water Project is not executed, the World Bank will not release single rupee from Rs. 12,000/- crores projects, as disbursement link indicators will not be achieved. आपका यह पैसा लैप्स हो जाएगा इसलिए मेरा जल शक्ति मंत्री जी से निवेदन है कि इस पर कार्य करें। ये बहुत वरिष्ठ माननीय मंत्री हैं। क्योंकि जिस तरह से पिछले साल शिमला को पानी की प्रोब्लम्ज फेस करनी पड़ी ऐसा न हो कि यह प्रोब्लम फिर से हो जाए। मेरी आपसे करवद्ध प्रार्थना है कि इस पर कार्य किया जाए। Why penalty is not being imposed on contractor for delay of project? इनकी क्या दोस्ती है, क्या नहीं है, यह

09/03/2022/1630/टी0सी0वी0/ए0जी0-2

तो मैं नहीं जानता लेकिन उन पर क्यों कार्रवाई नहीं की जा रही है, यह मैं जानना चाहता हूं?

अतं में मैं आपसे कहूंगा कि कर्मचारियों की कुछ मांगें हैं और कर्मचारियों ने हाउस रेंट की मांग की है। उनके हाउस रेंट का इस बजट में कोई भी जिक्र नहीं किया गया है। दूसरा, सचिवालय कर्मचारियों को सचिवालय भत्ता देने का जिक्र किया गया है जबकि उसके समकक्ष कार्यालयों को छोड़ दिया गया है। यह नोटिफिकेशन वर्ष 2012 की नोटिफिकेशन की कांटिन्यूशन में की गई है तो उसके अनुसार हिमाचल प्रदेश राज्य सचिवालय के समकक्ष जो कार्यालय हैं, उनमें कार्यरत सभी अधिकारियों व कर्मचारियों को भी "सचिवालय पे" मिलना चाहिए। मेरा हिमाचल प्रदेश के ऊर्जावान मुख्य मंत्री, श्री जय राम ठाकुर जी से निवेदन है कि कृपया इसे इम्प्लीमेंट करने का प्रयास करें।

एन0एस0 द्वारा जारी ….

09-03-2022/1635/NS/AS /1

श्री विक्रमादित्य सिंह.....जारी

अंत में कहना चाहूंगा कि सरकार ने इस बजट में कर्मचारियों के वेतन के एरियर के बारे में कोई भी ज़िक्र नहीं किया है। इसके लिए मुख्य मंत्री जी बताएं कि एरियर कब तक क्लीयर कर दिया जाएगा? इन्हीं शब्दों के साथ, मैं धन्यवाद करता हूं और इसमें जो कार्य अच्छा किया गया है उसके लिए बधाई। मगर जैसा मैंने पहले कहा कि अगर आपको लग रहा है कि इसका राजनीतिक लाभ आपको मिलने वाला है तो वर्ष 2022 के चुनावों में पता चल जाएगा कि दूध का दूध और पानी का पानी कैसे होता है? अध्यक्ष महोदय, आपने बोलने का मौका दिया, आपका धन्यवाद। जय हिंद, जय हिमाचल।

09-03-2022/1635/NS/AS /2

अध्यक्ष : अब इस चर्चा में अंतिम सदस्य श्री सुखविन्द्र सिंह सुक्खु जी भाग लेंगे और आप समय का ध्यान रखें।

श्री सुखविन्द्र सिंह सुक्खु, नदौन : अध्यक्ष महोदय, जितना समय अन्य माननीय सदस्यों को दिया है उतना ही समय मुझे देना। मुख्य मंत्री जी ने वर्ष 2022-23 में लगभग 51,365 करोड़ रुपये का बजट प्रस्तुत किया है और यह मुख्य मंत्री जी का पांचवां बजट है तथा आपने अपनी रस्म अदायगी पूरी की है क्योंकि जाने वाला साल है। पांचों बजट में कहीं-न-कहीं नीतिगत सोच का अभाव है। सोचा हमने था कि डबल इंजन की सरकार है। यहां पर सत्ता पक्ष के विधायक कह रहे थे कि डबल इंजन की सरकार आई है। जब हमने 51,365 करोड़ रुपये के बजट को खंगाला कि कहीं-न-कहीं डबल इंजन की जो केंद्र सरकार आठ वर्ष से बैठी हुई है वह ग्रांट-इन-ऐड के रूप में 10,000 करोड़ रुपये देगी। अध्यक्ष महोदय, लेकिन इसका कहीं उल्लेख नहीं है। मैं यह बात इसलिए कहना चाह रहा हूं क्योंकि जो बजट के आंकडें हैं और इन पर मैं चर्चा नहीं करूंगा। इस बजट में एक नीतिगत सोच जरूर दिखानी चाहिए थी कि आने वाले समय में हम किस प्रकार अपनी राजस्व प्राप्तियों को बढ़ायेंगे? आज हमारी राजस्व प्राप्तियां सारे टैक्स और नॉन टैक्स को मिला करके 15,000 करोड़ रुपये हैं। हमें 15वां वित्त आयोग हर साल 10,000 करोड़ रुपये देता है। इस वर्ष हमें 9,000 करोड़ दे रहा है और अगले साल 10,500 करोड़ रुपये दे रहा है। आने वाले समय में वित्त आयोग की रिकमेंडेशन है और जो पैसा हमें मिलना है वह कम होता जाएगा। वर्ष 2025-26 में सिर्फ 3,500 करोड़ रुपये रह जाएंगे।

अध्यक्ष महोदय, आप लोग जब विकास की बात करते हैं तो सही मायने में इस बजट का केपिटल एक्सपेंडिचर 12 प्रतिशत के करीब है और इसमें 29 प्रतिशत दिखाया गया है। 17 प्रतिशत लोन लेकर विकास की स्कीमों में लगना है। अध्यक्ष महोदय, नीतिगत सोच की कमी इस सरकार में पिछले पांच साल में थी और आने वाले पांच साल में भी है। इसी महीने सरकार 3000 करोड़ रुपये कर्ज लेगी। आने वाले समय में इसी साल के अंत में हिमाचल प्रदेश पर 70,000 करोड़ रुपये का कर्ज होगा। इसका मतलब यह है कि 70 लाख की जनसंख्या में प्रत्येक व्यक्ति चाहे वह सदन में बैठा विधायक, अधिकारी, ऊपर प्रैस गैलरी में बैठै पत्रकार भाई और पुलिस के कर्मचारी हैं, प्रदेश के हर नागरिक पर एक लाख रुपये का कर्ज चढ़ा होगा। इतना ही नहीं आने वाले दो वर्षों में जो बच्चे पैदा होंगे उन पर भी एक लाख रुपये का कर्ज चढ़ा होगा। यह डबल इंजन सरकार की नीतिगत सोच है।

09-03-2022/1635/NS/AS /3

प्रदेश को कर्ज़ में छोड़ कर जा रहे हैं। हमारे माननीय सदस्य श्री भवानी सिंह पठानिया ने कल एक कहावत ठीक कही है कि दो राजा लड़ रहे होते हैं और जब राजा चारों तरफ से घिर जाता है तो भागने की कोशिश करता है। इस सरकार का भी वही हाल है और भागने की कोशिश कर रही है

श्री आर0 के0 एस0 द्वारा जारी।

श्री बी0 एस0 द्वारा जारी।

09.03.2022/1640/RKS/एएस-1

श्री सुखविन्द्र सिंह सुक्खु... जारी

क्योंकि सत्तापक्ष के राजा सब तरफ से घिर चुके हैं। जब राजा भागने की कोशिश करता है तो अपने संसाधनों जैसे पानी के कुएं और अन्न भंडारण इत्यादि में जहर डाल देता है ताकि जिस राजा ने उसका घेराव किया है उसे इसका फायदा न मिले। इसी तरह यह सरकार भी प्रदेश की जनता को कर्ज तले दबाकर नष्ट करने का प्रयास कर रही है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार हिमाचल प्रदेश को बेचने का काम कर रही है। आने वाले वर्षों में

हिमाचल प्रदेश का प्रत्येक नागरिक कर्ज के बोझ से दब जाएगा। देश तो पहले ही मुद्रीकरण और अन्य चीजों के तहत बिक रहा है लेकिन इस पर हम अभी बात नहीं करना चाहते। हम हाइड्रो से अपना राजस्व बढ़ा सकते थे। वर्ष 2005-06 की पावर पोलिसी के अनुसार हम जिस पावर प्रोजैक्ट को प्राइवेट पार्टी या सरकार को देते थे उसमें हमें पहले 12 वर्षों में 12 प्रतिशत फ्री पावर मिलती थी। 12 से 30 साल तक 30 प्रतिशत और 30 से 40 साल तक 40 प्रतिशत पावर फ्री मिलती थी। 40 वर्ष के बाद वह प्रोजैक्ट प्रदेश सरकार को वापिस हो जाता था। लुहरी-I, लुहरी-II, और धौलासिद्ध प्रोजैक्ट में आपने क्या समझौता किया? आपने नई ऊर्जा नीति के साथ SJVNL के साथ समझौता किया है। हम लोग भले ही न रहें लेकिन हमें अगली पीढ़ी की चिंता करनी चाहिए। आपने यह समझौता कर दिया कि लुहरी-I, लुहरी-II, और धौलासिद्ध प्रोजैक्ट सदा के लिए आपके पास रहेंगे। जो हमें 12 प्रतिशत फ्री बिजली मिलनी थी, वह अब नहीं मिलेगी। आपने कहा कि हम 40 साल बाद आपको 25 प्रतिशत बिजली वापिस करेंगे और आपने 70 साल की कंडिशन भी हटा दी। आप हिमाचल प्रदेश की जनता के हितों को बेच रहे हैं। आपने रिसोर्स पैदा करने के लिए राइडर कहां लगाया है? नई ऊर्जा नीति में आप प्राइवेट वालों के लिए 40 वर्ष की कंडीशन के बाद पावर प्राजैक्ट वापिस लेने की बात करते हैं लेकिन पी.एस.यू. के तहत जो पावर प्रोजैक्ट्स दिए हैं उनमें क्यों समझौते हो रहे हैं? हिमाचल प्रदेश के लोगों के हितों के साथ क्यों खिलवाड़ किया जा रहा है? जोगिन्द्रनगर के चूल्हा प्रोजैक्ट का कार्य वर्ष 2007 में पूर्ण किया

09.03.2022/1640/RKS/एएस-2

जाना था। उस समय इस प्रोजैक्ट की लागत 431 करोड़ रुपये आंकी गई थी। इस प्रोजैक्ट को बनते-बनते आज 19 वर्ष बीत गए और आज इसकी लागत 2150 करोड़ रुपये पहुंच गई है। आप इस तरह हिमाचल प्रदेश की जनता का पैसा क्यों बरबाद कर रहे हैं? जिन अधिकारियों ने इस कार्य को लंबित किया उनके विरुद्ध क्या कार्रवाई की गई? जब यह प्रोजैक्ट बनकर तैयार होगा तो जो इससे जो बिजली उत्पादन होगा वह 50 रुपये प्रति

यूनिट के हिसाब से पड़ेगा। यह प्रदेश की जनता के भविष्य के साथ खिलवाड़ है। श्री जगत सिंह नेगी जी के प्रश्न के उत्तर में शोंगटंग-कड़छम- वांगटू प्रोजैक्ट का जवाब आया है।

श्री बी.एस. द्वारा... जारी

09.03.2022/1645/बी.एस./डी0सी0/-1

श्री सुखविन्द्र सिंह सुक्खु जारी...

जो प्रोजैक्ट की मिट्टी उठनी थी, मिट्टी उठाने के लिए जो प्रोजैक्ट बनाना था, 121 करोड़ रुपया खर्च कर दिया गया। वह 450 मैगावाट का प्रोजैक्ट है, क्यों ऐसी ला परवाहिंया हो रही हैं और अभी तक भी आने वाले तीन-चार सालों में वह प्रोजैक्ट नहीं बनेगा। क्यों नहीं बनेगा? हिमाचल पॉवर कारपोरेशन उस प्रोजैक्ट को बना रही है। उसमें होल टाइम चेयर मैंन की की आवश्यकता है। अधिकारी बैठे हैं जनता हमारी है, पैसे हमारे हैं, पैसों को बर्बाद किया जा रहा है। जहां से रेवेन्यू जनरेट होना चाहिए था हमें एक पैसा नहीं आ रहा है, यही नहीं आने वाले समय में जिस प्रकार की ऊर्जा नीति आपकी सरकार यहां पर ले करके आई है, कि 70 साल तक वह प्रोजैक्ट उनकी पास रहेगा, क्यों ऐसा परविर्तन किया गया? बहाना बिल्कुल साफ है कि कोई प्रोजैक्ट लगाने नहीं आया। प्राइवेट वाले 12 प्रतिशत फ्री पॉवर भी दे रहे हैं और 30 साल जब प्रोजैक्ट की उम्र होगी तो 18 प्रतिशत फ्री पॉवर दे रह हैं और 30-40 साल के बीच में वह 40 प्रतिशत पॉवर दे रहे हैं, उसके बाद प्रोजैक्ट हिमाचल प्रदेश को दे रहे हैं। आपने नई ऊर्जा नीति बनाई और आपकह रहे हैं कि 70 साल तक आप इस प्रोजैक्ट को चलाओ। जम्मू-कश्मीर की पॉवर पोलिसी बनी उसका आप अध्ययन करिए, हिमाचल की वर्ष 2005-06 की पॉवर पोलिसी बनी है आप उसका अध्ययन करिए। यह बात मैं इसलिए आपके ध्यान में लाना चाहता हूं कि अगर आज हमने नहीं सोचा तो भविष्य में आने वाली पीढ़ियां हमें गाली देगी कि कैसे नेता इस सभागार में बिठा करके रख दिए थे, जिन्होंने हिमाचल के बहते हुए सोने की क्या कीमत लगाई है। एस0जे0बी0एन0एल0 के साथ आपके जो भी एम0ओ0यू0 साइन हुए हैं, उनको रिवाइज करने की जरुरत है। हम हमाचल प्रदेश को धुंए का शहर नहीं बनाना चाहते, अगर हमें हाइड्रो जेनरेशन से हमे कोई लाभ नहीं मिल रहा है तो धुंए के शहर मत बनाइए। जब यहां

पर धुंए के शहर बन जाएंगे तो हमारे पर्यटन को इससे नुकसान होगा। मुख्य मंत्री जी एक और चीज में आपके ध्यान में लाना चाहता हूं। आपने अपने बजट भाषण में बिलासपुर-भानुपल्ली-रेल लाइन का जिक्र किया है। बहुत अच्छी बात है बननी चाहिए। आप देखिए कि 15 साल पहले जो समझौता हुआ है उसे रिवाइव करने की जरुरत है। उसमें जो उस समय के अधिकारी या अन्य कोई भी होंगे उन्होंने उस वक्त हिमालच प्रदेश के भविष्य के साथ क्या खिलवाड़ किया गया? उसमें कहा गया है कि भानुपल्ली रेल बिछाने के लिए

09.03.2022/1645/बी.एस./डी0सी0/-1

हिमाचल प्रदेश की जो भुमि अधिग्रहण करेंगे और जो कोस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन होगी उसमें 25 प्रतिश जो हमारा शेयर होगा उसे हम देंगे। यानी 15 सौ करोड़ लगाने के बाद, जो शेयरिंग है उसे तो रेलवे ने हमसे करवा दिया परंतु फायदा किसे होना है? केवल दो सिमेंट फैक्ट्रियों को, क्योंकि सिमेंट फैक्ट्री वालों ने सरकार से क्या फैसला करवाया इस पर भी फिर से विचार करने की जरुरत है। 1500 करोड़ लगाने के बाद, कोस्ट शेयरिंग में हमें भागीदारी बनाने के बाद मुख्य मंत्री महोदय, रेवेन्यू शेयरिंग में हमें एक पैसा भी नहीं मिल रहा है। रेवेन्यू शेयरिंग में क्या मिल रहा है कि हम आपको सर्विस प्रोवाइड करेंगे। जिस इन्डस्ट्री के लिए दो उद्योगों के लिए वह रल लाइन बिछाई जा रही है उससे जो करोड़ों रुपया आएगा उसमें कुछ शेयर हमारा भी होना चाहिए। मुख्य मंत्री जी सात सौ करोड़ रुपया उनको दे चुके हैं। 70 करोड़ के अलावा जमीन की कोस्ट हिमाचल प्रदेश सरकार दे रही है। ये ही नहीं चण्डीगढ़-बद्दी रेल लाइन की बात करना चाहूंगा। इसमें तो लिख रहें है कि केन्द्र सरकार कर रही है, 50 प्रतिशत लैंड एक्यूजिशन की कोस्ट भी हिमाचल की सरकार वहन करेगी और कंस्ट्रक्शन की कीमत तो और भी ज्यादा बढ़ गई है उसे भी हिमाचल प्रदेश सरकार वहन करेगी। सरकार कहां सोई रहती है?

श्री एन0 जी0 द्वारा जारी...

09-03-2022/1650/डी.सी.-एन.जी. /1

श्री सुखविन्द्र सिंह सुक्खु ..... जारी

कोस्ट शेयरिंग तो कर रहे हैं लेकिन रेवन्यू शेयरिंग नहीं कर रहे हैं। क्यों हिमाचल की जनता का पैसा फालतू में बांट कर लूटा रहे हैं? जब बिलासपुर-भानुपल्ली रेल लाइन सीमेंट उद्योगों के पास पहुंचेगी, माननीय सदस्य श्री संजय अवस्थी जी ने ठीक कहा था कि इनके विधान सभा क्षेत्र में सीमेंट उद्योग लगे हैं और वहां के लोगों को 1500 करोड़ रुपये की इस रेल लाइन पहुंचाने के बाद सीमेंट 440 या 450 रुपये में मिलेगा। हमारे पैसे, हमारे खनिज, हमारी माइनिंग और सीमेंट का रेट चण्डीगढ़ से ज्यादा होगा। दिल्ली से ज्यादा रेट हिमाचल प्रदेश के गरीब लोगों को मिल रहा है। अर्की विधान सभा क्षेत्र में, जहां पर सीमेंट का उद्योग लगा है वहां पर as per cost सीमेंट मिलना चाहिए। जिस भी विधान सभा क्षेत्र में ऐसे उद्योग लगते हैं वहां पर इसी प्रकार की व्यवस्था होनी चाहिए, जैसे हाइड्रो प्रोजैक्ट्स में लाडा के रूप में दिया जाता है। माननीय मुख्य मंत्री जी आप एक समझौता और करने जा रहे हैं और मैं आपको इसलिए जागरूक करना चाहता हूं कि आप हिमाचल प्रदेश को मत बेचिए। आज आप अधिकारियों से घिर चुके हैं, आप सरकारी कर्मचारियों से और मंत्रियों से घिर चुके हैं। जब कोई राजा चारों ओर से घिर जाता है तो वह वहां से भागने की कोशिश करता है। वह कहता है कि 'यह स्यापा है छडों परां'।

अध्यक्ष : माननीय सदस्य अब वाइंडअप कर दें।

श्री सुखविन्द्र सिंह सुक्खु : अध्यक्ष महोदय, माननीय मुख्य मंत्री जी का ड्रीम प्रोजैक्ट है कि बल्ह में अन्तर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा बनना चाहिए। हम भी कहते हैं कि बनना चाहिए और हम भी उसका स्वागत करते हैं। लेकिन जो delay tactics or delay corruption है उसे भी देखने की जरूरत है। आप अपनी सरकार का और हिमाचल की जनता का 2,000 करोड़ रुपये खर्च करने के बाद उनसे कुछ नहीं ले रहे हैं।

09-03-2022/1650/डी.सी.-एन.जी. /2

माननीय योगी जी ने यू.पी. के अंदर जेवर में एयरपोर्ट बनाया और उसमें प्रदेश का रेवन्यू शेयर रखा। लेकिन आप किस शर्त पर एम.ओ.यू. साइन करने जा रहे हैं? उसके लिए आप

सारी जगह खरीदेंगे और आपने 2,000 करोड़ रुपये भी रख लिया है। लेकिन आप रेवन्यू शेयरिंग में एक भी पैसा नहीं ले रहे हैं। यदि आपने इस शर्त के साथ एम.ओ.यू. साइन किया तो आप मण्डी व हिमाचल की जनता को धोखा देंगे। आप यदि कोस्ट शेयरिंग कर रहे हैं तो रेवन्यू शेयरिंग भी कीजिए। आप उसमें अपना हक मांगिए क्योंकि यह हक हिमाचल की जनता का है। इसमें हम सब आपका साथ देंगे। ऐसा नहीं है कि ये कभी नहीं हुआ है क्योंकि उत्तर प्रदेश सरकार ने ऐसा किया है। यू.पी में जेवर अन्तर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा बन रहा है और उसमें वहां की सरकार ने कहा कि यदि हम कोस्ट शेयर करेंगे तो हम रेवन्यू भी शेयर करेंगे। आप रेलवे के एम.ओ.यू. को भी दोबारा रिवाइव कीजिए। हम अपने हिमाचल की जनता का धन ऐसे ही लूटने नहीं देंगे। अध्यक्ष महोदय, जो बीत गया उस अतीत को मत याद कीजिए।

अध्यक्ष : माननीय सदस्य श्री सुखविन्द्र सिंह सुक्खु जी कृपया अब एक मिनट में वाइंडअप कर दीजिए।

श्री सुखविन्द्र सिंह सुक्खु : अध्यक्ष महोदय, आपने बहुत सारे माननीय सदस्यों को 30-30 मिनट दिए हैं। क्या मैं कोई गलत बात कर रहा हूं? अध्यक्ष महोदय, यदि हमने कोई गलती की है तो हम विपक्ष में बैठ कर उसकी सजा काट रहे हैं। आप (सत्तापक्ष) तो गलती पर गलतियां करते जा रहे हैं। आपको तो इसकी सजा डबल मिलेगी। हिमाचल की जनता बहुत जगरूक है और एक सजा तो आपको अभी कुछ समय पहले दे भी दी है। हिमाचल की जनता बहुत बुद्धिमान है और वह जानती है कि आप क्या करने जा रहे हैं। यहां पर आप किसानों की बात कर रहे हैं, हम सब लोग किसी-न-किसी रूप से कृषि से जुड़े हुए हैं। किसान खेती क्यों करेगा, दुग्ध उत्पादक दुग्ध उत्पादन क्यों करेगा,

श्री जे.एस. द्वारा जारी.....

09.03.2022/1655/JS/YK/1

श्री सुखविन्द्र सिंह सुक्खुः----जारी---

क्योंकि उस रूरल इकोनॉमी के बारे में भी सोचने की जरूरत है। आप नहीं सोच रहे हैं। तभी तो आपने रस्म अदायगी पूरी कर दी। जय राम ठाकुर जी को कभी तनाव नहीं होता था लेकिन आजकल तनाव आ रहा है। बार-बार ये सीट से उठ जाते हैं। ये गुस्सा हो जाते हैं। चार साल तक ये बड़े शांत स्वभाव में थे। आपको बहुत प्रैशर पड़ रहा है। चुनावों का प्रैशर है, दिल्ली का प्रैशर है, मंत्रियों का प्रैशर है और कुछ विधायकों का प्रैशर है। कुछ नाराज विधायक जो उस ओर हैं, वे इधर भी आना चाहते हैं। माननीय मुख्य मंत्री जी, आपने 60 साल वालों को पैंशन दी। वह आपने अच्छा किया। लेकिन आपने पैंशन कितनी दी केवल 1100 रुपये दिए। आपने गाय की रक्षा करने वाले को भी 700 रुपये दिये लेकिन आपने घास व दाल का मूल्य एक ही कर दिया। उनको आप कम-से-कम 1500 रुपये पैंशन देते। ये नीतिगत परिवर्तन है। हमारी सरकारें भी पैंशन देती आई हैं। आपके टाइम में कोई नई योजना नहीं आई है। हम राजीव गांधी आवास योजना के तहत आवास भी देते थे। माननीय अध्यक्ष महोदय, किसानों के लिए हम इस मंच के माध्यम से कहना चाहते हैं कि अगर कांग्रेस घोषणा पत्र में सब्जियों के लिये, जो गोभी उगाता है, भिंडी उगाता है, आलू उगाता है, प्याज उगाता है, हमने किसानों को देखा है, जब शाम होती है और जब वह फुल गोभी बेचने जाता है अगर दिन में वह 30 रुपये में बिकती है तो शाम को पौने दो रुपये किलो उसको बेचनी पड़ती है। हम उनके लिए मिनीमम सपोर्ट प्राइस लाएंगे जैसे एप्पल में ले कर आए हैं। यही नहीं दूध उत्पादकों के लिए कुछ नहीं किया। आप उसमें दो रुपये बढ़ा रहे हैं। हम तो इस मंच के माध्यम से कह रहे हैं कि दूध उत्पादक क्यों दूध पैदा करेगा जब आप उससे कम पैसे पर लेंगे? हम कम-से-कम जो भी दुग्ध उत्पादक होगा और इसकी स्टडी की गई है, कम-से-कम 80 रुपये किलो दूध उससे लेंगे और इस नीति को यहां पर लागू करेंगे। यह हमारे घोषणा पत्र में आएगा। ....व्यवधान...

अध्यक्षः माननीय सदस्य आप वाइंड अप करें। ....व्यवधान...

09.03.2022/1655/JS/YK/2

श्री सुखविन्द्र सिंह सुक्खुः माननीय अध्यक्ष महोदय, ...व्यवधान...हमने कहा है और हम जो मंच पर कहते हैं, ठोक-बजा कर कहते हैं। हमारा घोषणा पत्र आएगा और उसमें कहेंगे। इसमें आप लोगों को क्यों तकलीफ हो रही है? ....व्यवधान...माननीय अध्यक्ष महोदय कर्मचारी, अधिकारी चाहे वह बोर्ड में लगा है, चाहे कॉर्पोरेशन में लगा है, पत्रकार बन्धु भाई और यहां पर 70 लाख की जनसंख्या है। हमारा छोटा सा और सुन्दर प्रदेश है। पांच साल से आपकी नीतियों ने इसको बर्बाद करके रख दिया है। आपने छठा वेतन आयोग बड़े रो-धोकर दिया। चलो अच्छा किया और आप उसमें देखिये उसमें आप अच्छी सैलरी दे रहे हैं। अब जो चीफ सेक्रेटरी, सेक्रेटरीज़ को पे मिलेगी उसमें चीफ सेक्रेटरी को तीन से सवा तीन लाख तक पे मिलेगी क्योंकि बेसिक 2,25,000 के करीब होगी। डॉक्टर्ज़ का वेतन 2,30,000 रुपये तक होगा और उसमें 31 परसेंट डी.ए. लग जाएगा। इंजीनियर्ज़ की 3-3 लाख, 2-2 लाख रुपये की सैलरी है। कर्मचारियों का आप उत्थान कर रहे हैं। अगर थोड़ा सा दिल आप और खोल देते ....व्यवधान...एम.एल.ए. को नहीं कह रहा हूं ....व्यवधान...आपको एक चीज मैं और बता दूं, 70 लाख की जनता 68 विधायकों को चुनती है। हर पांच साल बाद उसको जनता की अदालत में पेश होना पड़ता है। जनता उससे सवाल पूछती है कि आपने मेरे क्षेत्र के लिए क्या किया? क्या इस गांव में सड़क पहुंची? क्या उस गांव में पानी पहुंचा? हर गरीब आदमी उसके दरवाजे तक पहुंचता है और वह विधायक बड़ी विनम्रता से उसकी बात सुनता है। हमने नहीं कहा कि हमें चाहिए, हमने कहा कि आपने छठा वेतन आयोग दिया।

श्री एस.एस. द्वारा जारी------

09.03.2022/1700/SS-YK/1

श्री सुखविन्द्र सिंह सुक्खु क्रमागत :

आपने बहुत अच्छा किया और उसके लिए आप इस मार्च में 3000 करोड़ रुपया कर्जा ले रहे हैं। जब आपने प्रदेश को बेचना ही है तो सरकारी कर्मचारी जो हर रोज़ नारा लगा रहे

हैं कि जय राम मामा मान्दा नहीं कर्मचारियों की सुनदा नहीं, उनके लिए आप 3 या 4 हजार करोड़ रुपया और कर्जा ले लो तथा उस कर्जे के आधार पर इनको ओल्ड पेंशन स्कीम लगा दो। चाहे वे बोर्ड या कारपोरेशन के कर्मचारी हैं उन बेचारों को कुछ मिलता नहीं है। सन् 2000 के बाद के जो अधिकारी इस अधिकारी दीर्घा में बैठे हैं उनको और कुछ पत्रकारों को भी पेंशन लगा दो। आपका इसमें क्या लगता है आपने कर्जा ही तो लेना है। लेकिन कर्जा लेने से पहले जो आप रेवेन्यू बांट रहे हैं उस चीज़ को भी देखो। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि मुख्य मंत्री जी आप सब वर्गों का ख्याल रखें।

अध्यक्ष : सुखविन्द्र सिंह सुक्खु जी, आप एक मिनट बैठिए। अब इस माननीय सदन की कार्यवाही एक घंटा यानी 6.00 बजे अपराह्न तक बढ़ाई जाती है।

श्री सुखविन्द्र सिंह सुक्खु : अध्यक्ष महोदय, हम आपके माध्यम से कह रहे हैं कि 1.30 लाख सरकारी कर्मचारी हैं, पहले 2.25 लाख कर्मचारी थे।

अध्यक्ष : माननीय सदस्य आप वाइंड अप कर दीजिए। आपको बोलते हुए 25 मिनट हो गए हैं। आपकी सारी बातें आ गई हैं। आप रिपीट मत करिए।

श्री सुखविन्द्र सिंह सुक्खु : जो आउट सोर्स कर्मचारी हैं, करूणामूलक कर्मचारी हैं ...व्यवधान... अध्यक्ष महोदय, मुझे कंक्लूड तो करने दो। क्लोजिंग तो होने दो।

अध्यक्ष महोदय, आज हम आपको यह कहना चाह रहे हैं कि जो आउट सोर्स कर्मचारी है, करूणामूलक कर्मचारी हैं, पैरा फीटर्ज हैं, पीस मील वर्कर्ज हैं जोकि ठाकुर साहब ने बहुत लगाए हैं। सिर्फ दो ही क्षेत्र के लगे हैं। एक सिराज और दूसरे धर्मपुर क्षेत्र के लगे हैं, मल्टी पर्पज़ वर्कर्ज हैं, हिमाचल की सरकार जनता का धन इस तरह से नहीं बांटेगी जिस तरह से जय राम ठाकुर जी की सरकार बांट रही है।

09.03.2022/1700/SS-YK/2

रेलवे को दे दो, मुफ्त में दे दो, एम0ओ0यू0 कर लो, एयरपोर्ट कर लो; हम इस सरकार को इस मंच से ठोक बजाकर कहते हैं कि ओल्ड पेंशन स्कीम कांग्रेस पार्टी लाएगी। कांग्रेस पार्टी अधिकारियों को भी लाएगी, सब लोगों को लाएगी।

इसके अलावा जो पुलिस कर्मचारी जो 24 घंटे खड़े रहते हैं वे आपके दरवाजे पर गए। हमने सोचा था कि गवर्नर अड्रैस में आप उनकी समस्याओं को अड्रैस करेंगे लेकिन आपने उनकी समस्याओं को अड्रैस नहीं किया। उनका कार्यकाल जो आपने 8 साल से घटाकर 5 साल किया है हम उस कंडीशन को भी हटाएंगे। हम इस सदन में ये वायदे करते हैं और आपको यह भी कहते हैं कि यह कांग्रेस के घोषणा पत्र में आएगा।

अंत में मैं यह भी कहूंगा कि रोहित ठाकुर जी ने एक बात रखी है।

अध्यक्ष : माननीय सदस्य, अब आप बैठिए।

श्री सुखविन्द्र सिंह सुक्खु : मुख्य मंत्री महोदय, इस सभागार के 40-45 विधायकों ने आपसे अनुरोध किया है कि 1903 में कालका से शिमला रेल लाइन बनी थी तो उसमें 103 टनल्ज बनीं। 40-45 विधायकों ने साइन करके आपसे अनुरोध किया कि 70 परसैंट हिमाचल हिल्ली टैरेन है इसलिए टनल बनाने के लिए अगर विधायक उसे विधायक प्राथमिकता में देना चाहता है तो उसको अभी जो विधायक प्राथमिकता है उसमें सम्मिलित किया जाए।

इसके अलावा मैं एक और बात कहना चाहूंगा कि आपने बड़े जोर-शोर से कहा कि 150 करोड़ रुपया देंगे। रोहित ठाकुर जी ने बड़े अच्छे आंकड़े यहां पर रखे। 150 करोड़ रुपया आप हमें 5 साल में देंगे। आप बोलते हैं कि दो पी0डब्ल्यू0डी0 की सड़के हैं, दो सिंचाई की सड़कें हैं, दो ड्रिंकिंग वॉटर की सड़कें हैं और दो रोपवे की सड़कें हैं; मेरा यह मानना है कि आप इन सब रोडों पर खर्च करने के लिए दो-दो या तीन-तीन करोड़ रुपया दे रहे हैं। आप कम-से-कम 150 करोड़ रुपये के बजाय 180 करोड़ रुपया दे दो, उससे आपका क्या जा रहा है क्योंकि आपने कर्जा ही लेना है। सम्भालना तो हमने ही है।

जारी श्रीमती के0एस0

09.03.2022/1705/KS/YK/1

श्री सुखविन्द्र सिंह सुक्खु जारी---

इसलिए आप इस कर्जे को और बढ़ा लो। हमारा आपसे अनुरोध है कि प्रदेश हित में आप इस बारे में सोचिए। एक-दो नई योजनाएं आपने शुरू कीं, बाकी मैंने देखा कि सारी कांग्रेस ने शुरू की हैं। उनमें एक मुख्य मंत्री सहारा योजना है जिसके बारे में आशा जी ने कहा कि 5000 कर दो, जब आपने यह योजना शुरू की है तो इसमें बढ़ाने में आपको कोई हर्ज नहीं होना चाहिए। आपकी एक और 1100 वाली योजना है जो कि अच्छी योजना है।

अध्यक्षः सुक्खु जी, कृपया वाइंड अप करें।

श्री सुखविन्द्र सिंह सुक्खुः यह बहुत अच्छी योजना है लेकिन उसकी इम्पलीमेंटेशन ठीक नहीं है। जब हम 1100 नंम्बर पर शिकायत करते हैं तो इतना तो बता सकते हैं कि उसका क्या हल निकला? इस चीज़ को भी आप देखिए। अध्यक्ष महोदय, आप विश्वविद्यालय में बड़े शांत हुआ करते थे लेकिन आजकल हर वक्त घंटी ही बजाते रहते हैं। हमारा थोड़ा सा तो आप ख्याल रखिए। आप हमारी बात को डाइवर्ट करने की कोशिश करते हैं। माननीय मुख्य मंत्री जी, कुछ बातें हमने आपके सामने रखी हैं, आप कुछ एम.ओ.यू. साइन करने जा रहे हैं, एस.जे.वी.एन.एल. के साथ आप समझौता करने जा रहे हैं, हिमाचल को मत बेचिए, यही मेरा आपसे अनुरोध है। अध्यक्ष महोदय, आपने समय दिया, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।

अध्यक्षः अब माननीय मुख्य मंत्री चर्चा का उत्तर देंगे परन्तु इससे पहले मैं सभी माननीय सदस्यों को सूचित करना चाहता हूं कि आज दिनांक 09.03.2022 को माननीय मुख्य मंत्री द्वारा मंत्रिमण्डल के माननीय सदस्यों तथा इस सदन के माननीय सदस्यों के सम्मान में 7.00 बजे होटल पीटरहॉफ में रात्रि भोज का आयोजन किया गया है। अतः आप सभी सादर आमंत्रित हैं। अबब माननीय मुख्य मंत्री महोदय चर्चा का उत्तर देंगे।

09.03.2022/1705/KS/YK/2

मुख्य मंत्रीः माननीय अध्यक्ष महोदय, बजट अनुमानों पर वर्ष 2022-23 के लिए जो सामान्य चर्चा इस बजट के प्रस्तुतीकरण के पश्चात इस माननीय सदन में हो रही थी, उसका समापन और उस चर्चा का उत्तर देने के लिए मैं खड़ा हुआ हूं। मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि बहुत सार्थक चर्चा इस माननीय सदन में हुई है। मैं यह भी देख रहा था कि कुल 49 माननीय सदस्यों ने इस चर्चा में भाग लिया। 25 सदस्य सत्ता पक्ष से 22 प्रतिपक्ष से, सी.पी.आई.एम. के 1 और निर्दलीय भी 1 सदस्य ने इस चर्चा में भाग लिया और 17 घंटे 30 मिनट से भी ज्यादा लम्बे समय तक यह चर्चा चली। स्वाभाविक रूप से एक लोकतांत्रिक व्यवस्था के अनुरूप सत्ता पक्ष की ओर से इस बजट का अभिनंदन किया गया, स्वागत किया गया और इस बजट के माध्यम से जो बहुत महत्वपूर्ण चीजें प्रदेश के विकास के लिए, हर वर्ग के लिए राहत के रूप में दी गईं, उसका स्वागत किया गया वहीं विपक्ष की ओर से कुछ स्वर हमें सुनने को मिले जहां स्वागत भी हुआ, धन्यवाद भी हुआ लेकिन एक परम्परा के मुताबिक, विपक्ष की भूमिका निभाने की दृष्टि से रस्म अदा करते हुए बजट की हर बात का विरोध करने की कोशिश भी हुई। उसमें हमें आपत्ति भी नहीं है ।जब हम लोकतांत्रिक व्यवस्था में विश्वास करते हैं, उसका सम्मान करते हैं तो स्वाभाविक रूप से हमें यह मानकर चलना चाहिए कि कुछ बातें अच्छे के लिए होंगी, कुछ बातों के लिए अच्छा बोला जाएगा और कुछ बातें विपक्ष की ओर से ऐसी आएंगी जिन पर कटाक्ष होगा, विरोध होगा।

श्रीमती अ0व0 द्वारा जारी---

09.03.2022/1710/av/yk/1

मुख्य मंत्री-----जारी

लेकिन हमें उन सारी बातों को सुनने की मनःस्थिति रखनी चाहिए और हमने रखी भी है। इस माननीय सदन के अंदर कई बार इस प्रकार की परिस्थितियां भी सामने आईं जब बहुत अच्छे माहौल में चर्चा हुई। लेकिन कई बार ऐसे दौर भी आएं जब चर्चा करते-करते थोड़ी तल्ख़ी भी हुई। मैं मानता हूं कि लोकतांत्रिक व्यवस्था के अनुरूप इस प्रकार की बातें होती

हैं और इसके लिए हमारे मन में कोई बुरी भावना नहीं है। यहां पर जब विपक्ष की ओर से चर्चा में बोल रहे थे तो लगभग सभी माननीय सदस्यों ने एक सामान्य भाषण के रूप में अपनी-अपनी बात रखीं। सभी माननीय सदस्यों ने अपनी-अपनी बात इस मनःस्थिति के साथ कही कि सत्ता पक्ष में भारतीय जनता पार्टी के सदस्य बैठे हैं। हालांकि बहुत सारे सदस्यों ने बजट के बारे में थोड़ा अध्ययन भी किया हुआ है और उस बारे में भी बोलें। मैं समझता हूं कि सदन के अंदर सभी माननीय सदस्यों को माननीय राज्यपाल के अभिभाषण और मुख्य मंत्री द्वारा प्रस्तुत किए गए बजट पर पर हो रही चर्चा के दौरान अपने-अपने अच्छे सुझाव देने का मौका होता है। इन दोनों अवसरों पर सभी माननीय सदस्य अपनी-अपनी बात को खुलेमन से यहां रख सकते हैं। मगर केवल रस्म अदा करना कि हम बजट का समर्थन नहीं कर सकते और यह बजट झूठ का पुलिंदा है; ऐसी बातें ठीक नहीं होतीं। ...व्यवधान... वैसे हमें आप लोगों का समर्थन चाहिए भी नहीं, हां आप अपनी बातों को यहां पर साबित करते; तो ठीक होता। लेकिन केवल यह सोचकर कि हमारे बड़े नेता ने इस प्रकार की बातें बोली हैं इसलिए हमें भी ऐसी ही बातें बोलनी हैं, ऐसी भावना ठीक नहीं है। अभी यहां पर माननीय सदस्य श्री सुखविन्द्र सिंह सुक्खु बोल रहे थे और मुझे नहीं मालूम कि इनको अंतिम वक्ता के रूप में क्यों रखा जाता है। माननीय सदस्य जब बजट पर बोल रहे थे तो इन्होंने भी कभी हाईडल प्रोजैक्ट्स तो कभी लोन के सिलसिले में ही बातें कही हैं। इस माननीय सदन के अंदर लोन के सिलसिले में एक शेर बार-बार बोला जाता है कि :-

09.03.2022/1710/av/yk/2

इक चाक़ हो तो यारब चिला लेता गिरेबां अपना।
जालिम ने फाड़ डाला है, तार-तार करके॥

प्रदेश को तार-तार तो आप लोगों ने किया हुआ है। आप लोगों ने उस वक्त अगर थोड़ा-सा भी रहम किया होता तो स्थिति ऐसी नहीं बनती। एक छेद होता तो हम चिला लेते परंतु आपने तो तार-तार किया हुआ है; अब इसमें हम क्या चिलाएं। आप यहां पर देश

और इस प्रदेश में सत्ता के अपने लंबे अनुभव का जिक्र करते रहते हैं कि हमारी पार्टी की सरकार इस प्रदेश और देश में इतने-इतने वर्षों तक रहीं। फिर इस हालत की जिम्मेवारी भी आप लोगों को लेनी चाहिए। इनका तो यह हाल है कि अच्छा काम हमने किया और बाकी बुरे काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किए। ...व्यवधान... अभी 20 वर्षों तक भारतीय जनता पार्टी की सरकार और रहेगी। जब हमारी पार्टी की सरकार को 20 साल और हो जाएंगे तो हम आपसे इस प्रकार की बातें सुनने को तैयार रहेंगे। यहां अपने भाषण के दौरान विपक्ष के सभी सदस्यों ने एक आंकड़ा पकड़ लिया और कहा गया कि ग्रोथ रेट इतना प्रतिशत हो गया है। यहां पर कहा गया कि ग्रोथ रेट -5.20 प्रतिशत से 8.30 प्रतिशत तक कैसे पहुंच गया, मैं आपको इस बारे में बताना चाहूंगा।

टी सी द्वारा जारी

09/03/2022/1715/टी0सी0वी0/ए0जी0
मुख्य मंत्री... जारी

राजस्थान में आपकी सरकार है और उस प्रदेश में पूरे देश का वरिष्ठ नेतृत्व है, उनमें एक व्यक्ति उसमें मुख्य मंत्री है। वहां वर्ष 2020-21 में ग्रोथ रेट -2.86 था और अभी जो बजट प्रस्तुत किया गया है उसमें कहा गया है कि ग्रोथ रेट 11.04 होगा। छतीसगढ़ आपकी पार्टी द्वारा शासित राज्य है। वहां आज बजट प्रस्तुत हुआ है। वहां पर वर्ष 2020-21 का ग्रोथ रेट -1.37 था और वर्ष 2021-22 का ग्रोथ रेट 11.54 बताया गया है। झारखण्ड में वर्ष 2020-21 में ग्रोथ रेट -4.40 और वर्ष 2021-22 में बताया जा रहा है कि ग्रोथ रेट 8.80 रहेगा। हरियाणा जो हमारा पड़ोसी राज्य है और वहां हमारी पार्टी की सरकार है। वहां वर्ष 2020-21 में ग्रोथ रेट -5.30 था जबकि अभी जो बजट प्रस्तुत किया गया है उसमें बताया गया है कि अनुमानित ग्रोथ रेट 9.80 होगा। उसी प्रकार से हमने अगर हिमाचल प्रदेश में -5.20 से 8.30 कहा तो इसमें कतई भी झूठ नहीं है। यह पूर्णतः सत्य पर आधारित है। ग्रोथ रेट का

जो फार्मूला है, इसको उसके मुताबिक निकाला गया है। ...व्यवधान... मैं आपको तथ्य बता रहा हूं। अभी श्री सुखविन्द्र सिंह सुक्खु और विपक्ष के नेता, श्री मुकेश अग्निहोत्री जी ने भी इस तरह का जिक्र किया कि कुछ भी नहीं किया। कुछ हुआ ही नहीं । यह जनसंख्या कैसे बढ़ गई, यह बोलना रह गया अन्यथा ये कह देते कि हमारे बिना कुछ भी नहीं। वर्ष 2017-18 में सामाजिक सुरक्षा पेंशन के लाभार्थियों की संख्या 4.25 लाख थी और वर्ष 2022-23 में यह बढ़कर 7.50 लाख हो गईं। हमने बजट में ऐलान किया है कि 60 वर्ष की आयु से ऊपर सभी को सामाजिक सुरक्षा पेंशन के दायरे में लाएंगे। आपके समय में इस पर मु0 4.50 करोड़ रुपये खर्च होते थे और वर्ष 2022-23 में हम इस पर मु0 1300 करोड़ रुपये खर्च करने जा रहे हैं। आप फिर भी कह रहे हैं कि कुछ भी नहीं किया। ... व्यवधान... यह भी बजट का ही हिस्सा है। ... व्यवधान ...

एन0एस0 द्वारा जारी ...

09-03-2022/1720/NS/AG/1

मुख्य मंत्री.....जारी

...व्यवधान... अध्यक्ष महोदय, मैं यहां पर तुलनात्मक दृष्टि से पिछले चार वर्षों का थोड़ा-सा कंपैरिज़न बताना चाहूंगा। पिछली सरकार के पांच वर्ष के दौरान कुल 24,200 करोड़ रुपये के योजना परिव्ययों का प्रावधान किया गया था। यह मैं उस वक्त का ज़िक्र कर रहा हूं जब वर्ष 2013-14 से लेकर वर्ष 2017-18 तक आपकी सरकार थी। पिछले चार वर्षों में हमारी सरकार ने 40,229 करोड़ रुपये के योजना परिव्ययों का प्रावधान किया गया है जबकि आपकी सरकार ने 24,200 करोड़ रुपयों का प्रावधान किया था। आपको यह क्यों नज़र नहीं आ रहा है? इसमें आपको अंतर दिखाई नहीं दे रहा है। आप इसे स्वीकार क्यों नहीं करते हैं? अध्यक्ष महोदय, 24,200 करोड़ रुपये से 40,229 करोड़ रुपये पर पहुंचना कोई छोटा विषय नहीं है। इसलिए मैं यहां पर कह रहा हूं।

अध्यक्ष महोदय, यहां पर मैंने पहले ही 62,200 करोड़ रुपये का कर्ज़ बताया है और इसकी हमने डिटेल दे दी है लेकिन आप इसको मान ही नहीं रहे हैं। ...व्यवधान... अध्यक्ष महोदय, आमतौर पर हिमाचल प्रदेश में यह रहता है कि कर्ज़ लेने की ऑथोराइज्ड लिमिट

को पूरा किया जाता है। ...व्यवधान... आपके समय में कर्ज लेने की ऑथोराइज्ड लिमिट को एग्जॉस्ट किया गया है और जितना लिया जा सकता था वह पूरे-का-पूरा लिया है। ...व्यवधान...

अध्यक्ष : माननीय सदस्य, मुख्य मंत्री जी बजट की चर्चा का उत्तर दे रहे हैं, आप सुन लीजिए। आप सुनिए। ...व्यवधान...

मुख्य मंत्री : अध्यक्ष महोदय, हमारी सरकार में कर्ज लेने की जो ऑथोराइज्ड लिमिट थी और अभी तक हमने 5,384 करोड़ रुपये का मार्केट ऋण उस लिमिट से कम लिया है। मैं आपको यह कहना चाहता हूं। ...व्यवधान...

अध्यक्ष : आप बैठिए। सुन लीजिए। ...व्यवधान... सुनिए।

मुख्य मंत्री : ...व्यवधान... आपको पूरा सुनना है तो पूरा सुनिए। ...व्यवधान...

श्री आर0 के0 एस0 द्वारा जारी।

09.03.2022/1725/RKS/एएस-1

मुख्य मंत्री... जारी

...व्यवधान...

अध्यक्ष : माननीय मुख्य मंत्री जी चर्चा का उत्तर दे रहे हैं। आप कृपया बैठ जाइए।

मुख्य मंत्री : वर्ष 2018-19 में खुले बाजार से ऋण लेने के लिए प्राधिकृत सीमा के विरुद्ध हमने 1,627 करोड़ रुपये कम ऋण लिया है। वर्ष 2019-20 में भी प्राधिकृत सीमा से कम ऋण लिया गया है। वर्ष 2020-21 में 3,187 करोड़ रुपये कम ऋण लिया है। ...व्यवधान...

अध्यक्ष : माननीय सदस्य बैठ जाइए। ...व्यवधान... माननीय सदस्य, माननीय मुख्य मंत्री चर्चा का उत्तर दे रहे हैं, आप बीच में न बोलें। आप बैठ जाइए। ...व्यवधान... यह अच्छी परम्परा नहीं है। माननीय नेता प्रतिपक्ष जी मैं आपको अलाउ नहीं कर रहा हूं, आप बैठ जाइए।

मुख्य मंत्री : अध्यक्ष महोदय, हम तथ्यों के आधार पर कह रहे हैं। इसमें झूठ वाली बात कहां है? आपके समय तो कोविड भी नहीं था। लेकिन आपने उस समय भी मजे मारने के लिए ऋण लिया। आप FRBM की बात कर रहे हैं लेकिन हमने इस वैश्विक महामारी को भी फेस किया है। हमने प्राधिकृत लिमिट से 5,384 करोड़ रुपये कम कर्ज लिया है। ...व्यवधान...

अध्यक्ष : माननीय सुखविन्द्र सिंह सुक्खु जी बैठ जाइए, आप पहले चर्चा का उत्तर सुनें।

मुख्य मंत्री : हमने ऐसा कभी नहीं कहा कि हम 31 मार्च तक ऋण नहीं लेंगे। हम ऋण लेंगे लेकिन जो आंकड़ा आप दे रहे हैं हम उस आंकड़े से कम ऋण ले रहे हैं। मैं इस बात को स्पष्ट करना चाहूंगा कि हम ज्यादा-से-ज्यादा दो हजार करोड़ रुपये ऋण लेंगे। ...व्यवधान... हमने आज तक जो ऋण लिया है हम उसी का जिक्र करेंगे।...व्यवधान...

09.03.2022/1725/RKS/एएस-2

आने वाले समय में क्या परिस्थितियां होगी उनका आकलन हम कैसे कर सकते हैं। वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिए भारत सरकार द्वारा 9,384 करोड़ रुपये का ऋण खुले बाजार से उठाने के लिए प्राधिकृत किया है। लेकिन 9,384 करोड़ रुपये के स्थान पर हमने अभी तक केवल 4 हजार करोड़ रुपये ही ऋण लिया है। इस प्रकार वर्तमान सरकार के विवेकपूर्ण ऋण प्रबंधन की वजह से ब्याज की कैरिंग कॉस्ट कम रही तथा आगामी समय में प्रदेश पर कर्ज का भार अपेक्षाकृत कम होगा। ...व्यवधान...ऐसा कभी नहीं हुआ कि विपक्ष के लोग हर बात पर बालें। ...व्यवधान...

श्री बी.एस. द्वारा... जारी

09.03.2022/1730/बी.एस./ए0एस0/-1

मुख्य मंत्री जारी...

...व्यवधान... अध्यक्ष महोदय, यह इस माननीय सदन की परंपरा नहीं रही है। ...व्यवधान...

(**कांग्रेस विधायक दल के सभी माननीय सदस्य एवं सत्ता पक्ष के सभी माननीय सदस्य अपने-अपने स्थान पर खड़े हो करके नारेबाजी करने लगे**) ...व्यवधान...

अध्यक्ष : माननीय सदस्य, कृपया अपने-अपने स्थान पर बैठ जाइए।...व्यवधान...

श्री मुकेश अग्निहोत्री : यह जो एफ0आर0बी0एम0 प्रोजैक्शन -4.98 का यहां पर लाया गया है, आप इसे किताबों में ला चुके हैं, क्या आप इस कानून को पास करने के लिए या संशोधन हेतु इस माननीय सदन में ले करके आएंगे? ...व्यवधान...

अध्यक्ष : कृपया बैठ जाइए, संसदीय कार्य मंत्री जी कुछ कहना चाह रहे हैं। विपक्ष के माननीय सदस्यों ने काफी देर तक बोला है और अब मुख्य मंत्री जी चर्चा का उत्तर दे रहे हैं, तो हम इसमें व्यवधान डाल रहे हैं। यदि आपके मन में कोई प्रश्न है, तो उत्तर के बाद आप प्रश्न कर सकते हैं।

संसदीय कार्य मंत्री : अध्यक्ष महोदय, मैं व्यवस्था का प्रश्न उठा रहा हूं। व्यवस्था का प्रश्न केवल यह है कि यहां पर 49 माननीय सदस्यों के भाषण सुने गए हैं। अब चर्चा का उत्तर मुख्य मंत्री जी दे रहे हैं, अगर बीच में टोका-टोकी करते जाएंगे तो प्रश्नों के उत्तर नहीं आएंगा। यदि आपने नियम के अनुसार क्लैरिफिकेशन मांगनी है तो जब मुख्य मंत्री जी का उत्तर हो जाएगा, उसके बाद आप मांग सकते हैं। इस तरह से सदन नहीं चलेगा और न ही जवाब आएगा। ...व्यवधान...

अध्यक्ष माननीय सदस्य, कृपया बैठ जाइए..... ...व्यवधान...

श्री एन0 जी0 द्वारा जारी...

09-03-2022/1735/डी.सी.-एन.जी. /1

अध्यक्ष जारी.....

...व्यवधान... माननीय मुख्य मंत्री जी आप बोलिए।

मुख्य मंत्री : अध्यक्ष महोदय, जो सत्य होता है वह बहुत पीड़ादायक होता है। हम यहां पर फैक्ट्स रख रहे हैं। आप लोग FRBM की बात कर रहे हैं। यह प्राधिकार भारत सरकार व आर.बी.आई. की ओर से दिया गया है। हमें जरूरी लगेगा तो हम कर्ज लेंगे। आप कह रहें हैं कि ये करेंगे या वो करेंगे तो ऐसा डिक्टेशन पॉसिबल नहीं हो सकता। ...व्यवधान... भारत सरकार व आर.बी.आई. की ओर से प्राधिकार है तो हम करेंगे। ...व्यवधान... प्राधिकार भारत सरकार की ओर से है और प्राधिकारी आर.बी.आई. की ओर से है और आवश्यकता होगी तो हम करेंगे।...व्यवधान...

अध्यक्ष : माननीय विपक्ष के सदस्यगण मेरी बात सुनिए। माननीय मुख्य मंत्री जी उत्तर दे रहे हैं और यदि विपक्ष की ओर से बीच-बीच में खड़े होकर व्यवधान पैदा किया जाएगा तो यह सदन कैसे चलेगा? ...व्यवधान... आप बाद में जो मर्जी पूछिए। मैं आपको मना नहीं कर रहा हूं। जब आपको स्पष्टीकरण लेना होगा तो उसके लिए आपको समय दिया जाएगा।...व्यवधान... माननीय सदस्य श्री मुकेश अग्निहोत्री जी बैठ जाइए। माननीय मुख्य मंत्री जी आप कहें।

मुख्य मंत्री : अध्यक्ष महोदय, विपक्ष की ओर एक बात को बार-बार कहा गया है। विपक्ष के जिन प्रमुख लोगों में आपस में प्रतिस्पर्धा है उन सब लोगों ने यहां पर आउटले के बारे में जिक्र किया है। उन्होंने कहा कि आउटले बहुत कम है तो मैं इन्हें तुलनात्मक आंकड़े देना चाह रहा हूं। कोविड का इतना भयंकर दौर होने के बावजूद भी हैल्थ सैक्टर में आपकी सरकार के दौरान वर्ष 2013-14 से लेकर वर्ष 2016-17 तक 5,244 करोड़ रुपये था और हमारी सरकार के दौरान 10,195 करोड़ रुपये है।

09-03-2022/1735/डी.सी.-एन.जी. /2

लोक निर्माण विभाग में आपकी सरकार के दौरान वर्ष 2013-14 से लेकर वर्ष 2016-17 तक आउटले 10,430 करोड़ रुपये था और हमारी सरकार के दौरान 17,131 करोड़ रुपये है।

शिक्षा के क्षेत्र में आपकी सरकार के दौरान वर्ष 2013-14 से लेकर वर्ष 2016-17 तक 19,203 करोड़ रुपये था और हमारी सरकार के दौरान 30,683 करोड़ रुपये है। इसी प्रकार आप कृषि व बागवानी का जिक्र करते हैं और मैं आपको बताना चाहता हूं कि कृषि में आपकी सरकार के दौरान वर्ष 2013-14 से लेकर वर्ष 2016-17 तक 1,634 करोड़ रुपये था और हमारी सरकार के दौरान 2,480 करोड़ रुपये है। बागवानी में आपकी सरकार के दौरान वर्ष 2013-14 से लेकर वर्ष 2016-17 तक 908 करोड़ रुपये था और हमारी सरकार के दौरान 2,016 करोड़ रुपये है। जल शक्ति विभाग में आपकी सरकार के दौरान वर्ष 2013-14 से लेकर वर्ष 2016-17 तक 7,293 करोड़ रुपये था और हमारी सरकार के दौरान 11,920 करोड़ रुपये है। अध्यक्ष महोदय, मैं कहना चाहता हूं कि हिमाचल प्रदेश के एक-एक विधान सभा क्षेत्र में 300-300, 200-200 करोड़ रुपये उद्घाटन व शिलान्यास इसी कारण से हो रहे हैं। मैं कहना चाहता हूं कि आज प्रदेश में विकास जमीनी स्तर पर हो रहा है। अध्यक्ष महोदय, यदि हम नाबार्ड की बात करें तो ...व्यवधान... कर्जा है लेकिन उसके बावजूद भी हमने पैसा खर्चा है। पूर्व की सरकार ने अपने प्रथम चार वर्ष के कार्यकाल के दौरान इस सीमा में 38 करोड़ रुपये की वृद्धि की है

श्री जे.एस. द्वारा जारी.....

09.03.2022/1740/JS/DC/1

मुख्य मंत्री जारी-----जारी-------

और हमने इसमें 55 करोड़ रुपये की वृद्धि की। अध्यक्ष महोदय, मैं यह भी कहना चाहता हूं कि पूर्व की सरकार ने अपने प्रथम चार वर्ष के कार्यकाल में विधायक प्राथमिकता योजनाओं के लिए कुल 1,781 करोड़ रुपये का बजट प्रावधान किया और हमने 3,173 करोड़ रुपये का प्रावधान किया। तुलना करके आप अपने आपको देख सकते हैं कि आप लोग कहां पर खड़े हैं? अध्यक्ष महोदय, मैं यहां पर सभी को देख रहा हूं और जिक्र होता है कि-:

कभी खुद पर, कभी हालात पर रोना आया,
बात निकली तो हर बात पर रोना आया।

यह बात तो आपसे निकल रही है। आप लोगों को हर बात पर रोना आ रहा है। ...व्यवधान...अध्यक्ष महोदय, बहुत सारे माननीय सदस्यों ने इस बात का जिक्र किया कि कोविड का संकट आया और आपने कुछ नहीं किया। ठीक है, अगर आप लोगों ने इस स्थिति तक रखा होता, आप लोगों ने कुछ अच्छा या बड़ा करने की स्थिति में रखा होता तो हम बहुत कुछ करने की मंशा रखते थे। लेकिन जो हालात आप लोगों ने प्रदेश की आर्थिक दृष्टि से छोड़े हैं, ऐसी हालात में कोविड के दौर में भी हमने मदद करने की कोशिश की है।

अध्यक्ष महोदय, यदि मैं परिवहन सेक्टर की बात करूं तो टोकन टैक्स, स्पेशल रोड़ टैक्स, यात्रि और माल कर टैक्स में 153 करोड़ रुपये की मदद हिमाचल प्रदेश सरकार ने की। इससे ज्यादा और क्या किया जा सकता है? प्रश्न आप लोगों ने पूछा कि सरकार ने कुछ नहीं किया। निजी बस ऑप्रेटर्ज़ को पांच साल के लिए Interest Subvention पर ऋण दिया गया। उससे आगे बढ़ कर अध्यक्ष महोदय पर्यटन के क्षेत्र में उद्यमियों के लिए 5 वर्ष के लिए Interest Subvention पर ऋण दिया गया। इससे आगे बढ़ करके 1,16,000 किसानों को किसान क्रेडिट कार्ड के माध्यम से 19,67,00,000 रुपये की धनराशि प्रदान की गई। ...व्यवधान... पता नहीं

09.03.2022/1740/JS/DC/2

ये पर्चु आप कहां से लाते हैं लेकिन ये सत्य नहीं होते हैं। ...व्यवधान... कोविड से लड़ने के लिए ...व्यवधान...

अध्यक्षः माननीय मुख्य मंत्री जी के उत्तर देने के बाद अगर कोई क्लैरिफिकेशन आपको लेनी होगी तो उसके लिए मैं आपको समय दूंगा। ...व्यवधान... आप सुन लीजिए। बीच में ये टोका-टाकी ठीक नहीं है। ...व्यवधान... प्लीज़ आप लोग बैठिए। ...व्यवधान...

मुख्य मंत्रीः माननीय अध्यक्ष महोदय, कुछ बातें यहां पर करने की हैं और कुछ बातें हम शाम को भोजन में मिलने वाले हैं, क्योंकि आप लोग सादर आमंत्रित हैं, वहां पर भी बातें करेंगे। यदि कोई कसर रह गई तो वहां पर भी बातें करेंगे।

अध्यक्ष महोदय, मैं आदरणीय प्रधान मंत्री जी का इस बात के लिए धन्यवाद करना चाहूंगा कि कोविड की पहली डोज़, सेकिंड डोज़ और उसके बाद बच्चों को जो डोज़ आई वह फ्री ऑफ कॉस्ट दी गई। ...व्यवधान... ऐसे व्यक्ति की मृत्यु कोविड-19 से हुई, परन्तु उनकी प्रधान मंत्री गरीब कल्याण योजना में पात्रता नहीं थी, को 50 लाख रुपये का बीमा कवर भी किया गया। ...व्यवधान...

अध्यक्षः माननीय सदस्यगण, प्लीज आप सभी लोग बैठ जाएं। आप लोग सुनिये। ...व्यवधान... बैठिए

(विपक्ष के सभी माननीय सदस्यों ने नारे लगाते हुए सदन से बर्हिगमन किया।)

श्री एस.एस. द्वारा जारी----

09.03.2022/1745/SS-YK/1

अध्यक्ष : मुख्य मंत्री महोदय, अपनी बात रखें।

मुख्य मंत्रीः अध्यक्ष महोदय, इनको बाहर जाना ही था क्योंकि खास तौर से जब हकीकत सामने आती है, जब आदमी एक्सपोज हो जाता है तो ऐसा होता है। इस माननीय सदन में कई सदस्य इस प्रकार के तथ्य रखने की कोशिश कर रहे थे कि अपने झूठ को सत्य साबित करने में सफल हो जाएं। इसके लिए बार-बार प्रयत्न कर रहे हैं। मीडिया के माध्यम से भी ऐसा प्रचार कर रहे हैं जो तथ्यों पर आधारित नहीं है, सच्चाई पर आधारित नहीं हैं। अध्यक्ष महोदय, मैं यह जरूर कहना चाहता हूं कि हमारी सरकार जो भी काम कर रही है वह निष्ठा, ईमानदारी और समर्पित होकर कर रही है। जो भी बात हम माननीय सदन में कह रहे हैं वह तथ्यों पर आधारित कह रहे हैं। वे फैक्ट्स पर आधारित हैं, इसमें झूठ बोलने

या घुमा-फिराकर बात कहने का कोई स्कोप नहीं है। इसलिए उनको सुनने में कठिनाई हो रही थी। इसलिए वे पूरी बात सुने बिना ही बाहर चले गए। मैं उनको हरेक बात का जवाब देना चाह रहा था लेकिन वे उसे बिना सुने चले गए। अध्यक्ष महोदय, विपक्ष द्वारा जो वॉकआउट किया गया है मैं उसकी निंदा करता हूं।

अध्यक्ष महोदय, मैं इस बात को भी कहना चाहता हूं कि हमारी सरकार ने कोविड के इतने बड़े संकट के दौरान भी हर वर्ग की जितनी मदद करने की कोशिश की जा सकती थी वह की है। जैसे मैंने पहले कुछ बातों का ज़िक्र किया, उसी तरह से मैं यह भी कहना चाहता हूं कि स्वर्ण जयंती आश्रय योजना के अंतर्गत 12 हजार लाभार्थियों को मकान के लिए सहायता राशि दी गई। कोविड रोगियों को होम आइसोलेशन में बेहतर उपचार के लिए ब्लॉक स्तर पर मोबाइल टीमों का गठन किया गया है। उनको कोविड किट बनाकर घर पर दी गई जिसमें कोविड की दवाइयां, सैनिटाइजर, मास्क, चमनप्राश, थर्मामीटर, ऑक्सीमीटर इत्यादि शामिल हैं। ये सारी चीज़ें उपलब्ध करवाई गईं। इनके कार्यकाल में अगर ऐसा दौर आया होता तो मालूम नहीं ये उसमें क्या करते! उसमें भी ये गुंजाइश ढूंढते कि कहां से क्या कुछ निकल सकता है। कोविड किट में विटामिन-डी की गोलियां और ट्रीटमैंट से

09.03.2022/1745/SS-YK/2

संबंधित सारी चीज़ें उपलब्ध करवाई गईं। हमारे कैबिनेट के सभी सहयोगियों और विधायकों ने 30 परसैंट सैलरी का सहयोग दिया। मैं विपक्ष का भी धन्यवाद करता हूं कि विपक्ष के माननीय सदस्यों ने भी एक साल तक अपने वेतन में से 30 प्रतिशत की कटौती कोविड सहायता हेतु दी । मैं यह बात भी ज़रूर कहना चाहूंगा कि प्रदेश के सभी अधिकारियों व कर्मचारियों का कुछ दिन का वेतन हमने लिया। एक बार एक दिन का वेतन लिया और दूसरी बार दो दिन का वेतन लिया था, उससे भी कोविड काल में एक सहयोग मिला है। कोविड से मृत व्यक्तियों के दाह संस्कार के लिए जो आवश्यक सहायता प्रदान की जा सकती थी, वह भी प्रदान की गई। बच्चों की पढ़ाई को जारी रखने के लिए 10वीं व 12वीं कक्षा के छात्रों के लिए दूरदर्शन ज्ञानशाला के माध्यम से ऑनलाइन कक्षाओं का

प्रावधान किया गया। शहरी क्षेत्रों में बेरोज़गार युवाओं के लिए मुख्य मंत्री शहरी रोज़गार गारंटी योजना की शुरूआत की गई। सामाजिक सुरक्षा पेंशन के लाभार्थियों, पैरा वर्कर्ज तथा अन्य कर्मचारियों के लिए संशोधित दरों से त्वरित रूप से राशि प्रदान की गई। उसी तरह से अध्यक्ष महोदय मैं यह भी कहना चाहता हूं कि जो बी0ओ0सी0डब्ल्यू0 के माध्यम से जो उसमें पात्र लोग थे जिनको मनरेगा और दूसरी योजना के अंतर्गत लाभ दिया जा सकता था, हमने तीन बार दो-दो हजार रुपये की राशि उनके खाते में डाली। इस प्रकार हमने मदद करने की कोशिश की है। हमने हर वर्ग की मदद करने की कोशिश की है। अभी तो विपक्ष के सदस्य चले गए। मुझे हमेशा अलग-अलग मिलकर कहते थे कि नाबार्ड की लिमिट बढ़ा दो, विधायक क्षेत्र विकास निधि का पैसा बढ़ा दो, विधायकों को जो ऐच्छिक निधि दी जाती है उसको बढ़ा दो; हमने इनकी तीनों बातों को स्वीकार किया। उसमें हमने पैसा बढ़ाया। अध्यक्ष महोदय, हमने विधायक क्षेत्र विकास निधि में बढ़ोतरी की।

जारी श्रीमती के0एस0

09.03.2022/1750/KS/AS/1

मुख्य मंत्री जारी---

अध्यक्ष महोदय, मैं यह कहना चाहता हूं कि विधायक क्षेत्र विकास निधि वर्ष 2013-14 में 50 लाख रुपये थी, 2014-15 में इतनी ही रही, 2015-16 में 75 लाख, 2016-17 में 1 करोड़ रुपये हुई। हमने वर्ष 2018-19 में इसको 1.25 करोड़ किया, उसके बाद वर्ष 2019-20 में 1.50 करोड़ किया, 2020-21 में 1.75 करोड़ और 2021-22 में 1.80 करोड़ तथा अभी हमने इसको 2.00 करोड़ रुपये किया है। इनके समय में यह 90 लाख रुपये थी जिसको 90 लाख से बढ़ाकर हमने 2 करोड़ किया, यह मैं कहना चाहता हूं यानि लगभग उसमें 50 परसेंट की बढ़ौत्तरी हमने की है। इसी तरह से जो 5.00 लाख रुपये ऐच्छिक निधि थी, उसको भी हमने बढ़ाकर 12.00 लाख तक, दोगुना से भी ज्यादा बढ़ाया क्योंकि विधायक इंस्टीट्यूशन मज़बूत होना चाहिए।

हमने चाहे चुने हुए प्रतिनिधि हैं, पंचायत प्रधान है, उप प्रधान है, वार्ड मैम्बर है, जिला परिषद मैम्बर, नगर परिषद का अध्यक्ष, नगर पंचायत का अध्यक्ष, नगर पंचायत के सदस्य, नगर पंचायत के सदस्य, मेयर, डिप्टी मेयर, पार्षदों आदि सभी का मानदेय बढ़ाया है जिसकी तफ़सील देने की मैं आवश्यकता महसूस नहीं करता क्योंकि सारी डिटेल बजट प्रस्तुत करते समय हमने रख दी थी।

अध्यक्ष महोदय, हम आगे बढ़कर इस बात को भी देखें, अगर हम पैरा वर्कर्ज़ की बात करें, आंगनबाड़ी वर्कर के हमने 1700 रुपये बढ़ाए, मिनी आंगनबाड़ी वर्कर के 900, आंगनबाड़ी सहायिका के 900 रुपये, आशा वर्कर के 1825 रुपये, सिलाई अध्यापिकाओं के 900रुपये, मिड डे मील वर्कर्ज़ के 900 रुपये, वाटर कैरियर के 900 रुपये, जल रक्षक के 900 रुपये बढ़ाए और इसी तरह से पैरा फीटर के भी 900 रुपये बढ़ाए। दिहाड़ीदारों के लिए हमने 50 रुपये की बढ़ोत्तरी की। 50 रुपये की बढ़ौत्तरी का अभिप्राय है कि 1500 रुपये प्रतिमाह की बढ़ौत्तरी उनके लिए हुई है। 4200 रुपये की बढ़ौत्तरी हमारे कार्यकाल में एक दिहाड़ी लगाने वाले व्यक्ति के लिए हमने दी है।

09.03.2022/1750/KS/AS/2

आउटसोर्स के जितने भी हमारे कर्मचारी हैं, उनको भी इस बजट में लाभ दिया गया है। पंचायत चौकीदार के मानदेय में 900 रुपये की बढ़ौत्तरी की। राजस्व चौकीदार और लम्बरदारों के मानदेय में भी 900 रुपये की बढ़ौत्तरी की जो आज हमसे मिलने आए थे। 1000 रुपये की बढ़ोत्तरी एस.एम.सी. के लिए की और उनकी सेवाएं बनाए रखेंगे, यह भी हमने कहा है। आई.टी. टीचर्ज़ के लिए 1000 रुपये की बढ़ोत्तरी की। एस.पी.ओज़ के लिए भी हमने 1000 रुपये की बढ़ोत्तरी की। हमने सभी वर्गों के लिए प्रयत्न किया है कि उनकी मदद करें ताकि इस महंगाई के जमाने में उनको अपने परिवार को चलाने में कठिनाई का सामना न करना पड़े।

अध्यक्ष महोदय, मुकेश अग्निहोत्री जी, राम लाल ठाकुर जी, आशीष बुटेल जी और राजेन्द्र राणा जी ने जी.एस.टी. कम्पन्सेशन का खासतौर से ज़िक्र किया कि आने वाले समय में कैसे होगा? मैं यह कहना चाहता हूं कि हमारी सरकार ने वित्तीय अनुशासन बनाने का पूरा प्रयास किया है। इसका सबसे बड़ा सबूत यह है कि वर्तमान सरकार के 4 वर्षों के कार्यकाल में केन्द्र सरकार द्वारा खुले बाजार से ऋण उठाने के लिए प्राधिकृत सीमा के विरुद्ध हर वर्ष हमने कम ऋण लिया है। वर्तमान सरकार द्वारा वर्ष 2017 में अपना कार्यभार सम्भालने के बाद पहली बार यह प्रयास किया गया है कि बाजार ऋण प्राधिकृत सीमा से कम ऋण लिया जाए तथा इस दिशा में वर्ष 2017-18 के अंतिम तिमाही में जो वर्तमान सरकार के कार्यकाल में है, 800 करोड़ रुपये कम ऋण उठाए हैं, यह भी मैं आपके माध्यम से इस माननीय सदन को जानकारी देना चाहता हूं।

अध्यक्ष महोदय, अगर हम योजनाओं की बात करें तो मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि आमतौर पर हमने इस बात को देखा है कि

श्रीमती अ0व0 द्वारा जारी---

09.03.2022/1755/av/yk/1

मुख्य मंत्री-----जारी

यदि हम योजनाओं की बात करें तो मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि हमने अपने पहले बजट से शुरू की गई सभी योजनाओं को चालू रखा है और उनके लिए बजट में लगातार प्रावधान करते आए हैं। आमतौर पर यह देखने को मिलता है कि पांचवां बजट चुनाव के मद्देनज़र सारी परिस्थितियों को देखकर प्रस्तुत किया जाता है। यहां पर हमारे विपक्ष के साथी बोल रहे थे कि यह एक चुनावी बजट है। मगर मैं यह कहना चाहता हूं कि यह चुनावी बजट नहीं है। यह हमारी सरकार का पांचवां बजट है और जो योजनाएं अपने प्रथम बजट में शुरू की थीं, हमने उनको और मजबूत करने की दिशा में काम किए हैं। मैं यह पूछना चाहता हूं कि क्या गृहिणी सुविधा योजना हमने चुनाव के वर्ष में शुरू की है? हमने यह

योजना अपनी सरकार बनने के पहले वर्ष में शुरू की थी। प्रदेश के 3.25 लाख घरों में गैस कनेक्शन पहुंचाने का काम हमने इस चुनावी वर्ष में शुरू नहीं किया। इसके अतिरिक्त, यदि हम मुख्य मंत्री हिम केयर योजना की बात करें तो इस योजना के माध्यम से अभी तक हम हिमाचल प्रदेश में 2.27 लाख गरीब लोगों का निःशुल्क उपचार करवाने में सफल हुए हैं जिसके अंतर्गत 200 करोड़ रुपये से ज्यादा राशि खर्च की जा चुकी है। हम प्रदेश में सहारा योजना को लगातार मजबूत करने की दृष्टि से काम कर रहे हैं; तो क्या इसको भी हम चुनावी वर्ष में लाए हैं? हमने यहां पर मुख्य मंत्री स्वावलंबन योजना का जिक्र किया और इस योजना को हमने आज से 4 वर्ष पहले शुरू किया था। हमने इस योजना को आज भी और मजबूत करने की दिशा में कदम उठाए हैं, तो क्या हमने इसको भी चुनावी वर्ष में शुरू किया है? हमने इस बार के बजट में कहा है कि हमारी जितनी भी मातृ शक्ति या बहनें काम करना चाहती हैं तो उनको मुख्य मंत्री स्वावलंबन योजना के अंतर्गत 35 प्रतिशत सब्सिडी दी जाएगी। हमने बुढ़ापा पैंशन की आयु सीमा अपनी सरकार के आते ही 80 वर्ष से घटाकर 70 वर्ष की और पिछले बजट के दौरान उसको महिलाओं के लिए 65 वर्ष किया था तथा इस बजट में उसको सभी के लिए 60 वर्ष कर दिया है। क्या हमने ये सारी बातें चुनाव के दिनों में की हैं? हमने ये सारी योजनाएं उस दिन से लाई हैं जिस दिन प्रदेश में हमारी सरकार बनी थी। हमने सारी योजनाओं को

09.03.2022/1755/av/yk/2

अपने प्रथम बजट से लेकर पांचवें बजट तक कायम रखकर इनको और मजबूत करने की कोशिश की है। यह सबसे खुशी की बात है कि हमने चुनाव का बोझ अपने दिमाग पर नहीं रखा। हमने चुनाव की परिस्थितियों के मद्देनज़र इस बजट को प्रस्तुत नहीं किया है। हम जानते हैं कि यहां पर जो हमारी सरकार द्वारा काम किए जा रहे हैं वह पूरे प्रदेश की जनता की बेहतरी के लिए हैं और उसमें हमें पूरे प्रदेश का सहयोग मिलेगा। कांग्रेस पार्टी के लोग अपना लास्ट बजट पेश करते हुए कह गए थे कि हम 25,000 बी0पी0एल0 परिवारों को इंडक्शन चूल्हे देंगे। मगर इन्होंने एक भी नहीं दिया। इन्होंने यह भी कहा था कि हम

1,000 नौजवानों को बसों के परमिट देंगे। मैं यह पूछना चाहता हूं कि क्या इन्होंने एक को भी दिया? इन्होंने कहा था कि हर घर से नौकरी दी जाएगी। यहां पर माननीय सदस्य श्री विक्रमादित्य आउटसोर्स का जिक्र कर रहे थे। मैं तो यह कहूंगा कि पूरे प्रदेश से आउटसोर्स कर्मियों को इकट्ठा करने वाले सूत्रधार भी उस वक्त ये ही लोग थे। उनको रैली निकालकर पीटरहॉफ पहुंचाया गया और नारे लगवाए गए कि 'सातवीं बार राजा साहब'। माननीय श्री वीरभद्र सिंह का हम भी सम्मान करते हैं परंतु हम यह पूछना चाहते हैं कि क्या कांग्रेस पार्टी ने उनके लिए कोई नीति बनाने का प्रावधान किया? ये लोग जब खुद नहीं कर पाएं तो मुझे लगता है कि इस प्रकार का ज्ञान बांटना ठीक बात नहीं है। हम क्या करेंगे; उसको आने वाले समय में देखेंगे। ऐसा नहीं है कि हमने बजट सत्र में बजट तो प्रस्तुत कर दिया और इसके बाद हमारे पास समय नहीं है। हमारे पास अभी भी काम करने के लिए बहुत समय है। हम जब तक कि आचार संहिता नहीं लगेगी; रात-दिन प्रदेश की जनता की सेवा में समर्पित होकर काम करेंगे। हम विपक्ष के उन सभी माननीय सदस्यों का जिक्र करना चाह रहे हैं

टी सी द्वारा जारी

09/03/2022/1800/टी0सी0वी0/वाई0के0

मुख्य मंत्री... जारी

मैं इनसे कहना चाहूंगा कि आप एक योजना का ज़िक्र तो करें कि हिमाचल प्रदेश में हमने यह योजना शुरू की और इस योजना के माध्यम से हमने काम किया। लेकिन इनकी कोई योजना ही नहीं है। इनकी योजना यह होती है कि डैपूटेशन लाओ और स्कूल की नोटिफिकेशन हाथ में लेकर जाओ। ये मेरे विधान सभा चुनाव क्षेत्र से गाड़ियों में भर-भरकर लोगों को लाते थे।

अध्यक्ष : माननीय मुख्य मंत्री जी आपको और कितना समय लगेगा?

मुख्य मंत्री : अध्यक्ष महोदय, 15 मिनट और लगेंगे।

(**माननीय सदन की बैठक का समय सांय 6.15 बज़े तक बढ़ाया गया**)

मुख्य मंत्री : अध्यक्ष महोदय, उनको जीपों में भरकर लाया जाता था और उनको वहां खड़ा कर घोषणा कर देते थे कि आपको कॉलेज दे दिया। अधिकारियों को कह दिया जाता था कि इसकी नोटिफिकेशन इनके हाथ में दे दें। प्रदेश के अनेकों विधान सभा क्षेत्रों में शिलान्यास कर दिए लेकिन शिक्षा विभाग के नाम एक इंच जमीन और एक रुपये के बजट प्रावधान नहीं होता था उसके बावजूद भी शिलान्यास करके रख दिए। कुछ माननीय विधायक मुझे बुला रहे हैं कि आप हमारे कॉलेज का शिलान्यास करें क्योंकि आपने इसके लिए बजट और जमीन का प्रावधान किया है। आपने इसकी फॉरेस्ट क्लीयरेंस भी करवा दी है लेकिन फिर कहते हैं कि शिलान्यास करना कैसे है क्योंकि इन्होंने वहां पर पहले ही फटा लगा दिया है। ऐसी परिस्थिति जैसे पता नहीं आने वाले समय में दुनिया ही खत्म होने वाली है। जहां छाप सकते हैं, अपना नाम छाप रहे हैं। लम्बे समय तक सत्ता में रहने वाले लोग इस प्रकार का कार्य करें तो ज्यादा पीड़ा होती है। इस बात का ज़िक्र करते हैं कि हम छह बार मुख्य मंत्री रहें। क्या छह बार रहने का अभिप्राय यही होता है कि आप नियमों, कानूनों की धज्जियां उड़ाते जाएं। हमारा उनके प्रति सम्मान है। यह वे लोग नहीं करते थे, करवाने वाले ये लोग थे। आज वे हमारा

सामाना नही कर पा रहे हैं और मुंह छुपाकर निकल गए। इन्होंने जिस प्रकार की परिस्थितियां पैदा की है, मैं यह कहना चाहूंगा कि उन्होंने सारी व्यवस्थाओं को तबाह किया है और आज हमारा मार्गदर्शन करने जा रहे हैं। यहां कह रहे हैं कि आपने कर्मचारियों के लिए राइडर लगा दिया और आपको कोई स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं है। मैं माननीय सदन को अवगत करवाना चाहता हूं कि पंजाब पे-कमीशन को लागू करने के पश्चात् हम आगे बढ़ रहे हैं। हमारी सरकार ने 2 लाख से अधिक कर्मचारियों को नया वेतनमान प्रदान किया है और लगभग 1.20 लाख सरकारी कर्मचारी संशोधित वेतमान लेने के लिए अपना ऑप्शन दे चुके हैं। संशोधित वेतन निर्धारण करना एक टेक्निकल कार्य

है। इसको तत्परता से किया जा रहा है और 1.09 लाख कर्मचारी नये वेतनमान के अनुसार बढ़ा हुआ वेतन ले रहे हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि शीघ्र ही हमारे सभी कर्मचारी अपनी ऑप्शन देकर बढ़े हुए वेतनमान का लाभ लेने के पात्र होंगे। हिमाचल प्रदेश सरकार ने अपने कर्मचारियों व पेंशनरों का महंगाई भत्ता पंजाब से अधिक और केन्द्र की तर्ज़ पर देय तिथि से दिया है।

एन0एस0 द्वारा जारी ...

09-03-2022/1805/NS/AG/1

मुख्य मंत्री.....जारी

इसके विपरीत पंजाब सरकार ने न केवल हिमाचल प्रदेश के मुकाबले कम महंगाई भत्ता दिया बल्कि महंगाई भत्ता प्रोस्पैक्टिव डेट से देकर 50 महीनों की डी0ए0 राशि पंजाब सरकार ने अपने पास ही रखी। मेरा अनुमान है कि पंजाब के लगभग चार लाख कर्मचारियों और तीन लाख पैंशनरों के लाभ, 5000 करोड़ रुपये महंगाई भत्ते की राशि को वर्ष 2016 से वर्ष 2021 के बीच कर्मचारियों को लाभ देने की बजाए पंजाब सरकार ने अपने पास ही रखा। मैंने ये बातें सदन में बतानी थीं तो मैंने बता दी हैं।

अध्यक्ष महोदय, हमारी सरकार ने सरकारी अंशदान को दिनांक 01.04.2019 से 10 प्रतिशत से बढ़ा करके 14 प्रतिशत किया है। जिससे एन0पी0एस0 कर्मचारियों को 175 करोड़ रुपये का लगातार वार्षिक लाभ मिल रहा है। इससे एक लाख से अधिक एन0पी0एस0 कर्मचारी लाभान्वित हो रहे हैं। हमारी सरकार अंशदान को 10 प्रतिशत से 14 प्रतिशत करने वाले अग्रणी राज्यों में से है। इसलिए मैं इसे यहां पर बता रहा हूं क्योंकि ये लोग इतना शोर कर रहे हैं कि ओ0पी0एस0 दो। आपकी ही सरकार ने उस वक्त ओ0पी0एस0 बंद की। हमारी ही सरकार ने एन0पी0एस0 कर्मचारियों को लाभ दिए हैं और इनकी सरकार ने ये भी नहीं दिए। पिछली सरकार ने बड़ी देर के बाद रिटायरमैंट डैथ ग्रेच्युटी लाभ दिया और वह भी प्रोस्पैक्टिव तिथि 22.09.2017 से इसे लागू किया। इस कारण जो कर्मचारी दिनांक 15.05.2003 से 21.09.2017 के दौरान सेवानिवृत्त हुए थे वे इस लाभ से वंचित रह गए। हमने कर्मचारियों को भी डैथ-कम-रिटायरमैंट ग्रेच्युटी का लाभ

दिया जिससे 5612 एन0पी0एस0 कर्मचारियों को 150 करोड़ रुपये का लाभ मिला। अगर आपको करना था तो इनको भी करते लेकिन यह हमने किया है।

अध्यक्ष महोदय, एन0पी0एस0 कर्मचारियों को इनवेलिड पेंशन और फैमिली पेंशन देने के आदेश दिनांक 22.02.2022 को हमारी सरकार ने जारी किए। अब दिनांक 15.05.2003 के बाद सेवाकाल में मृत अथवा अपंग हुए लगभग 2200 एन0पी0एस0 कर्मचारियों के परिवारों को पारिवारिक पेंशन तथा इनवेलिड पेंशन का लाभ सी0सी0एस0 रूल्ज, 1972 की तरह मिलेगा जिस पर लगभग 250 करोड़ रुपये खर्च होंगे। पिछली सरकार चाहती तो वह अपने समय में केंद्र सरकार की तरह यह इनवेलिड पेंशन दे

09-03-2022/1805/NS/AG/2

सकती थी। इन आदेशों से एन0पी0एस0 कर्मचारियों में सुरक्षा की भावना बढ़ेगी। अध्यक्ष महोदय, एन0पी0एस0 कर्मचारियों को रिटायरमैंट डैथ ग्रेच्युटी के लाभ ओ0पी0एस0 कर्मचारियों की तरह दिये जा रहे हैं। हमने इसकी सीमा 10 लाख रुपये से बढ़ा करके 20 लाख रुपये करने का निर्णय लिया है। कर्मचारियों के लिए जितना बेहतरीन हमारी सरकार कर सकती थी उसको किया है। उनकी सरकार ने इनके लिए कुछ भी नहीं किया।

अध्यक्ष महोदय, अन्य विषयों को ले करके यहां पर जिक्र किया गया है। मैंने ग्रोथ रेट के बारे में बड़ा स्पष्ट कह दिया है। मैंने उन राज्यों का भी जिक्र किया है जहां कांग्रेस की सरकार है और उसका कंपेरीजन भी दिया है। ये उन आंकड़ों पर कुछ नहीं बोल पाए। अध्यक्ष महोदय, इस बात का जिक्र किया गया कि आप लैपटॉप नहीं दे रहे हैं। मैं इस बारे में यह कहना चाहता हूं कि हमने अभी हाल ही में केबिनेट की बैठक में निर्णय लिया है और उसके मुताबिक तकनीकी कारणों को लेकर लैपटॉप देने की औपचारिकताओं को पूर्ण कर लिया गया है।

श्री आर0 के0 एस0 द्वारा जारी।

09.03.2022/1810/RKS/एजी-1

मुख्य मंत्री... जारी

बहुत जल्द बच्चों को लैपटोप उपलब्ध करवा दिए जाएंगे। अगर मैं ग्रीन फील्ड हवाई अड्डा, मण्डी की बात करूं तो हम लगातार इसके लिए प्रयास कर रहे हैं। हवाई अड्डे को स्थापित

करने के लिए एक-दो दिन या एक वर्ष में औपचारिकताएं पूरी नहीं की जा सकती। लेकिन मैं कहना चाहूंगा कि इस हवाई अड्डे को स्थापित करने के लिए जो प्रयास हो रहे हैं, उसमें हम बहुत जल्द सफल होंगे। मैं पिछले चार वर्षों से देख रहा हूं कि विपक्ष के लोग हर बार सरकार के ऊपर कीचड़ उछालने का नया मुद्दा ढूंढने की कोशिश करते हैं। लेकिन इनके हाथ में जो मुद्दे हैं उन्हें लोग सुनने को तैयार नहीं हैं। इन्होंने कई मुद्दे उठाने की कोशिश की लेकिन ये हर जगह विफल हुए। इस सरकार का सवा चार साल का कार्यकाल बीत रहा है लेकिन सरकार के विरुद्ध आज कोई भी ठोस मुद्दा सामने नहीं आया। पहले शुरू के चार महीनों में ही सरकार कटघरे में खड़ी हो जाती थी। जो लोग अपनी मांगो को सहजता से कह रहे हैं, हम उनकी बात सुन रहे हैं। लेकिन ये कुछ लोगों को इस तरह से भड़का रहे हैं ताकि वे सरकार के खिलाफ आंदोलन का रास्ता अपनाएं जिससे इनको राजनीतिक लाभ मिल सके। यह सत्ता की भूख है। जिन लोगों को ये भड़काने की कोशिश कर रहे हैं वे थोड़े समय तक इनके प्रभाव में आ सकते हैं लेकिन वे लंबे समय तक इनके साथ खड़े नहीं होंगे। अंततोगत्वा वे हमारे साथ मिलकर चलेंगे। हमने पर्यटन के क्षेत्र में नई डेस्टिनेशन डवेलप करने के प्रयास किए हैं और इस बात का जिक्र बजट भाषण और महामहिम राज्यपाल के अभिभाषण के दौरान भी किया है। यह हमारा दुर्भाग्य था कि हम कोरोना के कारण चार वर्षों में से दो वर्ष ही काम कर पाए। हम पौंग डैम, तातापानी और लारजी में टूरिस्ट डेस्टिनेशन डवैलप करने की तरफ आगे बढ़े हैं। हम बीड़-बिलिंग में इंटरनेशनल डेस्टिनेशन की ओर आगे बढ़े हैं। हमने धर्मशाला में 207 करोड़ रुपये की लागत से रोपवे तैयार किया है। पहले यह कहा जा रहा था कि अटल टनल, रोहतांग का निर्माण कार्य वर्ष 2023 या वर्ष 2024 के अंत तक पूर्ण होगा लेकिन हमने इस टारगेट को अक्तूबर, 2020 में पूर्ण कर लिया। हमने जमीनी स्तर पर काम करने की कोशिश की है।

श्री बी.एस. द्वारा... जारी

09.03.2022/1815/बी.एस./ए0एस0/-1

मुख्य मंत्री जारी...

इसी तरह से मण्डी में यूनिवर्सिटी की बात कह रहे हैं। हमने कहा है कि हम मण्डी में यूनिवर्सिटी बनाएंगे और हम इसे बहुत जल्दी पूरा करके लोगों को समर्पित करेंगे। बल्क

ड्रग्ज फार्मा हब की यहां पर बात की जा रही है। मैं उसके बारे में सिर्फ इतना ही कहना चाहता हूं कि जो हमारा दूसरा चिकित्सा उपकरण पार्क है, उसके लिए भी हम काफी आगे बढ़े हैं और उसकी स्वीकृति के पश्चात जमींनी स्तर पर काम करने के प्रयास करेंगे और बल्क ड्रग्ज फार्मा के लिए जो हमनें प्रयास किए हैं उसमें भी हम निश्चित रूप से सफल होंगे, ऐसा मुझे भरोसा है।

जो इन्वेस्टर मीट हमने की उसके सार्थक परिणाम हमें जमींनी स्तर पर देखने को मिले हैं।

अध्यक्ष : अब इस माननीय सदन की कार्यवाही आधा घंटा और बढ़ाई जाती है।

मुख्य मंत्री : अध्यक्ष जी, हम एक नहीं बहुत सारी चीजों का जिक्र कर सकते हैं। ग्लोबल इन्वेस्टर मीट में एक महीने के आयोजन के पश्चात हमने उसमें साढ़े 13 हजार ग्राउंड ब्रेकिंग की और अभी प्रधान मंत्री महोदय आए थे, उसमें हमने 28 हजार करोड़ रुपए की ग्राउंड ब्रकिंग की है। ये उसे भी स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं है। हमने तय किया कि हिमाचल प्रदेश पॉवर सरप्लस स्टेट है, बिजली में हम गरीब लोगों के लिए राहत देंगे, उस पर हमने काम किया और 0-60 यूनिट बिजली फ्री ऑफ कोस्ट देने का निर्णय किया। उसके बाद आगे बढ़ करके हमने 60 के बाद 125 यूनिट तक एक रुपए के हिसाब से बिजली देंने का निर्णय किया है और यह निर्णय ऐतिहासिक है। इसी तरह से अगर करुणामूलक की बात करें तो जो करुणामूलक वाले बच्चे धरने पर बैठे हैं, उनसे हम बार-बार आग्रह कर रहे हैं कि आइए बैठ करके बात करते हैं। पहले अगर किसी कर्मचारी की 50 वर्ष में मृत्यु हो जाती थी, तो उसका परिवार पात्र नहीं होता था, परंतु हमने उनके लिए 50 वर्ष की आयु को बढ़ा करके 58 वर्ष तक की दिया है। इनकम का क्राइटेरिया हमने दो बार बढ़ाया, इसे हमने पहले 2 लाख 25 हजार और फिर 2 लाख 50 हजार तक किया। उसके बाद अध्यक्ष महोदय, हमने यह भी कहा कि करुणामूलक आधार पर जो क्लास-4 के लिए

09.03.2022/1815/बी.एस./ए0एस0/-2

आना चाहते हैं, उनका अभिनंदन है, स्वागत है। मैंने तो यह भी कहा है कि एक हजार नौजवानों को हम सीधे नौकरी देने का प्रावधान कर लेंगे। मुझे प्रसन्नता है कि करुणामूलक

वालों के आवेदनों की संख्या धीरे-धीरे बढ़ती जा रही है और मुझे पूरा भरोसा है कि हम आने वाले समय में सफल होंगे और हम उनकी समस्या का समाधान करने की कोशिश करेंगे। मुझे जो जानकारी मिली है उसके अनुसार 125 मामले हमने स्वीकृत किए हैं, 266 अभी सचिवालय में पंहुच गए हैं और शीघ्र ही हम इस काम को पूरा करने की कोशिश करेंगे, ताकि उन्हें हम ज्यादा-से-ज्यादा लाभ दे सकें।

एक मसला यह था कि टी0सी0पी0 नगर परिषद एरिया में जो एन0ओ0सी0 देने की व्यवस्था थी, उसमें बहुत सारे लोगों का आग्रह आ रहा था, उस आग्रह को हमने स्वीकार कर दिया और मुझे लगता है कि इस एन0ओ0सी0 में जो नए प्रावधान हमने जोड़े हैं, इसके कारण हमारे शहरी क्षेत्र में जो लोग हैं, उन्हें इसका लाभ मिलेगा।

स्वास्थ्य के क्षेत्र में हम देख रहे हैं कि एक्पेंशन काफी हो गई है, नई पी0एच0सी0 खोली गई हैं, सी0एच0सी0 हो गई हैं और बहुत से सिविल अस्पताल हो गए हैं, इसलिए हमने तय किया कि डॉक्ट्र्ज के और पद भरने चाहिए।

श्री एन0 जी0 द्वारा जारी...

09-03-2022/1820/ए.एस.-एन.जी. /1

मुख्य मंत्री जारी.....

हिमाचल प्रदेश के इतिहास में ये ऐसा पहला बजट है जिसमें 500 डॉक्टर्ज़ के पदों को भरने का निर्णय लिया गया है ताकि सभी जगह डॉक्टर्ज़ पहुंच सकें। अध्यक्ष महोदय, मैं पिछले कल अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के उपलक्ष पर बहुत बड़े कार्यक्रम में जोगिन्द्रनगर गया था। मुझे वहां पर राजीव गांधी राजकीय आयुर्वेदिक महाविद्यालय, पपरोला के डॉक्टर्ज़ मिले थे और उन्होंने मुझे कुछ बातों का जिक्र किया। वे कह रहे थे कि प्रदेश में लगभग 400 आयुष डॉक्टर्ज़ के पद रिक्त पड़े हैं। **अध्यक्ष महोदय, मैं इस माननीय सदन के माध्यम से घोषणा करता हूं कि प्रदेश में आयुष डॉक्टर्ज़ के 200 पद भरे जाएंगे और इसके**

अलावा मैं यह भी घोषणा करना चाहता हूं कि प्रदेश में 100 पद फार्मासिस्ट के भी भरे जाएंगे।

अध्यक्ष महोदय, वहां पर बच्चों ने इससे सम्बंधित और भी मसले उठाए हैं तथा वे सभी हमने नोट कर लिए हैं। उन सभी विषयों पर बेहतर क्या किया जा सकता है इसके लिए हम अवश्य प्रयत्न करेंगे। वहां पर अन्य विषयों पर भी सुझाव आए हैं। पंजाबी, ऊर्दू अध्यापक व बी.एड और टैट वाले अध्यापकों ने भी कहा है कि जिस प्रकार शास्त्री अध्यापकों को टी.जी.टी. पदनाम देने की घोषणा की गई है उसी प्रकार हमारे बारे में भी विचार किया जाए। अध्यक्ष महोदय, इस संदर्भ में मैंने शिक्षा विभाग को कहा है कि इसे एग्ज़ामिन करके प्रस्तुत किया जाए और इस पर जो भी किया जा सकता होगा वह हम करेंगे। यहां पर परवाणू औद्योगिक क्षेत्र के विस्तार के लिए बात आई थी। अध्यक्ष महोदय, उसके बारे मैं यही कहना चाहूंगा कि लगभग 180 बीघा भूमि का केस राजस्व विभाग में प्राप्त हो चुका है और वहां पर औद्योगिक प्रशासन की व्यवस्था को भी सुदृढ किया जाएगा। कुछ दिन पहले वहां से हमारे पास एक डेलिगेशन मिलने के लिए आया था और उनके साथ जब चर्चा हुई तो हमने उन्हें भी कहा था कि हम सुधार की दिशा में आगे बढ़कर काम करेंगे।

09-03-2022/1820/ए.एस.-एन.जी. /2

मुझे एक बात को लेकर बहुत विचित्र लगा और जिस प्रकार माननीय सदस्य श्री सुखविन्द्र सिंह सुक्खु जी कह रहे थे कि एस.जे.वी.एन.एल. को बेच दिया। अध्यक्ष महोदय, इस प्रकार की भयानक बातें कहना उचित नहीं है। मैं बताना चाहता हूं कि हम उसमें 26.85 प्रतिशत के मालिक हैं। इसके अलावा मैं कहना चाहता हूं कि इस प्रकार की कोई सम्भावना भी नहीं है। यहां पर विपक्ष के माननीय सदस्य 2005 की पॉवर पॉलिसी के बारे में बात कर रहे थे। यदि आज वे सामने बैठे होते तो हम उनसे पूछते कि 2005 की उस पॉवर पॉलिसी का इम्पैक्ट क्या हुआ? हिमाचल प्रदेश में कितने नए प्रोजैक्ट्स लगे? 2005 की पॉलिसी के बाद तो प्रदेश में ऐसी परिस्थिति बनी कि जो प्रोजैक्ट लगाना भी चाह रहे थे वे भी अपना

बोरिया-बिस्तर उठा कर वापिस चले गए। अब हमने पॉवर पॉलिसी में कुछ बदलाव किए हैं और उसके कारण प्रदेश में एक सकारात्मक माहौल बना है। मैं उम्मीद करता हूं कि आने वाले समय में निश्चित रूप से उसका लाभ होगा। इसके लिए हम और भी बेहतर करने की दिशा में आगे बढ़कर काम करेंगे। विपक्ष के लोग ये कहने की कोशिश कर रहे हैं कि हमने हिमाचल प्रदेश के हितों की रक्षा नहीं कि तो मैं उन्हें कहना चाहता हूं कि यह बिलकुल भी सत्य नहीं है। हिमाचल प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बिलकुल कमिटिड है और हम इस बात को स्पष्ट शब्दों में कहना चाहते हैं कि हर हालत में हम हिमाचल प्रदेश के हितों की रक्षा करने में सक्षम है और हमने रक्षा की भी है। हिमाचल के हितों को यदि किसी ने बेचा है तो वह कांग्रेस पार्टी की सरकार थी। वे लोग आज हमारे सामने नहीं बैठे है और हम उन्हें यह कई तथ्यों के आधार पर कह सकते हैं।

श्री जे.एस. द्वारा जारी.....

09.03.2022/1825/JS/DC/1

मुख्य मंत्री जारी----

एक और सुझाव है जो माननीय विधायकों की ओर से भी आज आया है। मैं इस बात को स्वीकार करता हूं कि माननीय विधायकों ने कहा था कि कुछ चीजों को हमारी विधायक निधि में परमिसिबल किया जाए। इसमें जो हम विधायक प्राथमिकता देते हैं, अभी तक उसमें क्योंकि आज हमने शिमला में टनल का फाउंडेशन स्टोन रखा और शिमला के इतिहास में मुझे लगता है कि बहुत लम्बे समय के पश्चात यह दौर आया है कि एक नई डबल लेन टनल का निर्माण कार्य आज से शुरू हो रहा है, उसके लिए मैं शिमला वासियों को बहुत-बहुत बधाई देता हूं।

अध्यक्ष महोदय, सत्ता पक्ष और विपक्ष के हमारे बहुत सारे माननीय विधायकों ने इस बारे में लिखकर दिया है। इन्होंने लिखकर दिया है कि विधायक प्राथमिकता में आने वाले समय में सड़कों का जितना स्कोप होता है, वह तो हम कर ही रहे हैं, पुलों के निर्माण के लिए हम प्रायोरिटी देते हैं लेकिन आने वाले समय में इस बात की भी प्रायोरिटी सुनिश्चित करेंगे कि हम इसमें टनल को भी रिकमेंड कर सके।

अध्यक्ष महोदय, मैं इस प्रस्ताव को स्वीकार करता हूं और आने वाले समय में विधायक प्राथमिकता में टनल का भी ज़िक्र विधायक कर सकते हैं क्योंकि बहुत जगह इस प्रकार की सम्भावनाओं से हम बेहतर ढंग से लोगों को सड़क की सुविधा देने की स्थिति में हो सकते हैं।

अध्यक्ष महोदय, बहुत सारी बातों का हमने ज़िक्र कर दिया है। हमने माननीय सदन में जो बजट प्रस्तुत किया है, इसके माध्यम से हमने कोशिश की है कि इसमें हर वर्ग का ख्याल रखा जाए और बहुत सारी चीजों का ज़िक्र सत्ता पक्ष के माननीय सदस्यों ने यहां पर चर्चा के दौरान किया है। इन्होंने एक-एक बात का ज़िक्र बहुत तर्क के साथ किया है लेकिन विपक्ष ने अपनी एक औपचारिकता, एक रस्म को अदा करने की दृष्टि से जो कदम उठाया है कि हम नहीं सुनेंगे, नहीं मानेंगे, हम सदन से बाहर चले जाएंगे और आज की तारीख़ में जब इनको लग रहा है कि चुनाव करीब आ गए हैं तो ऐसी परिस्थिति में, ऐसे हालात पैदा करने से उनको बहुत बड़ा लाभ होगा लेकिन लाभ नहीं इनको निश्चित रूप से नुकसान होने वाला है। कल का दिन बहुत महत्वपूर्ण है,

09.03.2022/1825/JS/DC/2

कल पांच राज्यों के चुनाव की काउंटिंग होगी तो मालूम पड़ जाएगा। जो ये बड़े-बड़े दावे कर रहे हैं कि हम यहां भी और वहां भी आ रहे हैं, असली हकीकत इनको कल मालूम पड़ेगी, उस बारे में मैं आज कुछ नहीं कहना चाहता। अध्यक्ष महोदय, जो यहां से चले गए, उनको मैं यह ज़रूर कहना चाहता हूं, बशर साहब का एक शेर मेरे पास है जिसका मैं ज़िक्र करना चाहूंगाः-

ख्वाहिशों के बोझ में बशर तू क्या-क्या कर रहा है,

ख्वाहिशों के बोझ में बशर तू क्या-क्या कर रहा है।

इतना तो जीना भी नहीं जितना तू मर रहा है।

इतने ख्वाब, इतनी ख्वाहिशें इन्होंने पाल ली है, ये विपक्ष में होकर घोषणाएं कर रहे हैं कि हम यह भी कर देंगे, वह भी कर देंगे। नवम्बर, 2022 के चुनाव में जो अबकी बार होगा, हम

उसमें पूरी ताकत के साथ जाएंगे, सामना करेंगे और हिमाचल प्रदेश में फिर से भारतीय जनता पार्टी की सरकार को लाएंगे, उसमें कहीं भी किसी तरह की कोई गुंजाइश नहीं छोड़ेंगे। इसलिए इनकी ख्वाहिशें, इनके ख्वाब हकीकत में कभी भी तबदील नहीं होंगे, यह मैं कहना चाहता हूं। सत्ता पक्ष के सभी माननीय सदस्यों, जिन्होंने इस बजट की चर्चा में भाग ले कर बहुत मज़बूती के साथ इस बजट का समर्थन किया, मैं उनका आभार व्यक्त करता हूं और विपक्ष के लोग जो सच्चाई और हकीकत से दूर रह कर ही झूठा और भ्रामक प्रचार करने की कोशिश कर रहे हैं, वे आज इस माननीय सदन में नहीं हैं। उन पर मुझे दया आती है। उन्होंने भले ही समर्थन नहीं किया। मैं इतना ही कहना चाहता हूं कि लोकतांत्रिक व्यवस्था के अनुरूप उन्होंने अपनी विपक्ष की भूमिका निभाने की कोशिश की है लेकिन ये उसमें सफल नहीं हुए। अध्यक्ष महोदय, सत्ता पक्ष और विपक्ष के सभी माननीय सदस्यों, जिन्होंने चर्चा में भाग लिया, मैं खुले दिल से सभी का आभार व्यक्त करता हूं जिन्होंने अपने महत्वपूर्ण सुझाव दिए। अध्यक्ष महोदय, आपने इस सदन में, इस चर्चा को बहुत वक्त दिया और सार्थक चर्चा को एक स्वरूप देने की कोशिश की, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। जय हिंद।

श्री एस0एस0 द्वारा जारी---

09.03.2022/1830/SS-YK/1

अध्यक्ष : संसदीय कार्य मंत्री जी कुछ कहना चाहते हैं।

शहरी विकास मंत्री (संसदीय कार्य मंत्री) : अध्यक्ष महोदय, मुख्य मंत्री महोदय ने इतनी लम्बी चर्चा का आज विस्तृत उत्तर इस माननीय सदन में दिया है। इसके लिए मैं इनको बधाई देता हूं। लेकिन विपक्ष का रवैया विपक्ष के अनुरूप भी नहीं रहा। अगर उनको वॉकआउट करना होता है तो उत्तर सुनने के बाद आखिर में क्लैरीफिकेशन में अगर संतुष्टि न हो तो वॉकआउट करते हैं। लेकिन जब सदन के नेता माननीय मुख्य मंत्री सदन में बोल रहे हों और बहुत ही महत्वपूर्ण विषय या बजट का जवाब दे रहे हों तो उस समय किसी भी प्रकार की टोका-टोकी करना, हर विषय पर सीट पर खड़े हो जाना जैसे कि उस सीट पर कोई स्प्रिंग लगे हों, बार-बार उछलते रहना; यह सब सदन की परम्पराएं के अनुकूल नहीं है। सदन में जो मर्यादा व परम्पराएं बनाई जाती हैं वे सब पर लागू होती हैं।

इसलिए उन्होंने जो मर्यादाएं भंग की हैं और परम्पराओं के अनुरूप काम नहीं किया है तथा उत्तर सुने बिना बेवजह बहिर्गमन किया है जबकि उनकी पूरी-की-पूरी चर्चा को पक्ष की ओर से मुख्य मंत्री जी ने स्वयं सुना है तो इस प्रकार का विपक्ष का व्यवहार निंदनीय है जिसकी हम भर्त्सना करते हैं। इस प्रकार का व्यवहार मान्य नहीं है।

अध्यक्ष : मैं एक बार पुनः सूचित करना चाहता हूं कि आज दिनांक 09.03.2022 को माननीय मुख्य मंत्री के द्वारा मंत्रिमंडल के माननीय सदस्यों तथा सदन के माननीय सदस्यों के सम्मान में सायं 7.00 बजे होटल पीटरहॉफ में रात्रि भोज का आयोजन किया गया है अतः आप सभी उसमें सादर आमंत्रित हैं।

अब इस माननीय सदन की बैठक वीरवार, दिनांक 10 मार्च, 2022 के 11.00 बजे पूर्वाह्न तक स्थगित की जाती है।

शिमला-171004 **यशपाल शर्मा,**
दिनांकः 9 मार्च, 2022 **सचिव ।**